दैनिक जागरण
संबंधों की डोर विश्वास के धागे से ही बुनी जाती है

नशा मुक्त भारत

प्रधानमंत्री ने नशे की लत की समस्या से निपटने के लिए 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान' की जो शुरुआत की, वह समय की मांग है। इस अभियान को देश भर में जनभागीदारी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को नशे की लत के खिलाफ एक साथ मिलकर प्रयत्न करने के लिए एकजुट करना है। इस अभियान का उद्देश्य केवल युवाओं को नशा मुक्त भारत के अभियान में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को समर्थन देना भी है। निश्चित रूप से यह एक महत्वाकांक्षी अभियान है। जब देश विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहा है, तब यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि देश के युवा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और किसी भी तरह के नशे के शिकार न होने पाएं। इस अभियान को वास्तव में जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि सरकारी आयोजनों एवं अभियानों में स्वेच्छा से जनभागीदारी नहीं हो पाती। एक समस्या यह भी है कि आमतौर पर ऐसे अभियानों से अन्य राजनीतिक दल और विशेष रूप से विरोधी राजनीतिक दल जुड़ना पसंद नहीं करते। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग कैसे प्राप्त हो?

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि युवाओं में नशे की बढ़ती लत किसी एक राज्य या क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है। यह एक तरह से पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसी के साथ तथ्य यह भी है कि कुछ सीमावर्ती राज्य इस समस्या से कहीं अधिक ग्रस्त हैं। उदाहरणस्वरूप पंजाब एक अर्से से नशे की समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। एक के बाद एक राज्य सरकारों ने पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ा, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिल सकी। पंजाब जैसी स्थिति पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों की भी है। इसका कारण यह है कि जहां पंजाब में पाकिस्तान मादक पदार्थ भेजने में लगा हुआ है, वहीं पूर्वोत्तर में यह काम म्यांमार से हो रहा है। यह एक चिंताजनक तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से नशे की आवक बढ़ी है। इसके अतिरिक्त देश में भी चोरी-छिपे मादक पदार्थ बनाने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को तो सक्रिय होना ही होगा, समाज को भी इस खतरे से सावधान रहना होगा। घर-परिवार और शिक्षा संस्थानों की ओर से छात्रों को इसके लिए सतत रूप से चेताया जाना चाहिए कि नशे की लत किस तरह युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देती है। हर स्तर पर सक्रियता और जागरूकता से ही नशे की समस्या से निपटा जा सकता है।

आपदा प्रबंधन

उत्तराखंड में इस वर्ष हो रही भारी वर्षा ने एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। जगह-जगह भूस्खलन, मुख्य और संपर्क मार्गों का ध्वस्त होना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन का प्रभावित होना बताता है कि प्राकृतिक आपदाएं अब सामान्य चुनौती नहीं रह गई हैं। पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही वर्षा ने आवाजाही, आजीविका और आवश्यक सेवाओं पर भी असर डाला है। इन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में सक्रियता दिखाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हेलीकाप्टरों की तैनाती भी दूरस्थ क्षेत्रों तक त्वरित सहायता पहुंचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जुटी हुई हैं। हालांकि, बीते वर्षों के अनुभव बताते हैं कि केवल तात्कालिक राहत पर्याप्त नहीं है। सुरक्षित स्थानों पर समयबद्ध पुनर्वास, संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक आकलन, ढलानों का उपचार और मजबूत आधारभूत ढांचे का निर्माण अब समय की जरूरत बन रहे हैं। यह समझना होगा कि आपदा प्रबंधन केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है। आमजन की सतर्कता, मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना, अनावश्यक यात्रा से बचना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है।

आपदा से बचाव के लिए हर स्तर पर सजगता और सतर्कता आवश्यक है

गुलाम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी बर्बरता

डा. आनंद कुमार

गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोगों का दमन अब पाकिस्तान का आंतरिक विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका हैं

पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को कश्मीरियों के अधिकारों का सबसे बड़ा हिमायती बताता रहा है। वह यही बेसुरा राग अलापता आया है कि भारत जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता आ रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों का जिस निर्ममता से दमन हो रहा है वह दर्शाता है कि पाकिस्तान की कश्मीर नीति का उद्देश्य कभी कश्मीरियों का हित नहीं, बल्कि इस मुद्दे का राजनीतिक और कूटनीतिक इस्तेमाल करना था। गुलाम जम्मू-कश्मीर में जारी आंदोलन कोई एकाएक पैदा हुई स्थिति नहीं है। यह वर्षों से बढ़ते राजनीतिक असंतोष, आर्थिक उपेक्षा और इस्लामाबाद के बढ़ते हस्तक्षेप का ही परिणाम है। पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना शिकंजा कसे रखने के लिए चुनावी व्यवस्था का दुरुपयोग करता रहा है। यहां विधानसभा की 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो विभाजन के बाद सीमा पार चले गए। मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के ये विस्थापित आज पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। स्थानीय लोगों की एक शिकायत यह भी है कि इन सीटों पर अपने मनमाने रवैये से पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है, जिसमें स्थानीय जनता की आवाज और हितों को उपेक्षित किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव सुधार की मांग धीरे-धीरे राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक न्याय और अधिक स्वायत्तता के व्यापक आंदोलन में बदल गई। इस आंदोलन का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी कर रही है। उसके नेताओं से संवाद के बजाय पाकिस्तानी शासकों ने उन्हें कुचलना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया।

इसी बीच हुए विधानसभा चुनावों से विवाद और गहरा गया। पहले चुनाव एक चरण में होने थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर तीन चरणों में कराए गए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से लेकर जेएएसी ने चुनावों को अविश्वसनीय बताते हुए उनके बहिष्कार का आह्वान किया। चुनाव लड़ने वाले दलों ने भी एक-दूसरे पर मतपेटियां लूटने और वोटों में हेरफेर के आरोप लगाए। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या गुलाम जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाएं वास्तव में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं या केवल इस्लामाबाद की जरूरतों को पूरा करने का जरिया बनी हुई हैं।

सबसे चिंताजनक बात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा है। सुरक्षा बलों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई। सुबूत मिटाने के लिए शवों को अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से हटाया गया। इस पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने उचित ही चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंटरनेट सेवाओं की बहाली, हिंसा की निष्पक्ष जांच और पत्रकारों तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का भी यही रुख है। स्पष्ट है कि यह मामला अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।

अवधेश राजपूत

प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझने या उनका समाधान निकालने के बजाय पाकिस्तानी सत्ताधीशों ने पूरे आंदोलन को भारत प्रायोजित बताने की कोशिश की। यह पाकिस्तानी शासकों की पुरानी आदत है। इसी आदत से मजबूर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को भारत की तरह 'दुश्मन' बताया। यह बयान पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र को ही उजागर करता है, जिसमें वह भारत के कश्मीरियों के अधिकारों की बात करता है, लेकिन अपने यहां मौलिक अधिकार मांगने वालों को ही दुश्मन घोषित कर देता है। यदि लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों के लिए यही रवैया अपनाया जाएगा, तो यहां उसका दावा समाप्त हो जाता है।

चूंकि इस बार प्रदर्शनकारियों की मांगें चुनावी सुधार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बेहतर शासन और आर्थिक अवसरों से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें केवल भारत विरोधी प्रचार के सहारे दबाया नहीं जा सकता। भारत ने भी इस घटनाक्रम पर कड़ी और उचित प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ध्यान देने की अपील की है। विभाजन के समय भारत आकर बस चुके शरणार्थियों ने भी गुलाम जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 1994 में भारतीय संसद द्वारा पारित उस प्रस्ताव की भी याद दिलाई, जिसमें समूचे जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया था।

गुलाम जम्मू-कश्मीर का घटनाक्रम पाकिस्तान की कश्मीर नीति की बुनियादी विफलता को ही उजागर करता है। पाकिस्तान दशकों से जम्मू-कश्मीर में भारत के रुख-रवैये पर तो सवाल उठाता रहा, लेकिन अपने यहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सुशासन स्थापित करने की दिशा में उसने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। किसी भी सरकार की वैधता केवल प्रचार से नहीं बनती, बल्कि जनता के विश्वास, पारदर्शी प्रशासन और लोकतांत्रिक भागीदारी से बनती है। दमन, चुनावी हस्तक्षेप और असहमति को दबाने की नीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। गुलाम जम्मू-कश्मीर का आंदोलन दर्शाता है कि वहां के लोग पाकिस्तानी शासन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं। वे सम्मानजनक जीवन, निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक अवसर और जवाबदेह शासन चाहते हैं। इन मांगों का उत्तर यदि गोलियों, गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंदी से दिया जाएगा तो असंतोष निश्चित ही गहराएगा। यह पाकिस्तान की कश्मीर नीति के लिए भी निर्णायक मोड़ है कि कश्मीर पर उसके नैरेटिव को सबसे गहरी चोट भारत से नहीं, बल्कि गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोगों से ही मिल रही है, जो अपने अधिकारों, सम्मान और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब केवल भारत और पाकिस्तान के पारंपरिक विवाद की दृष्टि से ही इस मुद्दे को नहीं देखना चाहिए। गुलाम जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच एवं वहां के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान आवश्यक है।

(लेखक मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में फेलो हैं)

response@jagran.com

असम की भूमि को लीलती बाढ़

पंकज चतुर्वेदी

जमीन का कटाव अपने साथ पलायन और आधारभूत ढांचे के नुकसान सहित कई त्रासदियां लेकर आता हैं

कई दशकों की सबसे भयावह बाढ़ झेल रहे असम में एक तरफ जलप्लावन है तो दूसरी तरफ जमीन के कटाव से लोग बेघर-बेजमीन हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से निकलने वाली सपाई नदी के तेज बहाव ने कई रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क लील ली। शिवसागर, डिब्रूगढ़ जैसे जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने दर्जनों बस्तियों को अपने में समा लिया। बाढ़ के चलते एक तो राज्य का विकास हर साल 19 साल पीछे चला जाता है तो दूसरी तरफ राज्य भूमि कटाव के कारण औसतन एक प्रतिशत की दर से जमीन खो रहा है। असम सरकार के अनुसार 1950 से अभी तक राज्य की 4,27,000 हेक्टेयर भूमि नदियों के कटाव के चलते लुप्त हो चुकी है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 7.4 प्रतिशत है। वर्ष 2020 के बाद जिस तरह जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव बढ़ा है और चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के साथ छेड़छाड़ बढ़ी है, राज्य में भूमि कटाव और तेज होता जा रहा है।

जुलाई 2019 में जल संसाधन मंत्रालय ने लोकसभा को बताया था कि 2014 से 2019 के बीच असम में भूस्खलन के कारण 86,536 लोग भूमिहीन हो गए थे। बाढ़ तो असम में सदियों से चार महीने डेरा डालती रही है, फिर भी वहां कभी नदी से डर कर लोगों का पलायन नहीं हुआ। बीते कुछ दशकों के दौरान पानी के बढ़ते भूमि कटाव ने इस राज्य में नए किस्म का विग्रह पैदा कर दिया है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे गांव-कस्बे साल दर साल सिकुड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट के चलते जब बारिश और गर्मी के अतिरेक एवं हिमनद पर निर्भर नदियों में अनियमित और बेमौसम तेज प्रवाह के चलते तटों का घुलकर पानी में समा जाना बेहद गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक संकट बढ़ा रहा है। सदियों पहले नदियों के साथ बहकर आई जिस मिट्टी ने कभी असम राज्य का निर्माण किया, अब वही इस राज्य को बाढ़ और भूमि कटाव से श्रापित कर रही है।

बाढ़ की विभीषिका झेल रहा असम। फाइल

जमीन का कटाव अपने साथ पलायन और सड़क, पुल, सरकारी भवनों आदि के नुकसान सहित कई त्रासदियां लेकर आता है। असम की लगभग 25 लाख आबादी ऐसे गांवों में रहती है, जहां हर साल नदी उनके घर के करीब आ रही है। ऐसे इलाकों को यहां 'चार' कहते हैं। चार अर्थात कछार यानी जहां तक नदी का अधिकतम विस्तार होता है। इनमें से कई नदियों के बीच के द्वीप भी हैं। हर बार जमीन का कटाव रोकना, मुआवजा, पुनर्वास चुनावी मुद्दा भी होते हैं, लेकिन यहां बसने वाले किस तरह उपेक्षित हैं, इसकी बानगी यहां का साक्षरता आंकड़ा है, जो महज 19 प्रतिशत है। यहां की आबादी का 67 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। तिनसुखिया से धुबरी तक नदी के किनारे जमीन कटाव, घर-खेत की बर्बादी, विस्थापन, गरीबी और अनिश्चितता की बेहद दयनीय तस्वीर है। कहीं लोगों के पास जमीन के कागजात हैं तो जमीन नहीं। कहीं बाढ़-कटाव में उनके दस्तावेज बह गए और वे नागरिकता रजिस्टर में 'डी' श्रेणी में आ गए। इसके चलते आपसी विवाद, सामाजिक टकराव भी गहरे तक दर्द दे रहा है। सोनितपुर जिले में 2,711 लोगों की जमीन नदी में समा गई तो मोरीगांव में 18,425, माजुली में 10,500, कामरूप में 9,337 लोग अपनी भूमि से हाथ धो बैठे। बेशक असम की भौगोलिक स्थिति जटिल है और यहां आने वाली तेज बाढ़ का असली कारण उसके पड़ोसी राज्यों से आने वाला तेज बहाव हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि असम में नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए अधिकांश तटबंध जर्जर हैं और कई जगह पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। एक मोटा अनुमान है कि राज्य में लगभग 4,448 किलोमीटर नदी तटों पर पक्के तटबंध बनाए गए थे, ताकि बाढ़ के समय जमीन के कटाव को रोका जा सके, लेकिन आज इनमें से आधे भी नहीं बचे हैं। वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं हुई। नदियों ने अपना रास्ता भी खूब बदला है। भूमि कटाव का बड़ा कारण राज्य के जंगलों और आर्द्र भूमि पर हुए अतिक्रमण भी हैं। सभी जानते हैं कि पेड़ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं और बरसात को भी सीधे धरती पर गिरने से बचाते हैं। आर्द्र भूमि पानी की मात्रा को बड़े स्तर पर नदी के जल-विस्तार को सोखते थे। दुर्भाग्य है कि ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण का रोग ग्रामीण स्तर पर संक्रमित हो गया और तभी नदी को अपने ही किनारे काटने के अलावा कोई रास्ता नही दिखा।

असम की नदियों में ड्रेजिंग के जरिये गहराई को बढ़ाया जाए। इसके किनारे से रेत उत्खनन पर रोक लगे। सघन वन भी कटाव रोकने में मददगार होंगे। अमेरिका की मिसीसिपी नदी भी ऐसे ही भूमि कटाव करती थी। वहां 1989 में तटबंध को अलग तरीके से बनाया गया और उसके साथ खेती के प्रयोग किए गए। आज वहां नदी-कटाव पूरी तरह नियंत्रित हैं। आने वाले दिनों में कम समय में अत्यधिक और तेज बरसात होना ही है। ऐसे में असम के अस्तित्व को बचाने के लिए उसके तटों की सुरक्षा के लिए दूरगामी योजना अनिवार्य है, जो यहां के जल और जन दोनों को बचा सके।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अंत: अन्वेषण

एक प्रश्न यदि स्वयं से किया जाए कि 'मैं कौन हूं?', तो संभवतः इसका उत्तर खोजना कठिन होगा। कारण यह है कि प्रश्नों के उत्तर अन्वेषण का परिणाम होते हैं, किंतु यह प्रश्न स्वयं के समक्ष रखने से पूर्व हमने मंथन नहीं किया। सत्य तो यह है कि इस लघु, किंतु नितांत जटिल प्रश्न के लिए एक गहन एवं दीर्घ अन्वेषण की आवश्यकता है। यह अन्वेषण है-'अतःअन्वेषण' अर्थात अपने भीतर के ज्ञान, सत्य एवं चेतना की खोज। यह कठिन है, किंतु जिसने स्वयं को समझ लिया तो समझिए उसने संसार को समझ लिया। उसके लिए कोई भी स्थिति मायने नहीं रखती। अंतर्मन से संवाद हमें मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास तथा आत्मिक संतोष प्रदान करता है। अंतःअन्वेषण कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं, अपितु जीवन भर चलने वाली साधना है। यह हमें बाहरी उपलब्धियों के मोह से ऊपर उठाकर आंतरिक परिपक्वता की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर छिपे प्रकाश को पहचान लेता है, वह अंधकार भरी राह पर भी सहजता से आगे बढ़ता है। वह चुनौतियों को भी अवसर में रूपांतरित करने की क्षमता से समृद्ध हो जाता है।

अंतःअन्वेषण का अर्थ संसार से पलायन करना या सांसारिक उत्तरदायित्वों से विमुख होना कदापि नहीं है। इसका वास्तविक आशय अपने भीतर उतरकर अपनी चेतना, विचारों, भावनाओं, गुणों, कमजोरियों, आकांक्षाओं और जीवन के उद्देश्य को समझना है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अपार संभावनाएं विद्यमान होती हैं, किंतु उनका विकास तभी संभव है, जब वह स्वयं के व्यक्तित्व का निष्पक्ष मूल्यांकन करे। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि उनका निर्माता बनने का साहस अर्जित करता है। अंतःअन्वेषण स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखाता है।

प्रेरणा अवस्थी

प्राकृतिक जल का समुचित प्रबंधन

मिथिलेश कुमार

वर्षाजल, नदी जल और भूजल के रूप में उपलब्ध समस्त जल को सहेजने के समुचित उपायों पर देना होगा जोर

गुजरात के अनेक हिस्सों और असम समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ का भयावह प्रकोप देखा जा रहा है। लगभग प्रत्येक वर्ष इस आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोग जान माल का नुकसान झेलते हैं। अनेक लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जीवन तबाह हो जाता है, अपने सदा सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जीवन भर की टीस ये बाढ़ लोगों को देती है।

वहीं दूसरी ओर इस मानसून के समय में भी देश का दूसरा भाग सूखे से ग्रसित रहता है। देश के कई क्षेत्रों में अब तक सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। यह कहीं न कहीं यह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि हमने जल प्रबंधन के संदर्भ में अभी सफलता हासिल नहीं की है। बात मानसून की वर्षा को सहेजने में अथवा जलस्तर नीचे जाने की हो, हर क्षेत्र में हम पीछे ही होते जा रहे हैं।

इस सदी के आरंभिक वर्षों में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज भी याद आते हैं जिन्होंने नदियों को जोड़ने की कल्पना की थी। यदि ऐसा सार्थक हो जाए तो हम जल का सार्थक और समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है तो फिर नदियों के पानी को दूसरी नदियों में क्यों नहीं भेजा जा सकता है।

दूसरी ओर दुर्भाग्य है कि उर्वरक के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण जो कुछ भी भूजल है वह भी प्रदूषित होने की ओर अग्रसर है। आज दुनिया में भारत भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। विकसित देश अमेरिका और चीन से भी हम अधिक भूजल का दोहन अंधाधुंध गति से कर रहे हैं। वही हमारी जल प्रबंधन के संदर्भ में बरसों की पहचान रहे। नदियों एवं तालाबों की स्थिति भी भयावह है। जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि वह मृतप्राय स्थिति में होती चली जा रही है।

आधुनिकता के नाम पर कंक्रीट के जंगल तैयार करके प्रकृति से निर्मित जल का संग्रहण तक हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारी पुरानी पीढ़ी तकनीक के दौर में नहीं रहने के बावजूद तालाब आदि के माध्यम से जल संचयन कर जल संकट जैसी स्थिति से बचते रहे थे। वहीं आज की अवस्था में जिस तरह जल प्रबंधन अब कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है उससे वर्तमान पीढ़ी तो प्रभावित हो ही रही है, सतत विकास हेतु आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, इस बारे में भी हमें विचार करना होगा।

जीवन के लिए आवश्यक जल को हम बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसे सहेज नहीं सके तो हमारी कैसी प्रगति, हमारी कैसी व्यवस्था। नीति नियामकों को अपनी नीति में बदलाव लाना ही पड़ेगा, अन्यथा यह जल कुप्रबंधन हमें भारी पड़ सकता है। विडंबना यह कि फैशन के नाम पर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जीवन के लिए आवश्यक दशाएं सुनिश्चित करने में हम बहुत पीछे हैं। लिहाजा जल के समुचित प्रबंधन की ओर ध्यान देना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अराजकता को न मिले छूट

'अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन के दौरान बिना अनुमति संसद मार्च को लेकर भड़की हिंसा की अनदेखी करने वाले सीजेपी नेताओं की अनैतिक मांग के संदर्भ में यह ठीक ही कहा है कि यदि हिंसा के जिम्मेदार अराजक तत्वों को बख्श दिया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा। जो सीजेपी नेता आंदोलन के वक्त यह स्वीकार कर रहे थे कि उनके द्वारा प्रायोजित छात्र आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुसकर हिंसा फैला रहे हैं, वही अब उन सभी अराजक तत्वों को रियायत देने का राग अलाप रहे हैं। वह भी तब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये सभी संदिग्ध आदतन अपराधी किस्म के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वयं को भद्दी-भद्दी गालियां देने वाले उन नादान छात्रों को ही क्षमा किया है, जिन्होंने किसी के बहकावे में आकर गलती की है। इस माफी में उन पेशेवर अपराधियों को शामिल न किया जाए, जिन्होंने छात्रों की भीड़ में घुसकर हिंसक अराजकता की। सीजेपी के आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति और सभ्य समाज की सुरक्षा में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान अराजक तत्वों के हमलावर होने पर अपने अधिकारियों और साथियों को पिटता हुआ नहीं देख सकते। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीमित बल प्रयोग उनकी मजबूरी बन गई। आखिर सुरक्षा बलों को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। चूंकि सीजेपी आंदोलन का मुद्दा अब न्यायालय में भी पहुंच चुका है, इसलिए दिल्ली पुलिस को मजबूत तथ्यों और सुबूतों के साथ आंदोलन में घुसे उन पेशेवर अराजक तत्वों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करनी ही चाहिए, जिन्होंने एक अभियान को अराजकता की भेंट चढ़ा दिया।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

स्पेन में घुसपैठ

स्पेन के एक कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि स्पेन में जो भी घुसपैठिए समुद्र के रास्ते आए हैं, उनको सीधे वापस नहीं किया जाएगा, वरन उन पर केस चला कर कार्रवाई की जाएगी। पर मोरक्को में यह अफवाह फैल गई कि लोगों को वहां से वापस नहीं किया जा रहा है। बस मोरक्को वासियों में स्पेन में घुसपैठ करने की होड़ मच गई। सभी जानते हैं कि अधिकांश मुस्लिम देश भूखे कंगालों के देश हैं। वह शादी चार तक करते हैं और बच्चे दर्जनों पैदा करते हैं। अधिकांश अनपढ़ रह जाते हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण देश में स्थान एवं रोजगार की कमी हो जाती है। वह दूसरे देशों में घुसने का प्रयास करते हैं। पर वह किसी मुस्लिम राष्ट्र में घुसने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। वे नई जगह जाकर बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या बढ़ाकर वहां भी शरियत लागू करने की बात करते हैं। लंदन, पेरिस आदि में गैर मुस्लिमों का जीना हराम कर दिया है। खैर मोरक्को से इनको जबरदस्ती पीछे ढकेला जा रहा है। वहां 60 हजार लोग घुस गए थे, लेकिन लौटने भी लगे, क्योंकि वहां के हालात अनुरूप नहीं थे।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, लखनऊ

जवाबदेही से भागती सत्ता

रविवार को प्रकाशित 'अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश' शीर्षक से लिखे लेख में संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और अव्यवस्था की आलोचना की गई है। किसी भी लोकतंत्र में हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कानून हाथ में लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरे घटनाक्रम को केवल एक पक्ष की दृष्टि से देखना भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। लगातार पेपर लीक के मामलों को लेकर जब शांतिपूर्वक धरने की घोषणा की गई, तब क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वह छात्रों के हितों को लेकर संवाद करे? आखिर युवा, छात्र और नागरिक बार-बार सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हो रहे हैं। संसद मार्च से जुड़ी घटनाओं में चिंताजनक पक्ष केवल भीड़ नहीं, बल्कि पुलिस का कठोर और कई बार असंतुलित व्यवहार रहा।

शिवम सिंह, बबेरू, बांदा, यूपी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाषः नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

270 से अधिक परीक्षाएं कराई हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने वर्ष 2018 से अब तक और 6.6 करोड़ से अधिक छात्रों के फार्म संभाले हैं, लेकिन इस एजेंसी में स्थायी भर्ती बहुत कम है।

आजकल

परीक्षा व्यवस्था में नए सिरे से सुधार

पिछले कुछ वर्षों में प्रश्नपत्र लीक के कई मामलों से परीक्षा व्यवस्था चर्चा के केंद्र में है। वस्तुतः परीक्षाओं की विश्वसनीयता कड़े कानून, उसके प्रभावी क्रियान्वयन, सुरक्षित परीक्षा संचालन और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया से सुनिश्चित होती है। हाल में किए गए विधायी और प्रशासनिक बदलावों का उद्देश्य इसी दिशा में व्यवस्था को मजबूत करना है। अब वास्तविक कसौटी यह होगी कि इनका प्रभाव परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता में व्यावहारिक स्तर पर कितना दिखाई देता है

मनीश कुमार झा
शिक्षा मामलों के जानकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते सप्ताह नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल (टास्क फोर्स) के गठन की घोषणा की है। प्रश्नपत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में 'दी पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' लागू किया। यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आइबीपीएस) तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा प्रक्रिया में अनधिकृत हस्तक्षेप, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़, परिणामों में हेरफेर तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करना या जारी करना दंडनीय अपराध हैं। कानून में बिना वारंट गिरफ्तारी, जमानत पर कड़े प्रविधान तथा यह व्यवस्था की गई है कि जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) या समकक्ष स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा।

27 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 'दी पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' प्रस्तुत किया। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके माध्यम से कई प्रविधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैंः इस अधिनियम के तहत अपराधों में सजा तीन से पांच वर्ष के स्थान पर पांच से दस वर्ष तथा जुर्माना दस लाख रुपये के स्थान पर 50 लाख रुपये तक करने का प्रविधान किया गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों पर अधिकतम जुर्माना एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये तथा सरकारी परीक्षाओं के आयोजन से प्रतिबंध की अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दी गई है।

जांच और विशेष अदालतें : आवश्यकता होने पर केंद्र सरकार विशेष कार्यबल (एसटीएफ) का गठन कर सकेगी और उसे संबंधित मामलों की जांच का दायित्व सौंप सकेगी। ऐसे मामलों में जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर एक सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत के रूप में नामित करेगा। इन अदालतों में मुकदमों की सुनवाई प्रतिदिन चलेगी और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर सुनवाई करने का प्रविधान किया गया है।

हालांकि 'दी पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' फरवरी 2024 से लागू है। इसके बावजूद नीट-यूजी 2026 में पेपर लीक का मामला सामने आया। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या मौजूदा कानून के कुछ प्रविधानों में संशोधन की आवश्यकता थी या मुख्य चुनौती कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और परीक्षा संचालन में थी। संशोधन में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए गए हैं। लेकिन कानून का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि परीक्षा में गड़बड़ी का समय पर पता लगाने, दोषियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी बनती है। ऐसे में परीक्षा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और जांच व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल : सरकार ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार से जुड़े विषयों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन किया है। अब यह देखना होगा कि उसकी सिफारिशें केवल परीक्षा सुरक्षा और तकनीकी उपायों तक सीमित रहती हैं या परीक्षा संचालन, एनटीए की कार्यप्रणाली तथा संस्थागत जवाबदेही से जुड़े व्यापक सुधारों को भी शामिल करती हैं। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि इन सिफारिशों पर निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी।

संशोधन में दोषी सेवा प्रदाता कंपनियों पर जुर्माना और प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी कंपनियों के चयन, उनके कार्यों की निगरानी और परीक्षा से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी जांच कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ताकि गड़बड़ी होने से पहले ही उसे रोका जा सके। संशोधन में जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रविधान किया गया है। लेकिन परीक्षा से जुड़े मामलों में कई राज्यों में जांच, डिजिटल साक्ष्य, बैंकिंग रिकार्ड और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में इस समय-सीमा का पालन व्यवहार में किस प्रकार होगा, यह देखना होगा।

संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत नामित करनी होगी और ऐसे मामलों की पैरवी के लिए विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति करनी होगी। विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था, विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति तथा जांच एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग आवश्यक होगा। संशोधन में अपील 30 दिन के भीतर दायर करने का प्रविधान है। पर्याप्त कारण होने पर उच्च न्यायालय 90 दिन तक विलंब से दायर अपील स्वीकार कर सकेगा। अब यह देखना होगा कि दूरदराज क्षेत्रों या सीमित आर्थिक साधनों वाले लोग इस समय-सीमा के भीतर आवश्यक कानूनी सहायता लेकर समय पर अपील कर पाएंगे या नहीं।

प्रश्न पत्र लीक होने से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा तत्परता बरतने की आवश्यकता है। फाइल

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की व्यवस्था में बदलाव

सुभाष कुमार ठाकुर
शिक्षा मामलों के जानकार

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल सरकारी नौकरियों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश का माध्यम नहीं हैं, बल्कि करोड़ों मध्यवर्गीय युवाओं के लिए अपने जीवन को संवारने का रास्ता है। इसलिए जब किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है तो उसका असर केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की भूमिका पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। वर्ष 2018 में स्थापित यह एक स्वायत्त संस्था है, जिसे देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इस संस्था से उच्च स्तर की दक्षता और विश्वसनीयता की अपेक्षा की जाती है। किंतु उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी यह संकेत देती है कि एनटीए बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भर है। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या करोड़ों युवाओं के भविष्य का निर्णय करने वाली संस्था के लिए स्थायी, विशेषज्ञ और मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है? जिस प्रकार इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक व्यवस्था, निर्वाचन आयोग चुनाव और संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे के साथ कार्य करते हैं, उसी प्रकार परीक्षा प्रणाली के लिए भी एक सुदृढ़, पेशेवर और विशेषज्ञ संस्था की आवश्यकता है।

हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। वर्ष 2024 में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डा. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति का निष्कर्ष था कि समस्या किसी एक चरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को समग्र रूप से अधिक सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, प्रश्नपत्रों को एन्क्रिप्टेड डिजिटल माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक भेजना, चरणबद्ध ढंग से पेन-पेपर आधारित परीक्षाओं से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की ओर बढ़ना, एआइ आधारित डाटा विश्लेषण द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, निजी एजेंसियों पर निर्भरता कम करते हुए लगभग एक हजार स्थायी और सुरक्षित सरकारी परीक्षा केंद्र विकसित करना तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मोबाइल टेस्ट सेंटर जैसी दूरदर्शी सिफारिशें शामिल हैं।

भारतीय परीक्षा प्रणाली के सुधार पर विचार करते समय केवल अपनी समस्याओं तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि दुनिया के वे देश, जहां करोड़ों विद्यार्थियों की परीक्षाएं अपेक्षाकृत निष्पक्ष और विश्वसनीय ढंग से संपन्न होती हैं, उन्होंने ऐसा कैसे किया। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की वर्ष 2026 में प्रकाशित शोध रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि परीक्षा सुधार का अर्थ परीक्षा व्यवस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे अधिक सक्षम और भरोसेमंद बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी परीक्षा प्रणाली की सफलता चार मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर करती है। पहला- विश्वसनीयता, अर्थात परीक्षा परिणाम पर समाज और नियोक्ताओं का भरोसा। दूसरा- निष्पक्षता, अर्थात प्रत्येक अभ्यर्थी को समान अवसर और पक्षपात-रहित मूल्यांकन। तीसरा- प्रासंगिकता, अर्थात परीक्षा वही ज्ञान और कौशल मापे जो उच्च शिक्षा, रोजगार और जीवन के लिए वास्तव में आवश्यक हों। चौथा- व्यावहारिकता, अर्थात पूरी परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों और संस्थागत क्षमता के अनुरूप प्रभावी ढंग से संचालित की जा सके।

खरी-खरी

एआइ की काट एआइ

विनय कुमार पाठक

कलमदास लिखना तो चाहते थे, पर लिख नहीं पाते थे। वैसे लिखते तो बहुत थे, पर किसी को उनका लिखा रास नहीं आता था। हालांकि उन्हें बीमारी थी छपास की। यानी पत्र-पत्रिकाओं में अपनी रचना छपते देखना बहुत भाता था उन्हें। रचनाओं के साथ छपे अपने नाम को वह बहुत ही प्यार से देखते थे। काफी मशक्कत करने पर भी सौ में से मुश्किल से एक रचना भी छप जाती तो गनीमत। इस मुश्किल के उपाय के रूप में उन्हें सहारा मिला एआइ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसे माननीय पिलकेंद्र जी प्यार से कृबु बुलाते हैं।

अब वह एआइ से रचनाएं लिखवाकर भेजने लगे। नतीजा हुआ कि सौ में एक के स्थान पर पांच रचनाएं छपने लगीं। फिर भी यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब फिर से उनकी रचनाएं सौ में एक की दर से छपने लगीं। इधर उधर से पता चला कि अब पत्र-पत्रिकाएं एआइ डिटेक्शन टूल का प्रयोग करने लगी हैं और उनकी चोरी पकड़ी गई है। खुद लिखने की इतनी क्षमता थी नहीं कि छपने की वही गति कायम रहती।

तभी उन्हें पता चला कि ये एआइ डिटेक्शन टूल न केवल यह बताता है कि लेख में एआइ का प्रयोग हुआ है या नहीं, बल्कि उसे फिर से ऐसा बनाए रखने में मदद करता है जिससे लगे कि यह एआइ के द्वारा नहीं, बल्कि मानव के द्वारा लिखा गया है। यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर थी। फिर क्या था, उन्होंने उस टूल का प्रयोग शुरू कर दिया। पहले एआइ से अपनी रचना को पूरी करवाते फिर उसी एआइ से मानवीकृत करके लेख भेजने लगे।

पर तभी एक और टूल आ गया जो यह बता सकता था कि रचना को एआइ से मानवीकृत किया गया है या नहीं। प्रकाशन अब इस टूल का प्रयोग करने लगे। नतीजा वही हुआ। अब फिर से उनकी छपास की भूख अतृप्त रहने लगी। अब फिर से वे उलझन में हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नया टूल आए जो एआइ से मानवीकृत बनाए गए लेख को पहचान कर उसे फिर से मानवीकृत करे और वे अपनी छपास की भूख को मिटा सकें। अब यही क्रम न जाने कब तक चलता रहेगा।

पोस्ट

बिहार की राजनीति में आज बड़ा बदलाव आ सकता है। राज्य में विपक्ष चुनाव लड़ने के सिवा कुछ नहीं करता। ऐसे में अगर बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीतते हैं तो प्रदेश को सवाल पूछने वाला एक नेता मिल सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर जीतेंगे?
प्रभात रंजन@prabhatranjann

गौतम अदाणी ने असम राहत कोष में 11 करोड़ रुपये दान किए। आनंद महिंद्रा ने पांच करोड़। अगर असम के सीएम आफिस ने पोस्ट करके उनका आभार न जताया होता तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। भारत को उनके जैसे और अरबपतियों की जरूरत है।
रायल सिंह@Royalsinghz3

लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाले लेफ्ट-लिबरल, तृणमूल और कांग्रेस नेताओं को यह दिखना चाहिए कि उनकी सरकारों में जिस मुस्लिम लेखिका को बंगाल से भगा दिया गया था, वे 19 साल बाद वहां सरकार बदलने पर ही जा सकीं।
डा. नवनीत मिश्रा@navneetmishra99

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में विपक्षी नेताओं का कृत्य हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला रहा?

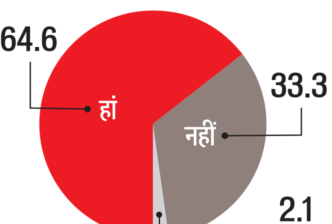

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल
प्रधानमंत्री की पहल पर नशा मुक्त अभियान नशे के विरुद्ध जागरूकता में प्रभावी बनेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

दो-दो पप्पू साथ मिल चले रचाने स्वांग,
नहीं जानते किंतु वे क्या राइट क्या रांग।
क्या राइट क्या रांग बन गए भगवा धारी,
रावण सा धरि रूप गई मति इनकी मारी।
जा सरयू के तीर पाप तुम पहले लो धो,
तब संतों के साथ हाथ तुम करना दो-दो!
-ओम प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

नए राजनीतिक अध्याय का आरंभ

अजय शुक्ला
ajay .shukla @lko.jagran .com

'अयोध्या में मेरी सेवा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं अपने ऊपर कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा।' राष्ट्र गौरव और सनातन की पताका के प्रतीक अयोध्या के राम मंदिर में चेतना को झकझोर देने वाली चढ़ावा चोरी की घटना के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपतराय ने इस उद्घोषणा के साथ ही स्वयं को मंदिर के समीप बने तीर्थ क्षेत्र भवन तक सीमित कर लिया था। इस चर्चित बयान के बाद चंपतराय ने राम भक्तों के नाम एक खुली चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने 'मौन' धारण करने की घोषणा की। आहत मन से कहते- 'जिन लोगों पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया, उन्होंने ही धोखा दिया।' विवाद बढ़ने के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन और कई अन्य हलकों से जब उन पर अंगुलियां उठीं, तो साफ कहा कि जब तक एसआइटी की अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती और वह पूरी तरह बेदाग साबित नहीं हो जाते, अयोध्या नहीं छोड़ेंगे।

चंपतराय अब ट्रस्ट से पूरी तरह अलग हैं। अयोध्या उन्होंने अब भी नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके आहत मन को कुछ मरहम लगा है। सावन की शुरुआत संग ही वह तीर्थ क्षेत्र भवन के अपने एकांतवास से बाहर निकलने लगे हैं। अब वह अयोध्या के संतों से भेंट व संवाद कर रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं। सबसे पहले वह एक ट्रस्ट कर्मचारी के यहां आयोजित शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। शनिवार को भी वह गोलाघाट के सीताकांत सदन सहित अन्य मंदिरों में पहुंचे। बताया गया कि अब वह नियमित अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में जाकर संतों का सानिध्य प्राप्त कर संवाद करेंगे।

इधर, जब पूरा देश और विपक्ष नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर भभक रहा था, तब अयोध्या में सरयू की धारा शीतलता प्राप्त कर रही थी। सिर्फ चंपतराय की मनःस्थिति में ही नहीं, अयोध्या में और भी कई बदलाव आए हैं। अयोध्या की बार एसोसिएशन जो सर्वाधिक मुखरता के साथ तीन दिन में चढ़ावा चोरी की जद में आए ट्रस्टियों को अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दे रही थी, वह अब मौन है। इंटरनेट मीडिया और टीवी चैनलों पर उद्गार व्यक्त करने वाले संत भी शांत हैं।

चढ़ावा चोरी पर पूर्ण नियंत्रण के पश्चात राम मंदिर में दुरुस्त की जा रही व्यवस्था। फाइल

मंदिर की व्यवस्था में भी बदलाव आए हैं। अब दानपात्रों को परिसर से उठाने से लेकर, उन्हें सुरक्षित गणना कक्ष तक पहुंचाने, नोटों की गिनती करने और बक्सों को पुनः सील करने तक के प्रत्येक चरण की अनिवार्य वीडियोग्राफी कराई जा रही है। संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में पूरी प्रक्रिया की सघन निगरानी हो रही। एक विशेष आठ सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया गया है, जिसमें बैंक, ट्रस्ट और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। कड़े सुरक्षा प्रोटोकाल और मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो रहा है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के साथ भक्तों की जो भीड़ मद्धिम पड़ी थी, वह फिर पुरजोश है।

इन बदलावों के पीछे 22 और 23 जुलाई को हुईं दो महत्वपूर्ण बैठकों को प्रमुख कारण माना जा रहा है। 22 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई थी जिसमें अन्य निर्णयों के अलावा एक नौ सदस्यीय धार्मिक समिति के गठन का निर्णय हुआ था। इस समिति में पांच स्थानीय संतों- ट्रस्ट अध्यक्ष महांत नृत्यगोपाल दास के उत्तराधिकारी मणिराम दास छावनी के महांत कमलनयन दास, निर्मोही अखाड़ा के महांत दिनेंद्र दास, रामवल्लभ कुंज के महांत राजकुमार दास, राम कथा कुंज के स्वामी रामानंद दास, हनुमत निवास मंदिर के स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण को शामिल किया गया और इसे राम मंदिर के सभी धार्मिक आयोजनों की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसके अगले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह और संघ की तरफ से राम मंदिर के पालक अधिकारी (केयरटेकर) सुरेश भय्या जी जोशी, कृष्णगोपाल, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा व अयोध्या के स्थानीय संतों की एक बैठक हुई। इस बैठक में चंपतराय के योगदान को खूब सराहा गया। संतों ने एकमत से कहा- 'श्रीराम के प्रति समर्पित हिंदुत्व के गौरव चंपतराय को बदनाम करने की मुहिम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती और संत समाज ऐसे कुत्सित अभियान का प्रत्युत्तर देने को तैयार है।'

सार यह था कि अब संत समुदाय चढ़ावा चोरी पर एक-दूसरे पर अंगुली नहीं उठाएगा, बल्कि अंगुली उठाने वालों पर एकजुट हमला करेगा। यह दिख भी रहा। जिस तरह संसद में सांसद पप्पू यादव के प्रहसन पर संतों ने एकजुट हमला बोला वह इसे प्रमाणित भी कर रहा है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में जब विपक्ष चढ़ावा चोरी पर भाजपा को घेर रहा होगा तो उसका जवाब संत समाज व मठ-मंदिरों से भी दिया जाएगा। 'कलंक' अब धुल रहा और राजनीतिक रंग गाढ़ा हो रहा है।

चीन में अल्पसंख्यक

विविधताओं का सम्मान

चीन में 'जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' के तहत सामाजिक वातावरण के निर्माण पर जोर दिया गया है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को यह बढ़ावा देता है

शू फेइहोंग
भारत में चीन के राजदूत

हाल ही में चीन में 'जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' लागू हुआ है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चीनी राष्ट्र के साझा समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाना है और इसे चीन के विभिन्न जातीय समूहों का व्यापक समर्थन मिला है। लेकिन कुछ बाहरी ताकतें इस कानून को 'अल्पसंख्यकों को जबरन आत्मसात करने' का नाम देकर जनमत को गुमराह कर रही हैं। चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन के सदस्य के नाते मुझे इस कानून पर हुई चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था। इसी अनुभव के आधार पर कुछ बातें साझा करना चाहता हूं।

पहला, यह कानून व्यापक सहमति को बढ़ावा देता है और विविधता का सम्मान करता है। चीनी राष्ट्र पांच हजार वर्षों से भी अधिक प्राचीन सभ्यता वाला एक महान राष्ट्र है। लंबे इतिहास में चीन के विभिन्न जातीय समूहों ने एक-दूसरे से सीखते और घुलते-मिलते हुए ऐसी चीनी सभ्यता का निर्माण किया, जिसकी पहचान विविधता में एकता, खुलेपन और समावेश से होती है। विभिन्न जातीय समूहों का रिश्ता ऐसा है कि 'तुम में मैं, मुझ में तुम' की भावना स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। इसलिए 'अल्पसंख्यकों के जबरन आत्मसात' का कथित आरोप महज एक झूठ है। कानून की दृष्टि से चीन का संविधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सभी जातीय समूह समान हैं तथा किसी भी समूह के विरुद्ध भेदभाव और दमन निषिद्ध है। यह कानून संविधान की इसी भावना का पूर्णतः प्रतिबिंब है। इसके प्रविधान संविधान के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि राज्य समानताओं को बढ़ावा देगा, विविधताओं का सम्मान और समावेश करेगा, विभिन्न जातीय समूहों के बीच पारस्परिक सहयोग व सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करेगा।

व्यावहारिक स्तर पर चीन हमेशा अल्पसंख्यक जातीय समूहों की संस्कृति के संरक्षण को महत्व देता रहता है। शीत्सांग (तिब्बत) के पोताला महल और जोखांग मंदिर जैसे सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। 'कुतदगु बिलिग' सहित विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे अनेक प्राचीन ग्रंथों का चीनी और उइगुर भाषाओं में अनुवाद, संपादन तथा प्रकाशन किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल चीन की 45 परियोजनाओं में से एक-तिहाई से अधिक अल्पसंख्यक जातीय समूहों की संस्कृति से जुड़ी हैं।

दूसरी बात, यह कानून सभी जातीय समूहों के विकास के अधिकार की रक्षा करता है। हाल के वर्षों में चीन के आधुनिकीकरण ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका लाभ अल्पसंख्यक जातीय समूहों को भी व्यापक रूप से मिला है। शीत्सांग, शिनच्यांग सहित पांच जातीय स्वायत्त क्षेत्रों का सकल क्षेत्रीय उत्पाद 2012 में 515 अरब डालर से 2025 में 1.21 ट्रिलियन डालर हो गया है। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने कहा है कि चीनी राष्ट्र एक बड़ा परिवार है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को बेहतर जीवन जीना चाहिए। 'जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' साझा समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने को अपना प्रमुख विषय बनाता है। इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों के विकास तथा बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की समानता और सुलभता बढ़ाने के लिए ठोस व विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, ताकि सभी जातीय समूह विकास के लाभ समान रूप से प्राप्त कर सकें।

धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा रहा पोताला महल। फाइल

तीसरी बात, यह कानून विभिन्न जातीय समूहों के आपसी मेल-जोल को बढ़ावा देता है। चीन में अल्पसंख्यक जातियों की एक-तिहाई से अधिक जनसंख्या नगरों तथा बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास करती है। अल्पसंख्यक जातियों की प्रवासी जनसंख्या 3.3 करोड़ से अधिक हो चुकी है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच आपसी मेल-जोल की आवश्यकता बढ़ गई है। 'जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून' में ऐसे सामाजिक वातावरण के निर्माण पर जोर दिया गया है, जहां विभिन्न जातीय समूह साथ रहें, साथ पढ़ें, मिलकर निर्माण करें, उपलब्धियां साझा करें, साथ काम करें और आनंदपूर्वक जीवन बिताएं।

यह कानून चीन की परिस्थितियों के अनुरूप जातीय मुद्दों के सही समाधान का विधिक सार है। यह न केवल चीन के लोगों के हित में है, बल्कि अन्य देशों को भी जातीय मुद्दों से निपटने का उपयोगी अनुभव प्रदान करता है। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं तथा एकीकृत बहुजातीय राष्ट्र हैं। दोनों ने लंबे अनुभव के आधार पर अपनी-अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप जातीय नीतियां विकसित की हैं। चीन भारत के साथ संवाद और आदान-प्रदान को और मजबूत करने का इच्छुक है, ताकि दोनों देश साथ मिलकर राष्ट्रीय शासन के स्तर को उन्नत कर सकें, ग्लोबल साउथ के बहुजातीय देशों के शासन अनुभवों को समृद्ध बना सकें तथा अधिक सौहार्दपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान दे सकें।

मारुति ने जुलाई में रिकार्ड वाहन उत्पादन दर्ज किया

नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) ने जुलाई में अपना रिकार्ड मासिक उत्पादन दर्ज किया है। जुलाई में कंपनी ने 2,48,845 वाहनों का उत्पादन किया, जो पिछले साल के इसी महीने के आंकड़े 1,87,073 इकाई के मुकाबले 33 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन रिकार्ड मार्च, 2026 में बना था, जब उसने 2,31,933 वाहनों का विनिर्माण किया था। (प्रेट्र)

अभी हमारी सहायक कंपनियों के मुद्रीकरण की कोई तात्कालिक योजना नहीं है। फिलहाल सहायक कंपनियों के मूल्य को अनलाक करने पर ध्यान दिया जाएगा।
– अशोक चंद्रा, सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक

एक नजर में

बैंक आफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज घटाया

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आफ महाराष्ट्र ने रविवार को अपने होम लोन पर ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर की घोषणा की। बैंक ने 'मानसून धमाका' विशेष आफर के तहत लिया गया है। आफर के प्रोसेसिंग फीस और दस्तावेजी शुल्क में भी पूरी छूट दी जाएगी। बैंक ने कहा कि यह होम लोन पर सात प्रतिशत और कार लोन पर 7.45 प्रतिशत का ब्याज उद्योग में सबसे कम दरों में से एक है। इससे ग्राहकों पर मासिक किस्त का बोझ कम होता है। (प्रेट्र)

नौ कंपनियों की पूंजी 2.51 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली : बीते सप्ताह शेयर बाजारों में रही तेजी की बदौलत बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 2.51 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सप्ताह के दौरान बजाज फाइनेंस का पूंजीकरण सबसे अधिक 80,345.97 करोड़ रुपये बढ़ा है। इसके अलावा, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआइ, एचडीएफसी बैंक, एलआइसी और आइसीआइसीआइ बैंक का पूंजीकरण भी बढ़ा है। दूसरी ओर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूंजीकरण घटा है। (प्रेट्र)

1,200 करोड़ का आइपीओ ला सकती है एसेट्ज

नई दिल्ली : रियल एस्टेट डेवलपर एसेट्ज लिमिटेड 1,200 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) ला सकती है। इसके लिए कंपनी ने कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर के पास गोपनीय रूट के जरिये दस्तावेज जमा कर दिए हैं। सिंगापुर की निवेश फंड फर्म पार्टनर्स एसेट्ज लिमिटेड की एक प्रमुख शेयरधारक है। गोपनीय रूट के तहत कंपनियों को अपने दस्तावेजों को सार्वजनिक डोमेन से बाहर रखने की इजाजत होती है, जब तक कि नियामकीय समीक्षा प्रक्रिया एक उन्नत चरण तक न पहुंच जाए। (प्रेट्र)

आपात स्थिति में एफडी पर लोन लेना है फायदे का सौदा

अधिकांश भारतीय परिवार भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए फिक्स्ड डिपाजिट यानी एफडी का सहारा लेते हैं। यह निवेश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जरिया है। लेकिन कई बार परिवारों के सामने मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर की मरम्मत जैसे अचानक खर्चे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट होता है कि वह अपनी एफडी को तोड़ें या फिर इसके बदले लोन लें। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि आपातकाल की स्थिति में एफडी पर लोन लेना फायदे का सौदा है। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको कितनी जल्दी और कितने पैसों की जरूरत है। पढ़िए **मनोज कुमार** की रिपोर्ट...

90 प्रतिशत वैल्यू तक मिलता है लोन

फिक्स्ड डिपाजिट यानी एफडी पर आप उसकी वैल्यू का 90 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं। मान लीजिए, आपने एक लाख रुपये की एफडी कर रखी है तो उस पर 90 हजार रुपये तक का लोन मिल सकता है।

एफडी पर लगातार मिलता रहेगा ब्याज

एफडी पर लोन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उस पर पहले से तय दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। कई बैंक एफडी पर लिए जाने वाले लोन के समय से पहले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लेते हैं।

कम ब्याज पर मिलेगा पैसा

यदि आप एफडी पर लोन लेते हैं तो इस पर आपको कम ब्याज देना होगा। आमतौर पर बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज से 1–3 प्रतिशत तक अधिक दर पर लोन दे देते हैं। उदाहरण के लिए : अगर आपको एफडी पर चार प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है, तो उस पर लिए जाने वाले लोन की दर 5–7 प्रतिशत सालाना होगी। सामान्य तौर पर पर्सनल लोन पर ब्याज की दर नौ प्रतिशत से शुरू होती है जो क्रेडिट स्कोर और आय के आधार पर 24–35 प्रतिशत सालाना तक हो सकती है।

लोन का पुनर्भुगतान नहीं करने पर क्या होगा

यदि कोई व्यक्ति अपनी एफडी पर लोन लेता है और वह उसका पुनर्भुगतान नहीं करता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एफडी परिपक्व हो जाएगी तो बैंक लोन की बकाया राशि को इसमें से काट लेगा। इसके बाद एफडी को जो भी पैसा बचेगा, वो आपको मिल जाएगा।

प्रोसेसिंग शुल्क से भी छूट संभव

अधिकांश बैंक पर्सनल या किसी भी अन्य प्रकार के लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क लेते हैं। यह शुल्क कुल लोन राशि का 1–3 प्रतिशत तक होता है। एफडी पर लोन लेने पर कई बैंक प्रोसेसिंग शुल्क से भी छूट देते हैं। इससे लोन लेने की लागत कम हो जाती है।

कैसे करें आवेदन

एफडी पर लोन लेने के लिए ग्राहक आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। चूंकि, बैंक के पास पहले से ही आपके बारे में पूरी जानकारी होती है, ऐसे में एफडी पर लोन लेने के लिए ज्यादा कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है और आवेदन के साथ एफडी, आधार और पैन नंबर जैसी सामान्य जानकारी देनी होती है।

(नोट : यह लेख केवल जानकारी के लिए है। एफडी पर लोन लेने से पहले बैंक से ब्याज दर व अन्य नियमों की अच्छी तरह से पड़ताल कर लें।)

जागरण इन्फो

महंगाई के जोखिमों के बीच रेपो रेट यथावत रहने की संभावना

- प्रमुख अर्थशास्त्रियों व कंपनियों के वित्तीय प्रमुखों ने जताई उम्मीद
- आरबीआइ एमपीसी की बैठक आज से पांच अगस्त तक

मुंबई, प्रेट्र : मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों और विदेशी मुद्रा जमा योजना पर रुख को लेकर प्रतीक्षा के बीच आरबीआइ अपनी अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को यथावत रख सकता है। देश के 10 प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न कंपनियों के वित्तीय प्रमुखों के एक सर्वे में ज्यादातर का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और असमान मानसून से मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों के बीच आक्रामक रुख अपनाते हुए अपनी नीतिगत स्थिति को 'तटस्थ' बनाए रखेगा।

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आरबीआइ 'देखों और इंतजार करो' की मुद्रा में रहेगा क्योंकि वह महंगाई के उभरते परिदृश्य का आकलन कर रहा है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'फिलहाल, मुद्रास्फीति नरम बनी हुई है और ऐसे में यथास्थिति ही सबसे अच्छा नीतिगत विकल्प है।' जैना स्माल फाइनेंस बैंक के वित्तीय प्रमुख गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि केंद्रीय बैंक मानसून की स्थिति और विदेशी मुद्रा जमा योजना की सफलता का इंतजार करेगा। नीतिगत दरों पर फैसला करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) तीन अगस्त से पांच अगस्त के बीच बैठक करेगी। केंद्रीय बैंक ने वृद्धि दर को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल से रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती की है।

जुलाई में बिजली की खपत और कोयला उत्पादन बढ़ा

पिछले महीने बिजली खपत में 11 प्रतिशत और कोयला उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जुलाई 2026 में भारत की बिजली खपत में लगभग 11 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मानसून के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय प्रदर्शन करके बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। देश की स्थापित सौर क्षमता में पिछले एक दशक में 50 गुना वृद्धि हुई है और भारत सालाना क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। आंकड़ें बता रहे हैं कि उच्च आर्द्रता के कारण कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़ी है, जिसने बिजली की खपत और अधिकतम मांग को बढ़ाया है।

- उच्च आर्द्रता के चलते कूलिंग उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली की मांग बढ़ी
- सौर ऊर्जा में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे तेज बढ़ता बाजार बना

बिजली मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2026 में देश की कुल बिजली खपत 170.70 अरब यूनिट (बीयू) रही, जो पिछले वर्ष जुलाई 2025 के 153.88 अरब यूनिट की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कई हिस्सों में उच्च आर्द्रता के कारण वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस की गई है। इस वजह से एयर कंडीशनर जैसे कूलिंग उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ा और बिजली की मांग और खपत दोनों में इजाफा हुआ। अधिकतम बिजली की मांग भी जुलाई में 270.20 गीगावाट पहुंच गई, जो जुलाई 2025 के 220.74 गीगावाट से काफी अधिक है। यह स्तर मई में दर्ज किए गए रिकार्ड मांग 270.82 गीगावाट के लगभग करीब रहा। पिछले साल मई में पीक डिमांड 230.99 गीगावाट थी, जबकि जून 2025 में यह 242.77 गीगावाट रही थी।

महंगे आयातित कोयले पर निर्भरता घटी

कोयला क्षेत्र में भी जुलाई में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। भारत का कोयला उत्पादन जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 7.51 प्रतिशत बढ़कर 6.97 करोड़ टन पहुंच गया, जबकि कोयला डिस्पैच (ताप बिजली संयंत्रों को आपूर्ति) में 17 प्रतिशत की तेजी देखी गई है। यह 8.63 करोड़ टन रहा। इसका श्रेय प्रमुख तौर पर कोल इंडिया को जाता है। उत्पादन की तुलना में डिस्पैच में ज्यादा वृद्धि थर्मल पावर की मजबूत मांग को दिखाता है। इस दौरान पावर प्लांट्स का भंडारण बढ़ा है। घरेलू उपलब्धता बढ़ने से महंगे आयातित कोयले पर निर्भरता घटी, जिससे सीमेंट, स्टील और कैप्टिव पावर प्लांट्स जैसे उद्योगों को फायदा हुआ है। पावर एक्सचेंज (जैसे आइईएक्स) पर ग्रिड बिजली की स्पाट कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

1.62 लाख मेगावाट हुई स्थापित सौर क्षमता

आंकड़े बताते हैं कि इस माह सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां गढ़ी गई हैं। सरकार की तरफ से जारी फैक्टशीट के अनुसार, भारत की स्थापित सौर बिजली क्षमता 2014 में मात्र 3000 मेगावाट (तीन गीगावाट) से बढ़कर 30 जून 2026 तक 1.62 लाख मेगावाट पहुंच गई है, जो 50 गुना ज्यादा है। वर्ष 2025 में अकेले 37 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई, जिससे भारत सालाना वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ग्रोथ मार्केट बन गया। भारतीय सौर ऊर्जा प्लांट में टैरिफ में जितनी गिरवाट आई है, उतनी और किसी देश में नहीं देखी गई। 2010 में लगभग 18 रुपये प्रति यूनिट से घटकर यह 2.44 रुपये प्रति यूनिट पर आ गया है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

पेट्रोल और डीजल की बिक्री में रहा उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक क्षेत्र की तीन पेट्रोलियम कंपनियों की पेट्रोल और डीजल की बिक्री में जुलाई के दौरान जोरदार उछाल आया। कमजोर मानसून के चलते किसानों और वाहन चालकों की ओर से ईंधन की मांग बढ़ने से ऐसा हुआ।

इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पेट्रोल बिक्री जुलाई में 9.7 प्रतिशत बढ़कर 34.5 लाख टन हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 31.4 लाख टन थी। यह मात्रा जुलाई, 2024 में बेचे गए 29.9 लाख टन से 15.1 प्रतिशत अधिक और 2023 की समान अवधि में दर्ज स्तर से 36.1 प्रतिशत अधिक रही। वहीं, डीजल की बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत बढ़कर 71.2 लाख टन हो गई, जो एक साल पहले 64.3 लाख टन थी।

आज से 3.40 बजे तक खुलेंगे वायदा एवं विकल्प बाजार

मुंबई, आइएएनएस : निवेशकों को तीन अगस्त से शेयर बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि आज से सेबी का संशोधित ट्रेडिंग ढांचा लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य मूल्य निर्धारण को मजबूत करना और बाजार की दक्षता में सुधार करना है।

नए ढांचे के तहत वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) श्रेणी में अब दिन में 3.30 के बजाय 3.40 बजे तक ट्रेडिंग हो सकेगी। हालांकि, गैर-एफएंडओ इक्विटी कैश स्टाक्स के लिए ट्रेडिंग घंटे अपरिवर्तित रहेंगे और बाजार 3:30 बजे बंद होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव प्री-ओपन सेशन से संबंधित है। संशोधित ढांचे के तहत, आर्डर एंट्री विंडो 9:00 बजे से 9:07 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद 9:07 बजे से 9:15 बजे तक आर्डर का मिलान होगा। सेबी का मानना है कि नया क्लोजिंग आक्शन सेशन समापन मूल्यों की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

राष्ट्रीय फलक

क्वांटम मैकेनिक्स के जटिल नियम समझेंगे आइआइटी के छात्र

जागरण संवाददाता, कानपुर

- प्रो. मनोज कुमार हरबोला की अभिनव पहल से तैयार हुई कामिक बुक
- ग्राफिक की मदद से दो दोस्तों की यात्रा का किया गया है वर्णन

क्वांटम मैकेनिक्स जैसे अत्यंत जटिल विषय को सहज, सरल और मनोरंजक बनाने के लिए आइआइटी के प्रोफेसर मनोज कुमार हरबोला ने एक अनूठी कामिक बुक तैयार की है। इसमें ग्राफिक चित्रों की मदद से दो दोस्तों की हिमाचल प्रदेश की यात्रा का वर्णन किया गया है। हिमाचल यात्रा और 'रहस्यमयी साझा सपने' पर आधारित कथा की यह पहल उन छात्रों को ध्यान में रखकर की गई है, जो भौतिकी के अमूर्त सिद्धांतों और गणितीय समीकरणों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रो. हरबोला के मुताबिक कामिक का उद्देश्य विज्ञान को समझने का तरीका बदलना है। खेल-खेल में सीखने से जिज्ञासा बढ़ती है और यही बेहतर सीखने की सबसे मजबूत नींव होती है।

क्वांटम मैकेनिक्स के मूलभूत स्तंभों को इस कामिक बुक में दैनिक जीवन के उदाहरणों और रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संस्थान की डिजाइन टीम ने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आइआइटी के दो छात्रों के हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज और उसके पास स्थित त्रियुंड पर्यटन स्थल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक रोचक कहानी के माध्यम से यह कामिक बुक क्वांटम भौतिकी के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इसमें क्वांटम एंटैंगलमेंट और वेवफंक्शन समेत अन्य सिद्धांतों को शामिल किया गया है। समीकरणों के बजाय रोजमर्रा की घटनाओं के माध्यम से क्वांटम सिद्धांतों को समझाया गया है। एक प्रसंग में सूर्योदय के जरिये बताया गया है कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश भी क्वांटम प्रक्रियाओं का परिणाम है। कथा के मुख्य पात्र दो दोस्त अपनी यात्रा के दौरान रात में एक जैसा ही सपना देखते हैं। इसकी वजह दोनों का निरंतर साथ रहते हुए एक जैसा व्यवहार है। प्रो. हरबोला के अनुसार बिना किसी संचार माध्यम के दो दोस्तों द्वारा एक ही सपना देखना यह दर्शाता है कि कैसे दो 'एंटैंगल्ड' कण एक निर्धारित दूरी के बावजूद एक-दूसरे से सीधे जुड़े रहते हैं। सपने के अम्यूजमेंट पार्क में पासे और सीढ़ियों का उलटा काम करना क्वांटम दुनिया की अनिश्चितता और नान-क्लासिकल व्यवहार का प्रतीक है।

आइआइटी प्रो. मनोज कुमार हरबोला। संस्थान

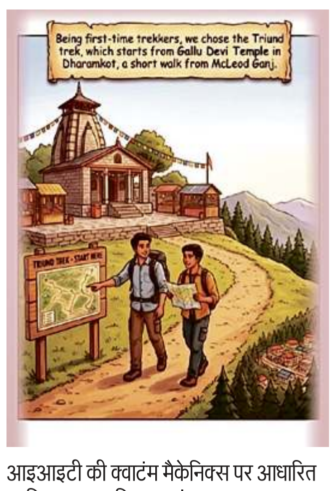

आइआइटी की क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित कामिक बुक का हिस्सा। संस्थान

विज्ञान की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए आइआइटी इससे पहले भी कई पहल कर चुका है। वर्ष 2025 में आइआइटी ने सेंटर फार एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग एक्सीलेंस (सर्टेक्स) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कक्षा शिक्षण में नवाचार को बढ़ावा देना है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से आइआइटी की ड्रामेटिक्स सोसायटी हर वर्ष विज्ञानियों और वैज्ञानिक खोजों पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर रही है। इनमें परमाणु विज्ञान, एलन टयूरिंग के जीवन और डीएनए पर आधारित प्रस्तुतियां शामिल हैं। इन नाटकों को देखने के लिए हर वर्ष करीब एक हजार लोग परिसर में पहुंचते हैं।

वाट्सएप पर बिजनेस मैसेज के लिए हो सकता है अलग फोल्डर, नए फीचर की तैयारी

वाशिंगटन, एएनआइ : वाट्सएप नए फीचर का परीक्षण कर रहा है। यह फीचर यूजर्स की मुख्य चैट लिस्ट को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा। इसके तहत बड़े बिजनेस जैसे बैंक या एयरलाइन से आने वाले मैसेज तय समय के बाद अपने-आप अलग "आफर्स और अपडेट्स" फोल्डर में चले जाएंगे। भविष्य में छोटी कंपनियों के मैसेज के लिए यह सुविधा मिलेगी।

जीएसएम एरेना की नई रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स के इनबाक्स को व्यवस्थित रखना है। बताया जाता है कि वाट्सएप विभिन्न समय सीमाओं के साथ इस फ़ीचर का परीक्षण कर रहा है, जिसमें 24 घंटे तक की समय सीमा शामिल है।

जो यूजर्स इस फीचर का उपयोग नहीं करना चाहते, उनके पास एप की सेटिंग्स के माध्यम से इसे बंद करने का विकल्प होगा। हालांकि, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि यूजर्स बिजनेस मैसेज के अलग फोल्डर में जाने की अवधि अवधि नहीं चुन सकेंगे।

सुनियोजित हिंसक कृत्य था केरल में अधिकारियों पर हुआ हमला : ईडी

- केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा- यह अचानक हुआ विरोध-प्रदर्शन नहीं था
- हमले के आरोपित की जमानत याचिका का केरल हाई कोर्ट में किया विरोध

कोच्चि, प्रेट्र : ईडी ने केरल हाई कोर्ट में कहा है कि इस साल मई में अधिकारियों पर हुआ हमला अचानक हुआ विरोध-प्रदर्शन नहीं था। यह सुनियोजित और संगठित हिंसक कृत्य था। हमले के आरोपित की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने यह बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन के घर पर तलाशी के बाद 27 मई को ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया था।

ईडी के मुलाबिक उसके अधिकारियों पर हुए हमले को कानून-व्यवस्था की सामान्य घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह हमला कई घंटों तक चली तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की बेटी की कंपनी और सीएमआरएल के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जांच के सिलसिले में की थी।आरोप है कि विजयन की बेटी वीना और उनकी कंपनी 'एक्सलाजिक साल्यूशंस' को 2017 और 2020 के बीच सीएमआरएल से आइटी और कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए पैसे मिले, जबकि ये सेवाएं कभी दी ही नहीं गईं। जब ईडी के अधिकारी तलाशी के बाद वहां से निकल रहे थे, तो भीड़ ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक ड्राइवर, एक सीआरपीएफ अधिकारी और तलाशी टीम के एक सदस्य को चोटें आईं।

ईडी ने दावा किया है कि आरोप केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों पर सुनियोजित और संगठित हमले की ओर इशारा करते हैं। भीड़ का मकसद सिर्फ तलाशी की कार्रवाई का विरोध करना नहीं था, बल्कि कानूनी जांच में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकना, जांच अधिकारियों को डराना-धमकाना और आपराधिक न्याय व्यवस्था को सही ढंग से चलने से रोकना था।

बिहार के रवि बने दुनिया के सबसे तेज लिखने वाले शख्स

जासं, आरा (भोजपुर) : कहते हैं कि जुनून और हुनर मिल जाएं तो पहचान खुद रास्ता तलाश लेती है। बिहार के भोजपुर जिले के निवासी रवि कुमार ने अपने अनोखे हुनर से ऐसा ही कर दिखाया है। महज 9 सेकेंड 15 मिलीसेकेंड में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 बड़े अक्षर लिखकर उन्होंने इंटरनेशनल बुक आफ रिकार्ड में नाम दर्ज कराया है। इसी के साथ रवि दुनिया के सबसे तेज लिखने वाले व्यक्ति बन गए हैं।

शिक्षक रवि कुमार ने 26 मई को यह रिकार्ड बनाया था। रिकार्ड बनने के बाद वीडियो और अन्य साक्ष्यों की कई स्तरों पर जांच की गई। विभिन्न जजों ने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और सभी प्रमाणों की पुष्टि के बाद करीब दो महीने की प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें आधिकारिक रूप से विश्व रिकार्डधारक घोषित किया गया। रवि बताते हैं कि बचपन से उनका सपना था कि लोग उन्हें गूगल पर सर्च करें।

नियमों के उल्लंघन पर शराब बनाने वाली कंपनियों पर एफएसएसएआइ की कार्रवाई

- नियामक ने यूएसएल के बारामती और मप्र स्थित संयंत्रों को जारी किया नोटिस
- इनब्रू बेवरेजेज पर भी कार्रवाई, 'फ्लेवर' मिलाने के नियमों का किया उल्लंघन

नई दिल्ली, प्रेट्र : एफएसएसएआइ ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और इनब्रू बेवरेजेस समेत शराब बनाने वाली कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है। खाद्य नियामक ने रविवार को कहा कि इन शराब कंपनियों की फैक्ट्रियों को ऐसे 'फ्लेवर' मिलाने के लिए नोटिस जारी किया है, जो किसी उत्पाद के प्राकृतिक स्वाद जैसे लगते हैं। हालांकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने स्पष्ट किया कि 'फ्लेवरिंग' पदार्थों (स्वाद एवं सुगंध देने वाले पदार्थों) के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नोटिस इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि कुछ निर्माता नियमों के खिलाफ मानकीकृत मादक पेय में उसी का 'फ्लेवर' मिला रहे हैं।

एफएसएसएआइ ने 10 जुलाई को कहा था कि उसने खाद्य संरक्षा एवं मानक (मादक पेय) विनियम, 2018 के उल्लंघन के आरोप में कई शराब निर्माताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन उल्लंघनों में बिना अनुमति 'फ्लेवर' मिलाना और उत्पाद की समयसीमा संबंधी दावों का नियमों के अनुरूप न होना शामिल है। हालांकि उस समय एफएसएसएआइ ने शराब बनाने वाली कंपनियों और उनके संबंधित फैक्ट्रियों के नाम की जानकारी नहीं दी थी।

एफएसएसएआइ ने रविवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) के बारामती स्थित संयंत्र को नोटिस जारी किया गया है, जहां मैकडावेल्स नंबर 1 रम का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही यूएसएल के मध्य प्रदेश स्थित संयंत्र को भी नोटिस दिया गया है, जहां एंटीक्विटी ब्लू व्हिस्की और रायल चैलेंज व्हिस्की का उत्पादन किया जाता है।

वन अधिकारी की मौत मामले में ओडिशा के आइएफएस अधिकारी निलंबित

जासं, भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने राज्य के गजपति जिले में 2021 में एक वन अधिकारी की रहस्यमय मौत के मामले में संलिप्तता के आरोप में भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर की गई है। संग्राम केशरी बेहरा वर्तमान में ओडिशा फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (ओएफडीसी) के निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर तैनात हैं। उन्हें परलाखेमुंडी के तत्कालीन सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) सौम्य रंजन मोहापात्र की मौत के मामले में आरोपित बनाया गया है।

ओडिशा वन सेवा के 2018 बैच के अधिकारी मोहापात्र 11 जुलाई 2021 को अपने घर में आग से गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के समय उनकी पत्नी भी घर में मौजूद थीं। अगले दिन 12 जुलाई को कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

भारतमाला घोटाला : ईडी ने कुर्क की 12.78 करोड़ रुपये की 62 संपत्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण • रायपुर

- 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र कोर्ट में पेश
- रायपुर-विशाखापत्तनम एनएच भूमि अधिग्रहण में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई

ईडी ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की 62 चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के रायपुर-विशाखापत्तनम नेशनल हाईवे से जुड़े मामले में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में 4.69 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी शामिल हैं। मामले में अब तक 36.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने जय प्रकाश गांधी और 13 अन्य आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है।

आरोपितों ने जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर कई गुना अधिक मुआवजा वसूला था। शिकायत पर ईओडब्ल्यू-एसीबी ने अभनपुर के तत्कालीन एसडीओ (राजस्व) निर्भय साहू और अन्य के खिलाफ 23 अप्रैल 2025 को एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।

फर्जी कागजातों से 9.27 करोड़ रुपये की अवैध कमाई : ईडी की जांच में राजफाश हुआ कि आरोपित जय प्रकाश गांधी और उनके परिवार को केवल 56.76 लाख रुपये का वैध मुआवजा मिलना था, लेकिन फर्जीवाड़ा कर उन्होंने 9.83 करोड़ रुपये हासिल किए। ग्राम नायकबांधा के कई अन्य भूमि स्वामियों और लाभार्थियों ने भी खसरा नंबरों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर निर्धारित पात्रता से कहीं अधिक मुआवजा प्राप्त किया। वहीं, उगेतरा गांव में एक महिला उमा तिवारी ने मृत भू-स्वामी की गोद ली हुई बेटी का फर्जी रिकार्ड बनवाकर 2.13 करोड़ रुपये का अवैध मुआवजा हड़प लिया।

भारत ने चीन के सिर्फ एक एफडीआइ प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने पिछले वित्त वर्ष में चीन के केवल एक एफडीआइ प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका मूल्य एक करोड़ रुपये था। हालांकि, हांगकांग से आए 610.42 करोड़ रुपये के 13 आवेदनों को मंजूरी दी गई। ये मंजूरियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए अप्रैल 2020 से पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के 'प्रेस नोट 3' के तहत किया गया। यह उपाय कोरोना महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अधिग्रहणों को रोकने के लिए किया गया था।

डीपीआइआइटी के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर सरकार ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान 10,292.67 करोड़ रुपये (1.18 अरब डालर) मूल्य के 63 एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

गीतारहस्य आणखीही बरेच काही सांगते!

‘‘**तरुण पिढीने** ‘गीतारहस्य’ वाचून टिळकांचे विचार समजून घ्यावेत म्हणजे चूक होणार नाही’’ असा सल्ला गृहमंत्री अमित शहा यांनी तरुण पिढीला दिल्याचे वाचनात (२ ऑगस्ट) आले. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाचा याला संदर्भ असणार, हे उघड आहे. पण गीतारहस्यामधील या सल्ल्याशी सुसंगत असे आणखी किमान एक-दोन विचार त्यांनी सांगितले असते तर ते अधिक उचित ठरले असते. वाचन, (मनन, चिंतन ही फार दूरची गोष्ट) लेखनाची सवय आजच्या बहुतेक राजकारण्यांना नाही. त्यामुळे ज्या महापुरुषाच्या नावाने समारंभ असतो, त्या ‘महापुरुषाचे विचार समजून घेणे आवश्यक आहे’ असे मोघमपणे बोलण्याची ‘चाणक्यनीती’ अवलंबिली जाते.

वि. वा. शिरवाडकर यांचे बंधू के. रं. शिरवाडकर यांनी ‘सार गीतारहस्या’चे या पुस्तकात टिळकांच्या मूळ पुस्तकाचे सुरेख विवेचन व विश्लेषण केले आहे. त्यात त्यांनी एकेठिकाणी टिळकांचे मत नोंदविले आहे ते असे, ‘कोणतीही कृती करायची ती कर्तव्य म्हणून, सूड म्हणून नव्हे’ (पृष्ठ:९९). आंदोलनकर्ते विद्यार्थ्यांच्या विरोधात पोलिसांनी एका प्रकारे सूड बुद्धीने केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांना हा विचार मान्य आहे का? तसेच ‘सर्व धर्मांबद्दल सहिष्णुता दाखवणारा गीताधर्म सफल वैदिक धर्माचे सार आहे.’ ‘जे कोणाचा द्वेष करीत नाहीत व कशाचाही लोभ ठेवीत नाहीत, ते कर्मयोगी समजावेत.’ (पृष्ठ: १२५, १४२) तसेच अन्य काही विचार आहेत, ते अमित शहांना मान्य आहेत का?

■ **अनिल मुसळे,** ठाणे

तुम्ही जेन-झींबाबत संयम दाखवलात का?

‘**जेन-झींना संयमाचा** सल्ला’ ही बातमी (२ ऑगस्ट) वाचली. तरुण पिढीने ‘गीतारहस्य’ वाचून टिळकांचे विचार समजून घ्यावेत, म्हणजे चूक होणार नाही, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात केले. गीतारहस्य मानवी जीवनातील नैतिक आचरणाची तत्त्वे आणि कर्तव्ये स्पष्ट करते. ती तत्त्वे तर फक्त तरुण पिढीच नव्हे तर प्रत्येकाने, विशेषतः राजकीय व्यक्तींनीही समजून घेणे सद्य राजकीय परिस्थितीत अत्यंत आवश्यक आहे. महाभारतात पांडवांनी फोडाफोडी करून कौरवांना आपल्यात समाविष्ट करून घेण्याची नीती अवलंबिली नाही याची आठवणही या निमित्ताने विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना करून देणे आवश्यक आहे. दिल्लीतील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनात सत्ताधारी पक्ष गीतेत सांगितलेल्या नैतिकतेने तरुणाईशी वागला का याचे आत्मपरीक्षण केंद्रीय गृहमंत्री कधी करणार?

■ **प्रवीण आंबेसकर,** ठाणे

नैतिकतेचे धडे देण्याचा अधिकार आहे?

पंतप्रधानांविषयी जेन-झींनी वापरलेल्या भाषेचा आज निषेध केला जात आहे. पण हा निषेध तत्त्वाचा आहे, की सोयीचा? राजकीय भाषेचा दर्जा घसरला, असे आज म्हणणारे लोक तेव्हा कुठे होते, जेव्हा विरोधकांविषयी वैयक्तिक, उपरोधिक आणि अवमानकारक भाषा वापरली जात होती?

सोनिया गांधींबाबत ‘जर्सी गाय’ अशा उल्लेखांपासून, ‘काँग्रेसची विधवा’सारख्या शब्दप्रयोगांपर्यंत, शशी थरूर यांच्या पत्नीविषयी ‘५० करोड की गर्लफ्रेंड’ अशा टीकेपासून ते ‘दीदी, ओ दीदी’ सारख्या सार्वजनिक उपरोधापर्यंत या सर्वांवरही तेवढ्याच तीव्रतेने आक्षेप घेतले गेले होते का? की तेव्हा ते निवडणुकीतील ‘राजकीय शैली’ म्हणून चालून गेले?

त्या वेळी हे सर्व स्वीकारार्ह वाटत असेल, तर आज नैतिकतेचे धडे देण्याचा अधिकार कुणाला आहे? आणि आज जर हे चुकीचे असेल, तर तेव्हाही हेच तत्त्व सर्वांना लागू नव्हते का? पंतप्रधानांचा मान राखलाच पाहिजे, पण लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांचाही तितकाच मान राखला पाहिजे.

■ **राम रेठे,** परतवाडा

हळवे, संवेदनशील पंतप्रधान...

*‘**दुसऱ्यांनाही आई** असते’ असा उल्लेख असलेली बातमी (२ ऑगस्ट) वाचली. आपल्या संवेदनशील पंतप्रधानांनी जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांनी शिवीगाळ केली किंवा शिवराळ भाषा वापरली याबद्दल त्यांना माफ केले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे यांनी दुसऱ्यांनाही आई असते असे म्हटले आहे. पण भेदभाव संस्कृतीमध्ये आपल्यालाच आई असते, दुसऱ्यांना कधीही आई नसते, याची माहिती राज ठाकरे यांना नसल्याचे दिसते. आपलीच मने दुखावतात, दुसऱ्याची मने कधीच दुखावत नाहीत. जंतर-मंतरवर न जाताही आपल्याबद्दल, आपल्या आईबद्दल शिवराळ भाषा वापरली. याचे ज्ञान यांना कसे होते, हे समजत नाही. संवेदनशील पंतप्रधानांना माफी मागण्याची सवय नाही. माफ करण्याची सवय आहे. आपले पंतप्रधान फार हळवे आहेत. त्यांचे संवेदनशील मन त्यांचे चाहते सतत जपत असतात. ते जपताना आपल्या पदाचेही भान काही जणांना राहात नाही. भारताच्या इतिहासात अशा संवेदनशील पंतप्रधानांबद्दल मोठ्या कथा रचल्या, ऐकल्या, वाचल्या जातील.*

■ **युगानंद गुलाबराव साळवे,** पुणे

जेन झी हा भ्रम, ते एक थोतांड...

सध्या सगळीकडे जेन झी चे कौतुक सुरू असले तरी जेन झी हे एक थोतांड आहे, निर्माण केला गेलेला भ्रम आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी आंदोलन, हिंसा, दंगा घडवून आणायचे कारस्थान आहे. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका देशात दंगे, हिंसक आंदोलन होऊन सत्तापालट झाला. आता त्या देशातून गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नाहीसा झाला?

जयप्रकाश नारायण यांना संपूर्ण क्रांती करायची होती, इंदिरा गांधी यांना गरिबी हटवायची होती. आता देशातील परिस्थिती आणखीन वाईट झाली आहे. कारण सतत वाढणारी लोकसंख्या. देशात मृगजळाचा महापूर आहे.

■ **सुधीर केशव भावे,** जोगेश्वरी, मुंबई

सत्ताधारी आमदारांचाही हाच मार्ग?

‘**स... स... सुधारणांचा**’ हा सत्ताधारी आमदार आशीष देशमुख यांचा लेख (२ ऑगस्ट) वाचला. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या गच्छंतीस राजीनामा वा पदत्याग असे संबोधणे हे ‘नीट’ अव्यवस्थेमुळे जगाचा निरोप घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक नाही का? तद्नंतर लगेचच, ज्या प्रकारे माजी शिक्षणमंत्री महोदयांचे संसदेत स्वागत करण्यात आले, त्यांचा जो काही विशेष सत्कार घडवून आणला गेला ते आमदार महोदयांच्या नजरेतून सुटले का? यातून काय संदेश द्यायचा होता सत्ताधाऱ्यांना? शिक्षणात सुधारणा घडवून आणायची म्हणजे शिक्षणमंत्र्यांपासून त्याची सुरुवात नको? बदली शिक्षणमंत्र्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, तसे काही घडताना दिसते का खुद्द आपल्याला तरी? लेखात असे म्हटले आहे की ‘जेन-झी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नव्या पिढीची मागणी पूर्ण झाली. येथेच चुकताय आपण, एक सत्ताधारी राजकारणी व माणूस म्हणूनसुद्धा, ही केवळ ‘जेन-झीं’ची मागणी नव्हे तर संपूर्ण देशाची मागणी होती हे अजूनही लक्षात येत नाही का सरकारदरबारी? का कळून न कळल्यासारखे भासवण्यातच पुरुषार्थ! शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा स्वागतार्ह असल्या तरी, राज्य म्हणून यातील किती एक गोष्टी आपण अमलात आणल्या आहेत? किंवा तसे प्रयत्न विद्यमान केले गेले? सरकारी शाळांची दुरवस्था, शिक्षकांची कमतरता, शाळा बंद पडणे हे तर नित्याचेच झाले आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या रास्त मागण्यांची तरी कधी दखल घेतली आपल्या सरकारद्वारे? मग हल्ली सत्ताधारीदेखील मोर्चे काढायला लागले त्याप्रमाणे, सत्ताधारी आमदार सार्वजनिक माध्यमांवर लेख लिहून आपल्या कर्तव्यांचे वहन केव्हापासून करायला लागलेत? का सत्ताधारी आमदारांनाही आपला आवाज विधिमंडळात व सत्ताधारी मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा मार्ग आचरावा लागतो आहे का?

■ **अचला नेने,** पुणे

मान्सूनचा अभ्यास अधिक व्यापक व्हावा

‘**हवा बदलते** आहे!’ हे संपादकीय (१ ऑगस्ट) वाचले. अलीकडील वर्षांतील अनुभव स्पष्टपणे सांगतात की, भारतातील पावसाचे वर्तन समजून घेण्यासाठी केवळ एल निनो हा एकच घटक पुरेसा नाही. हिंद महासागरातील तापमानातील बदल, इंडियन ओशन डायपोल (IOD), मॅडन-ज्युलियन ऑसिलेशन (MJO), अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरातील हवामानातील बदल तसेच जागतिक हवामान बदल यांसारख्या अनेक घटकांचा मान्सूनवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे हवामान अंदाज अधिक अचूक करण्यासाठी बहुआयामी संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज आहे.

■ **गणेश दळवी,** आष्टी, जि. बीड

नदी वाचवण्यासाठी सरसावले ‘जेन-झी’

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांना अल्बानियातील व्हिजोसा नदीच्या परिसरात एक आलिशान रिसॉर्ट बांधायचे होते. फ्लेमिंगोसह अनेक प्रजातींचा अधिवास असलेल्या या नदी परिसराचे संरक्षण करण्यासाठी अल्बानियातील जेन-झींनी गेले काही महिने तीव्र आंदोलन छेडले आहे.

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

जगभर २०-३० वयोगटातील तरुण पिढी अर्थात जेन-झींच्या राजकीय क्रांतींची चर्चा आहे. नेपाळपासून व्हेनेझुएलापर्यंत मोठ्या प्रमाणात जेन-झी क्रांतींनी राज्यसत्तेला दणका दिला. पण या क्रांतींवर होणारी महत्त्वाची टीका म्हणजे त्या फक्त सरकारविरोधी प्रतिक्रिया आहेत, कुठलंही ठोस समाधान देऊ शकत नसल्यामुळे त्या प्रतिरोध (रेझिस्टन्स) होत नाहीत. मग या क्रांतीकडे कसे पाहावे? तसेच नदीसाठी आणि नदीमुळे अशी जेन-झी क्रांती झाली आहे का?

जेन-झी... जागतिकीकरणानंतर जन्माला आलेली, इंटरनेटसोबतच लहानाची मोठी झालेली एक आगळीवेगळी पिढी. आधीच्या पिढ्यांपेक्षा ‘यांची’ भाषा वेगळी. संयम ठेवल्यास सरकारी व्यवस्थेत गोष्टी बदलतात हे या पिढीला मान्य नाही. संयम ठेवणे म्हणजे, आहे ते स्वीकारणे, जैसे थे धोरण अवलंबणे असं या पिढीचं थेट मत. जे सरकार आपल्या समस्या गांभीर्याने घेत नाही, ते सरकार हवंच कशाला? असं सरकार असल्यापेक्षा गेलेलं बरं, हा त्यांचा बेधडक पवित्रा. या पवित्र्यातूनच मग नेपाळ, बांगलादेश, मादागास्कर, पेरू इत्यादी देशांमध्ये झालेल्या जेन-झी क्रांतीतून एकतर राष्ट्राध्यक्षांनी पलायन केलं किंवा सरकार बदललं.

क्रांती म्हणजे काय? त्वरित होणारा बदल ही क्रांतीची ढोबळ व्याख्या. राजकीय क्रांती म्हणजे त्वरित झालेले सत्तांतर किंवा राज्यसंस्था कोसळणे. मग फ्रेंच राज्यक्रांतीत राजेशाही पायउतार होऊन लोकशाही येते, ब्रिटिश लोकशाही पद्धतीची जागा नवी अमेरिकन लोकशाही पद्धती घेते. अशा कमी काळात झालेल्या राजकीय स्थित्यंतरांची अनेक उदाहरणं देता येतील. पण या क्रांतींचं पुढे काय झालं? अमेरिकन राज्यक्रांतीतून आलेली नवीन लोकशाही टिकली, फ्रेंच राज्यक्रांतीतून सत्तेवर आलेल्या लोकशाहीचा मात्र काही वर्षांत अंत होऊन नेपोलियनसारख्या सम्राटाने फ्रान्सचा ताबा घेतला. असंच काहीसं लॅटिन अमेरिकेतील १८व्या शतकातील क्रांतीनंतर झाल्याचं दिसून येतं. एखादी क्रांती जेव्हा केवळ एक सवंग प्रतिक्रिया असते, तेव्हा ती अयशस्वी ठरते का? प्रतिक्रियात्मक क्रांती म्हणजे काय? क्रांतीच्या संदर्भाने प्रतिक्रिया म्हणजे-‘आहे ते नाकारणे’. आहे ते’ बदलायला कोणताही पर्याय प्रतिक्रिया देत नाही. मग मुबारक सरकार नको म्हणून झालेली इजिप्तमधील क्रांती असो, वा क्विंग राजवट नको म्हणून झालेली चिनी क्रांती असो. या राज्यक्रांतीतून आलेल्या नव्या राजवटी फार काळ टिकल्या नाहीत, कारण त्या निव्वळ प्रतिक्रिया होत्या. कोणताही सक्षम पर्याय त्यांनी दिला नाही.

प्रतिरोधाचे (resistance) तसे नाही. प्रतिरोध फक्त आहे ते केवळ नाकारतच नाही, तर त्याला तेवढाच उत्तम, वास्तविक आणि सक्षम पर्याय देतो. त्यासाठी प्रतिरोधाला तात्त्विक आणि राजकीय विचारांचे अधिष्ठान असते. अमेरिकन राज्यक्रांतीला जॉन लॉक याच्या तत्त्वज्ञानाचे, तसेच जेमस मिल आणि थॉमस पेन यांच्या राजकीय विचारांचे अधिष्ठान होते. त्यातूनच नवीन अमेरिकन लोकशाहीचा सक्षम पर्याय आला. म्हणून तो प्रतिरोध ठरला. फ्रेंच राज्यक्रांतीला रुसोच्या तात्त्विक विचारांचे अधिष्ठान असेलही, पण त्याच्या राजकीय विचारांतील लोकशाही काही त्यांना वास्तवात आणता आली नाही. ती प्रतिक्रियाच उरली. सारांश, जिथे राज्यक्रांती यशस्वी झाली, तिथे हे तात्त्विक-राजकीय विचारांचे अधिष्ठान ठळकपणे दिसते. जिथे क्रांती अयशस्वी होते तिथे एकतर अराजकाचा काळ येतो किंवा कोणीतरी भलतेच सत्तेवर चढते. त्यातून नवे सृजन होत नाही.

पण मग प्रतिक्रिया महत्त्वाची नाही? असे अजिबात नाही. प्रतिक्रिया हीच कोणत्याही प्रतिरोधाची सुरुवात असते. आहे ते नाकारल्याशिवाय नव्याचे सृजन होणार कसे? तसेच प्रतिक्रिया या हवेतून येत नाहीत. जनतेला झालेल्या त्रासाचे, तिच्या खंगलेल्या आणि भंगलेल्या मनोवस्थेचे, बराच काळ धुमसत असलेल्या जनक्षोभाचे प्रकटीकरण म्हणजे या राजकीय प्रतिक्रिया असतात. एखादी तात्कालिक घटना प्रतिक्रियेला फक्त वाट मोकळी करून देते. त्या घटनेतून उभे राहिलेले राजकीय प्रश्न तिचे माध्यम होतात. मग एखादी नदी असे माध्यम बनू शकते?

या प्रश्नाचे उत्तर अनेक दुर्मीळ प्रजाती ज्या नदीच्या कवेत विसवतात ती अल्बानियातील व्हिजोसा नदी देते. एका आकडेवारीनुसार, प्राण्यांच्या आणि वृक्षांच्या संपत चाललेल्या तब्बल ११०० प्रजाती या नदीच्या २७० किमी लांबीच्या नदीपात्रात सापडतात. या अलौकिक जैवविविधतेमुळेच तिला २०२३ मध्ये राष्ट्रीय उद्यानाचाही दर्जा देण्यात आला. याच नदीच्या मुखात विजोसा-नारटा पाणथळ प्रदेश आहेत. समुद्राला नदीशी जोडणाऱ्या नारटा लगून (lagoon) आणि विजोसा या नदीच्या मुखातील सुंदर प्रदेशात फ्लेमिंगो, पेलिकन असे असंख्य पक्षी स्थिरावतात.

२०२१ मध्ये अमेरिकेतील एक श्रीमंत उद्योगपती आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आपल्या पत्नीसोबत सुट्टीमध्ये या प्रदेशात आले. इथे फिरत असताना विजोसा-नारटा पाणथळ प्रदेशात एक रिसॉर्ट तसेच श्रीमंत लोकांसाठी आलिशान हॉटेल आणि सफारी उभी करावी असे या जोडप्याच्या मनात आले. तो विचार घेऊन ते अमेरिकेला परतले. तीन वर्षं उलटली. अमेरिकेत सार्वत्रिक निवडणुका लागल्या. या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रपती बायडेन यांचा पराभव झाला, आणि कुशनर

अल्बानियामध्ये गेले तीन महिने रोज रात्री जेन-झींची आंदोलने, संसदेवरील धडक मोर्चे सुरू आहेत.

यांचे सासरे डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आले. या महत्त्वाच्या राजकीय स्थित्यंतरानंतर कुशनर आणि त्यांची पत्नी इव्हांका अल्बानियाला परत आले. राष्ट्राध्यक्ष एडी रामा यांच्याशी त्यांनी आपल्या मनातील रिसॉर्टबद्दल त्यांनी चर्चा केली. एव्हाना संपूर्ण व्हिजोसा नदी राष्ट्रीय उद्यान घोषित झाली होती. त्यामुळे रिसोर्ट बांधणे कायदेशीररीत्या शक्य नव्हते. मग करायचे काय? लागलीच रामा यांनी राष्ट्रीय उद्यानासंदर्भातील कायद्यात घटनादुरुस्ती केली आणि मंजुरी मिळवून दिली. अर्थात त्या रिसोर्टला पर्यावरणासंदर्भातील काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे तरीही बंधनकारक होते.

या रिसॉर्टमुळे नदीपात्राला धक्का बसणार होता. फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होणार होता. मुख्य म्हणजे ही स्थानिकांची नदी एका खासगी उद्योजकाच्या घशात जाणार होती. स्थानिकांचा नदीशी आणि फ्लेमिंगो पक्ष्यांशी असणारा अतूट संबंध तुटणार होता. यामुळेच स्थानिकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या रिसॉर्टला विरोध केला. पर्यावरणासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता केल्याशिवाय तो प्रोजेक्ट सुरू होणार नाही, असं रामा यांनी ठासून सांगितलं. पण तरीही सगळ्या प्रक्रिया धाब्यावर बसवून मे २०२६ मध्ये नदीपात्रात बुलडोझर घुसले. रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी एक कुंपण उभं राहिलं. या कुंपणासमोर संतप्त स्थानिकांनी निदर्शनं करण्यास सुरुवात केली. त्यांची ‘समजूत’ काढायला पोलीसही तिथं आले. पण स्थानिकांचे आंदोलन काही शमेना, तेव्हा कंपनीचे सुरक्षारक्षक पुढे आले आणि काही आंदोलकांना फरफटत घेऊन गेले. त्यांना मारहाणही करण्यात आली. हे सारं होत असताना पोलीस मात्र तिथेच पुतळ्यासारखे गपगुमान उभे होते!

या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि अल्बानियातील जेन-झींचा संताप अनावर झाला. ‘अल्बानिया कोणत्या खासगी कंपनीची मालकी नाही’ असा सूर सर्वत्र उमटू लागला. खासगी कंपनीच्या गुंडांसमोर गुडघे टेकणारे पोलीस आणि त्यांचे सर्वेसर्वा एडी रामा हे कुशनर यांचे हस्तक असल्याची चर्चा होऊ लागली. पाहता पाहता राजधानी तिराना आणि इतर शहरांत तरुणाई जमली आणि देशभर जनप्रक्षोभ उसळला. पण या साऱ्यावर विरोधी पक्षनेते साली बेरीशा यांनी कमालीचे मौन बाळगले होते. यामुळेच ज्यांनी देश विकायला काढलाय त्या रामा यांचे सरकारही नको आणि त्यांना विरोध न करणारे बेरीशाही नको, सगळी संसदच बरखास्त करा अशी मागणी तरुणाई करू लागली. पण हे सारे कशासाठी? तर व्हिजोसा आणि तिचे फ्लेमिंगो वाचवण्यासाठी. यामुळेच या क्रांतीला ‘फ्लेमिंगो क्रांती’ असे नाव मिळाले.

रामा यांचा भ्रष्टाचार, देशातील बेरोजगारी, पर्यावरणाचे प्रश्न आणि त्याला लुटुपुटुचा विरोध करणारे साली बेरीशा या सगळ्याला लोक कंटाळले होते. कुशनरच्या कंपनीच्या कृत्यासाठी या दोघांचा भ्रष्टाचारच जबाबदार असल्याची लोकांची खात्री पटली. यामुळेच या दोन्ही महाभागांना थेट तुरुंगात टाकावे आणि नव्या पक्षांसह पुन्हा लोकशाही स्थापन करावी, या मागणीने जोर धरला. गेले तीन महिने रोज रात्रीची आंदोलने, संसदेवरील धडक मोर्चे यामुळे राज्यकर्ते हैराण झाले आहेत. पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वर्षाव करूनही तरुणाई मागे हटली नाही. रिसॉर्टला तात्काळ स्थगिती मिळाली असली, तरी आंदोलन अजूनही थांबलेले नाही. रामा ‘तुरुंगात’ गेल्याशिवाय बहुतेक थांबणारही नाही. पण रामा आणि त्यांच्या धोरणांना पर्याय काय, याचे मात्र उत्तर फ्लेमिंगो क्रांतीकडे नाही.

फ्लेमिंगो क्रांती ही जेन-झींची ज्वलंत प्रतिक्रिया आहे. विजोसा नदी आणि फ्लेमिंगो पक्षी या प्रतिक्रियेचे थेट माध्यम झाले. नदीच्या माध्यमातून येणाऱ्या अशा प्रतिक्रियांचा नदीच्या संवर्धनासाठी सृजनात्मक प्रतिरोध कसा करावा? हा भविष्यातील नदीकारणासमोरचा प्रश्न आहे. असा प्रतिरोध कुठे झाला आहे का? त्याबद्दल पुढील लेखांत.

कुतूहल

झाडं सूर्यप्रकाशाकडे का वळतात?

बाल्कनीमध्ये ठेवलेलं झाड सरळ ताठ राहावं, म्हणून आपण कुंडी फिरवतो आणि त्याची झुकलेली बाजू सूर्यप्रकाशाच्या उलट दिशेने करतो. पण थोड्याच दिवसांत दिशा बदलून झाडं परत सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढताना दिसतात. झाडाला ना दृष्टी आहे ना मेंदू; तरीही झाडं सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने कशी वाढतात?

पानांमध्ये असणारं हरितद्रव्य सूर्यप्रकाशाची ऊर्जा शोषून घेतं. हवेतून घेतलेला कार्बन डायऑक्साइड आणि मुळांकडून आलेलं पाणी, यांच्या रासायनिक अभिक्रियेतून शर्करा तयार होते. या शर्करेमुळेच झाडाच्या वाढीला आवश्यक असलेली रसायनं मिळतात. कार्बन डायऑक्साइड आणि पाणी यांची रासायनिक अभिक्रिया होण्यासाठी सूर्याच्या ऊर्जेची आवश्यकता असते, जी हरितद्रव्याच्या माध्यमातून शोषली जाऊन झाडाला पुरवली जाते. म्हणून झाडांना सूर्यप्रकाश आवश्यक असतो.

सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढ होण्याच्या झाडांच्या हालचालीला ‘प्रकाशानुवर्तन’ म्हणतात. झाडांत होणाऱ्या अनेक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विविध प्रकारची संप्रेरकं म्हणजेच ‘हार्मोन्स’ असतात. त्यापैकी एक म्हणजे ‘वृद्धीनियामक संप्रेरक’! ते झाडाच्या वाढीला कारणीभूत असलेलं हे संप्रेरक सूर्यप्रकाशापासून दूर, जिथं झाडावर थेट सूर्यप्रकाश पडत नसेल, तिथं परिणामकारक कार्य करू शकतं.

झाडाच्या खोडावर ज्या बाजूने सूर्यप्रकाश पडतो, तिथलं वृद्धीनियामक संप्रेरक त्या बाजूपासून दूर सरकतं आणि खोडाच्या दुसऱ्या बाजूला साठतं. त्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या विरुद्ध दिशेला असणाऱ्या खोडाच्या भागातली पेशींची संख्या वाढते आणि पेशींची वाढही होते. परिणामी या बाजूची लांबी वाढते. पण सूर्यप्रकाशाकडची खोडाची बाजू मात्र लांबीने फारशी वाढत नाही. लांबीत पडलेल्या फरकामुळे, जी बाजू लांबीला जास्त, ती बाजू वाकते. साहजिकच झाडाची फांदी सूर्यप्रकाशाच्या बाजूला झुकते.

सूर्यप्रकाशाच्या बाजूने उत्तरोत्तर होणाऱ्या झाडाच्या या वाढीला ‘धनात्मक प्रकाशवर्तन’ असं म्हणतात. याउलट झाडाची मुळं सूर्यप्रकाशापासून दूर म्हणजे सूर्यप्रकाशाच्या उलट दिशेने जमिनीत खोलवर जातात. या वाढीला ‘धनात्मक गुरुत्ववर्तन’ म्हणतात.

झाडं सजीव असल्यामुळे श्वसनदेखील करतात. त्यासाठी ती हवेतला ऑक्सिजन शोषून घेतात. दिवसा सूर्यप्रकाश असताना कार्बन डायऑक्साइडही शोषून घेतात, पण रात्री सूर्यप्रकाश नसताना अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया होऊ शकत नसल्यामुळे ती कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेत नाहीत. उलट तो बाहेर सोडतात. म्हणून रात्री झाडांजवळ जाऊ नये.

– डॉ. मानसी राजाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

अजिंक्य रहाणेने नुकतीच सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करत एका संस्मरणीय कारकीर्दीला पूर्णविराम दिला. ६ जून १९८८ रोजी संगमनेर तालुक्यातील अश्वी खुर्द येथे मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या रहाणेचा क्रिकेट प्रवास सातव्या वर्षी डोंबिवलीतील एका प्रशिक्षण शिबिरात सुरू झाला. पुढे सराव किंवा सामने खेळण्यासाठी क्रिकेट साहित्याने भरलेली मोठी बॅग घेऊन डोंबिवलीहून रेल्वेने तासनतास प्रवास करून चर्चगेट, दादर किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस गाठावे लागे. मुंबईच्या समृद्ध क्रिकेट संस्कृतीत तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम फलंदाज म्हणून तो घडला. त्याच्यासाठी माजी कसोटीपटू प्रवीण अमरे यांचेही मार्गदर्शन मोलाचे ठरले. शालेय, क्लब आणि रणजी क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर त्याने भारतीय संघात स्थान मिळवले व पुढे कसोटी संघाचा विश्वासार्ह आधारस्तंभ ठरला. तंत्रशुद्ध फलंदाजी, संयम आणि वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध आत्मविश्वासाने खेळण्याची क्षमता, ही रहाणेच्या फलंदाजीची प्रमुख वैशिष्ट्ये. परदेशातील खेळपट्ट्यांवरील त्याची कामगिरी विशेष उठून दिसली. २०१४ मध्ये लॉर्ड्सवरील शतक, तसेच मेलबर्न, वेलिंग्टन आणि जोहान्सबर्ग येथील संस्मरणीय खेळींमुळे त्याने कसोटी फलंदाज म्हणून लौकिक मिळवला. मायदेशातही त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एका कसोटीच्या दोन्ही डावांत शतक झळकावण्याची दुर्मीळ किमया साधली. त्याच्या कारकीर्दीतील सर्वोच्च बिंदू २०२०-२१ चा ऑस्ट्रेलिया दौरा ठरला. ॲडलेड येथे झालेल्या पहिल्या कसोटीत भारताला लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला. या सामन्याच्या दुसऱ्या डावात भारतीय संघ अवघ्या ३६ धावांत गारद झाला. त्यानंतर तत्कालीन कर्णधार विराट कोहली पितृत्व रजेवर गेल्याने नेतृत्वाची जबाबदारी रहाणेकडे सोपवण्यात आली. मेलबर्न येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत त्याने अविस्मरणीय शतक झळकावत भारताला विजय मिळवून दिला. दुखापतींमुळे अनेक प्रमुख खेळाडू संघाबाहेर होत असतानाही युवा आणि नवख्या खेळाडूंना एकत्र बांधून त्याने ब्रिस्बेन येथे भारताला मालिका विजय मिळवून दिला. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वांत संस्मरणीय परदेश दौऱ्यांपैकी हा एक मानला जातो. याच मालिकेदरम्यान प्रेक्षकांतील काहींनी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजवर वर्णद्वेषी टिप्पणी केल्यानंतर, त्या व्यक्तींना मैदानाबाहेर काढल्याशिवाय आम्ही पुढे सामना खेळणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेणारा रहाणेही सर्वांनी पाहिला.

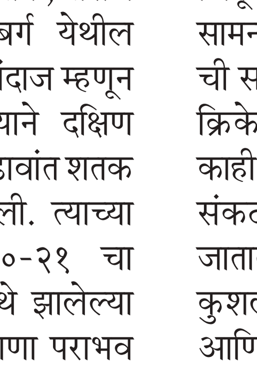

अजिंक्य रहाणे

कारकीर्दीदरम्यान त्याला अनेक चढ-उतारांचा सामना करावा लागला. फलंदाजीतील सातत्य कमी झाल्याने त्याला संघाबाहेरही व्हावे लागले. मात्र, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो मेहनत घेत राहिला. कर्णधार म्हणून त्याने मुंबईला रणजी करंडकही (२०२३-२४) जिंकून दिला. आकडेवारीच्या निकषावर, ८५ कसोटी सामन्यांतील ५०७७ धावा, १२ शतके आणि ३८.५६ ची सरासरी त्याच्या प्रतिभेला पूर्ण न्याय देत नाही. क्रिकेटमध्ये आकड्यांना मोठे महत्त्व असले, तरी काही खेळाडू धावांपेक्षा त्यांनी घडवलेल्या क्षणांसाठी, संकटसमयी दाखवलेल्या धैर्यासाठी ओळखले जातात. अजिंक्य रहाणे त्यापैकीच. झुंजार फलंदाज, कुशल कर्णधार, ‘स्लीप’मधील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आणि एक सुसंस्कृत, संयमी व्यक्तिमत्त्व म्हणून तो भारतीय क्रिकेटप्रेमींच्या कायम स्मरणात राहील.

राजवाडे विचारविश्व

शहाजींच्या कर्तबगारी वर्णनाचे संदर्भस्रोत

‘**नाव, आडनाव,** कुल, वंश व मातृपितृनामे यांची शहानिशा झाल्यावर आता शहाजीच्या कर्तबगारीच्या रूपरेषेची आखणी करण्यास लेखणी मोकळी झाली आहे’, असे सांगत राजवाड्यांनी मग आपल्या संदर्भस्रोतांची माहिती दिली. ‘बृहदीश्वराच्या देवालयातील शिलालेख, शिवदिग्विजय, शिवाजीप्रताप, बसातिने सलातीन (फारसी ग्रंथ) व शहाजी महाराजांची कैफियत या ग्रंथांवरून आणि इतर काही टिपणांवरून व पत्रांवरून ही आखणी (मी) करणार आहे. या साधनांमधील शहाजी महाराजांची कैफियत हे प्रकरण बव्हंशाने ‘बसातिने सलातीना’चाच संक्षेप असल्यामुळे स्वतंत्र साधन म्हणून त्यास यद्यपि फारशी किंमत नाही, तत्रापि शहाजीसंबंधाने इतरत्र न आढळणारी माहिती त्यात आहे. बसातिने सलातीन या फारशी ग्रंथाचा कर्ता शहाजीचे नाव कर्नाटकातील मोहिमांसंबंधात तुरळक काढतो, प्रामुख्याने न काढिता मुसुलमान सेनापतींच्या अनुषंगाने मदतनीस म्हणून गौणत्वाने जरी काढतो तरी मध्येच शहाजी फार शिरजोर झाल्याची तक्रारही करतो. त्यावरून अनुमान करता येते की ह्या कर्नाटकातील मोहिमांत शहाजीचे अंग प्रमुख होते...’

‘शहाजीच्या वरचढ कर्तृत्वाचे दिग्दर्शन शिवदिग्विजय व शिवप्रताप ह्या मराठी बखरींवरून बरेच उठावदार घडते’, असे राजवाड्यांनी त्यानंतर म्हटले खरे, पण पाठोपाठ त्या संदर्भस्रोतांची मर्यादित विश्वासार्हताही स्पष्ट करताना लिहिले, ‘शहाजीचरित्रातील प्रसंग विजयकार किंवा प्रतापकार कालानुक्रमाने, शिस्तवार व कसोशीने न देता मागचे पुढे व पुढचे मागे असे धरसोडीने देतात आणि तेहि देण्यात इतिहासलेखन करण्यातली अनभिज्ञता स्थलोस्थली प्रकट करतात. बृहदीश्वर शिलालेखहि ह्या बखरींच्याच वर्गात पडतो. तो मूलतः बखरच आहे, इतकेच की त्याला दगडावर कोरिला जाण्याचा मान मिळाला आहे. ह्या तिन्ही आधुनिक बखरींमध्ये परंपरागत, कर्णोपकर्णी ऐकलेली व कागदपत्रांवरून काढिलेली जी माहिती दिली आहे, तिला प्रत्यंतर पुरावा दुसऱ्या कोणत्याहि मराठी बाह्य ग्रंथाचा नाही. परंतु लढायांसंबंधाने जी माहिती धरसोडीने दिली आहे तिला बसातिने सलातीनातील किंवा इतर मुसलमानी तवारिखांतील पुराव्याचा पडताळा देऊन पारखिता येते. या साधनांची ऐतिहासिक किंमतही अशी आहे. त्यातून विश्वसनीय भाग निवडून काढून तो कालानुक्रमाने शिस्तवार मांडण्याचा उद्योग आता करावयाचा आहे... पुढे कालांतराने समकालीन कागदपत्रांचा अस्सल पुरावा जेव्हा केव्हा बाहेर येईल तेव्हा येईल, त्यानंतर प्रस्तुत मांडणीत फेरबदल, वाढ किंवा छाट करणे साहजिकच भाग पडेल.’

शहाजींची कर्तृत्वगाथा सांगायला सुरुवात करण्यापूर्वी राजवाड्यांनी अगदी थोडक्यात मालोजीचाही पराक्रम नोंदवला. त्यांनी लिहिले, ‘मालोजी शक १४७२त जन्मला... वयात आल्यावर त्याचा फलटणच्या निंबाळकराच्या मुलीशी विवाह झाला. मवासपणाची (=भाडोत्री सैनिकाची) कवाईत तो बापापाशी व सासऱ्यापाशी सहज शिकला. शक १४९९ मध्ये, सत्ताविसाव्या वर्षी तो शिलेदार झाला. त्यावेळी मूर्तिजा निजामशहा नगरास राज्य करीत होता. शक १५१० पर्यंतची अकरा वर्षे शिपाईगिरी व शिलेदारी करीत करीत तो पाचचार हजार घोड्यांचा मालक बनला... १५१० साली मूर्तिजा निजाम इभ्राईम आदिलशहाच्या कुतुबशहाची बहीण मलिकाजहान हिच्याशी ठरलेल्या लग्नाच्या आड गेला, म्हणून विजापूरचा सरदार दिलावरखान मूर्तिजावर चालून आला. मूर्तिजा त्यावेळी आवश्याच्या किल्ल्यावर राहात होता व मालोजी त्याच्या तैनातीस होता. दिलावरखानाला मोठ्या सफाईने हरवून मालोजीने मूर्तिजाचा बचाव केला. मालोजीच्या ह्या कर्तबगारीचा उल्लेख बृहदीश्वर शिलालेखकर्त्याने केला आहे, एवढेच नव्हे तर १४९९ पासूनच अनेक मोहिमांत पराक्रम गाजवल्यामुळे त्याची साख (=पतप्रतिष्ठा) खूपच वाढल्याचेही म्हटले आहे... अशा ह्या मालोजीला शक १५१५ साली भूमिगत द्रव्य सापडले व जगदंबेचा साक्षात्कार होऊन राज्यप्राप्तीचा वरही मिळाला. ऐतिहासिक दृष्टीने पाहता या वराचा अर्थ असा दिसतो की, महाराष्ट्रराज्य स्थापन करावे, अशी महत्त्वाकांक्षा ह्यावेळी मालोजीच्या मनात अत्यंत अंधुकशी उद्भवली. शक १५१६मध्ये मालोजीला वयाच्या चव्वेचाळिसाव्या वर्षी शहाजीराजे पुत्र झाला...’ अशा रीतीने काव्यनायकाच्या कर्तबगारीची पार्श्वभूमी राजवाड्यांनी वाचकांसमोर ठेवली.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

...सिर्फ कफन बदला है!

पर्यावरणास एखाद्या कृतीने हानी पोहोचणार असेल तर त्यासाठीची पाहणी, निरीक्षण आणि त्या संदर्भातील निर्णय ती कृती केली जाण्याआधी व्हायला हवा.

एखादी कृती, प्रकल्प यांस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट पर्यावरण मंजुरी देण्याचा सरकारचा अधिकार सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या पीठाने रद्द केला. त्यानंतर अनेकांनी त्याचे स्वागत केले, संपादकीये लिहिली आणि एकूणच यामुळे आता पर्यावरण रक्षणास कशी मदत होईल, याबद्दल आनंद व्यक्त केला. पण प्रत्यक्षात वास्तव तपासू गेल्यास हा आनंद, समाधान अत्यंत अल्पजीवी ठरण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय अशी पूर्वलक्ष्यी पर्यावरण मंजुरी कशी देता येईल याचेच एक प्रकारे 'दिशादर्शन' करतो. जे झाले ते काय आणि कसे आणि त्यामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या लढ्यासमोर पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे लक्षात घेण्यासाठी या संदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम तपशिलासह लक्षात घ्यायला हवा.

त्याची सुरुवात होते १४ सप्टेंबर २००६ या दिवशीच्या निर्णयाने. त्या दिवशी सरकारने १९८६च्या पर्यावरण रक्षण कायद्यातील (एन्व्हायर्न्मेंट प्रोटेक्शन ॲक्ट १९८६) 'कलम तीन'चा आधार घेत 'पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अध्यादेश (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन) प्रसृत केला. त्यानुसार २० हजार चौ. मी.पेक्षा अधिक जागा व्यापणाऱ्या प्रकल्पांस पर्यावरण तो सुरू करण्याआधी मंजुरी घेणे अत्यावश्यक ठरले. हा मनमोहन सिंग सरकारचा काळ. त्यांच्या अखत्यारीत पर्यावरण हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात होता. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प सुरू करण्याआधी त्यास पर्यावरणीय मंजुरी अत्यावश्यक केली जाण्याचे संबंधित वर्तुळात स्वागत झाले. ते रास्त. त्यानंतर या संदर्भातील महत्त्वाची घडामोड घडली ती २०१७ सालच्या मार्च महिन्यात. म्हणजे अर्थातच नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर. त्या वर्षी १४ मार्चला पर्यावरण खात्याने एक अध्यादेश (नोटिफिकेशन) प्रसृत केला आणि ज्या प्रकल्पांनी पर्यावरण पूर्व-परवानगी घेतलेली नाही वा २० हजार चौ. मी. आकाराच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे, त्यांस सहा महिन्यांची मुदत दिली आणि त्या काळात त्यांनी अर्ज केल्यास पर्यावरण मंजुरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देण्याचा निर्णय त्याद्वारे घेतला. त्यास मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता ही सोय एकदाच (वन-टाइम) दिली जाईल, असे लेखी आश्वासन केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले. तथापि या सोयीची मुदत सहा महिन्यांनंतर आणखी ३० दिवसांनी वाढवली गेली. त्याच वर्षी आणि त्यानंतर २०२० साली 'कॉमन कॉज' आणि 'अलेंबिक फार्मास्युटिकल्स' अशा दोन प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण मंजुरी घेतली जाणे अत्यावश्यक असल्याचा आणि प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देणे पर्यावरण रक्षणासाठी 'तिरस्कार्य' (ॲनाथेमा) असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. म्हणजे पर्यावरणाची मंजुरी ही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच घेणे बंधनकारक ठरवले.

या प्रक्रियेस नवे वळण मिळाले ते ७ जुलै २०२१ या दिवशी. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने एका साध्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे (ऑफिस मेमोरंडम) पर्यावरणीय मंजुरी न घेताच सुरू करण्यात आलेल्या सर्व प्रकल्पांस हिरवा कंदील दिला. त्यावर हा निर्णय आणि आधीचा, २०१७ सालचा अध्यादेश यांस 'वनशक्ती' या पर्यावरण रक्षक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या पीठासमोर त्याची सुनावणी झाली आणि उभयतांनी एकमताने १६ मे २०२५ या दिवशी दिलेल्या निकालाद्वारे सरकारचे दोन्हीही निर्णय रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे प्रकल्प सुरू करण्याआधीच पर्यावरण मंजुरी घेण्याचा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय अबाधित राहिला. तथापि न्या. अभय ओक यांच्या निवृत्तीनंतर या निर्णयास पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावरील सुनावणीसाठी नवे

> पण हवामान-बदलाच्या चटक्यांत समस्त मानवजात होरपळून जात असताना पर्यावरण रक्षण वा संवर्धन आपल्या प्राधान्यक्रमावर अजूनही नाही, हे विदारक सत्य आहे.

सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या निर्णयाची सुनावणी अन्य दोन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर करण्याऐवजी तीन न्यायाधीशांच्या पीठाची स्थापना केली. ते स्वतः, मूळ निर्णय देणारे न्या. भुयान आणि न्या. के. व्ही. चंद्रन यांच्यासमोर या निर्णयाची फेर सुनावणी झाली. यावर १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरन्यायाधीशांच्या पीठाकडून निर्णय दिला गेला आणि प्रकल्पांस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देणे वैध ठरवले गेले. या निर्णयावर न्या. भुयान यांनी आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला. तथापि दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निर्णय अमलात आला. यातील; २०१७ च्या अध्यादेशास आव्हान देणाऱ्या 'वनशक्ती'ची याचिकेवर फेर सुनावणी घ्यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ती घेतली जाऊन गेल्या आठवड्यात २९ जुलै रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या पीठाने 'कार्यालयीन आदेशाद्वारे' पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तथापि अशी पूर्वलक्ष्यी मंजुरी द्यावयाची असेल तर पर्यावरण खात्याने 'कार्यालयीन आदेश' हा मार्ग न निवडता 'अपवादात्मक परिस्थिती' असेल तर 'पर्यावरण रक्षण कायद्यातील 'कलम तीन'चा आधार घेऊन अशी पूर्वलक्ष्यी परवानगी द्यावी,' असे स्पष्ट केले.

एका मार्गाने सरकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देऊ शकत नाही; पण ती द्यावयाची असेल तर सरकारला दुसरा, अधिक राजमान्य मार्ग त्यासाठी उपलब्ध आहे असा याचा अर्थ. म्हणजे हव्या त्या प्रकल्पास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देण्याचा सरकारचा अधिकार अबाधितच राहतो; हे यातून स्पष्ट व्हावे. पर्यावरणासाठी एखादी कृती हानीकारक असेल तर ती कृती होण्याआधी रोखणे म्हणजे पर्यावरण रक्षण. अशी कृती रोखण्याचे अधिकार आणि तशी प्रक्रिया असणे त्यासाठी महत्त्वाचे. कृती घडून गेल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरण रक्षण होऊ शकणार नाही, हे सामान्यांसही कळेल असे साधे तर्कशास्त्र. तेव्हा पर्यावरणास एखाद्या कृतीने हानी पोहोचणार असेल तर त्यासाठीची पाहणी, निरीक्षण आणि त्या संदर्भातील निर्णय ती कृती केली जाण्याआधी व्हायला हवा. पर्यावरण रक्षणासाठी पश्चात बुद्धी निरुपयोगी असते. वृक्षतोड, हरितपट्ट्याचे निवासी संकुलासाठी रूपांतर, विमानतळ वा धरण वा असे कोणतेही प्रकल्प सरकारच्या मते 'अपवादात्मक' असू शकतात. त्यांच्यामुळे पर्यावरणाची हानी कशी, किती होईल याचा अभ्यास या प्रकल्पांची कामे सुरू होण्यापूर्वीच व्हायला हवा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय पर्यावरण रक्षणाची मंजुरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कशी मिळवता/देता येईल त्याबाबत महत्त्वपूर्ण 'दिशा'दर्शन करतो. ही दिशा कोणती? त्याचे उत्तर उत्तराखंडातील अमानुष डोंगरतोड, विदर्भातील वाघांच्या मुळावर उठणारे खाण प्रकल्प, मुंबई वा अन्य किनारपट्टीत नष्ट होणाऱ्या खारफुटी आदींतून मिळू शकेल.

वास्तविक हवामान-बदलाच्या चटक्यांत समस्त मानवजात होरपळून जात असताना पर्यावरण रक्षण वा संवर्धन आपल्या प्राधान्यक्रमावर अजूनही नाही, हे विदारक सत्यच यातून समोर येते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करणारे ते कोणत्या आधारे करतात, हा प्रश्न. त्याच्या उत्तरासाठी तारकेश्वरी सिन्हा यांस उद्धृत करणे समयोचित. राजकारणात जेव्हा साहित्य/संस्कृती, काव्यशास्त्रविनोदाची जाण असणारे मुबलक होते तेव्हाचा तो काळ. त्या वेळी एका राजकारण्याच्या कार्यशैलीत लक्षणीय बदल झाला आहे किंवा काय, असा प्रश्न सिन्हा यांस विचारता त्या उत्तरल्या, ''पंछी कहते है की चमन बदला है, सितारे कहते है की गगन बदला है... मगर शमशान की खामोशी कहती है की लाश वही है... सिर्फ कफन बदला है''. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने पर्यावरणाच्या प्रेतावरील वस्त्र तितके बदलले जाईल; इतकेच.

केंद्र सरकारचे 'कोर्स-करेक्शन'

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

जंतर-मंतर असो वा देशात कुठेही; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी, तरुण-तरुणींनी सावध राहायला हवे. तुम्ही फक्त एक लढाई जिंकलेली आहे, युद्ध नव्हे याची जाणीव नसेल तर तुम्ही एका मोठ्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे, हा संदेश गेल्या आठवडाभरात वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारकडून त्यांना देण्यात आलेला आहे. सध्या केंद्र सरकार 'कोर्स करेक्शन' करत आहे. केंद्र सरकारची हार झालेली नाही, ते फक्त धक्क्यातून सावरण्यासाठी थोडा वेळ घेत आहेत. वेळ मागून घेणे ही कदाचित आंदोलन करणाऱ्या जेन-झींसाठी धोक्याची घंटा असेल. जेन-झींनी सरकारने दिलेला इशारा समजून घेतला पाहिजे. जंतर-मंतरवरील आंदोलन यशस्वी झाले, धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले गेले, याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होईल असे नव्हे. सरकार पूर्वीच्याच 'नियंत्रित' पद्धतीने काम करेल, कदाचित अधिक जोमाने. त्याची दिशा पुढील काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळू शकेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. सोमवारी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहेत. या चर्चेला शहा उत्तर देतील तेव्हा ते दुप्पट ताकदीने प्रत्युत्तर देतील. त्यांच्या लोकसभेतील भाषणाकडे सगळ्यांनी लक्ष देण्याची गरज असेल.

गेल्या आठवडाभरामध्ये केंद्र सरकार जनतेच्या रोषामुळे मागे हटल्याचे, ते दबावाखाली आल्याचे दिसले. धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार सोडावा लागला, त्यातून ही बाब स्पष्ट झाली. कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) तीन मागण्या केल्या होत्या, त्यातील ही एक पूर्ण झाली. आंदोलकांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे सरसरकट मागे घेण्याची मागणी मात्र पूर्ण झालेली नाही. त्यामध्ये अटी-शर्ती सरकारने लागू केल्या आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण, या भूमिकेआड राहून गुन्हे मागे न घेण्याचे कारण सरकारला मिळाले आहे, ही बाबही दुर्लक्षित करता येत नाही. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटीची नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही पूर्ण झालेली नाही. त्याबाबत सरकारकडून तडजोड केली जाण्याची शक्यता असल्याचे दिसते. ही झाली जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने टाकलेली पावले आणि हा झाला सरकारचा मवाळ, 'हॅलो फ्रेण्ड्सवाला' चेहरा! केंद्र सरकारने घातलेला हा मुखवटा काढून टाकला तर वेगळे चित्र दिसू शकेल. हे चित्र आंदोलकांना दिसले तर त्यांना सावध होता येईल. गेल्या दोन-चार दिवसांपासून सरकारने ढाल घेऊन स्वतःचा बचाव केला इतकेच नव्हे, तर तलवारीने वारही करायला सुरुवात केली. केंद्र सरकार

> जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली असली तरी हा आंदोलकांचा विजय समजणे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. कारण सरकारने सध्या बचावात्मक पवित्रा घेतला असला, तरी ती सरकारची तेवढ्या काळापुरती रणनीती असू शकते. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांची खरी परीक्षा आता सुरू होणार आहे.

जाणीवपूर्वक वार करायचे ठरवते तेव्हा तो चुकवता येणे जवळपास अशक्य असते. त्याची चुणूक फरीदाबादमधील १५ वर्षांच्या तरुणीने अनुभवली आहे! या तरुणीला चहुबाजूने घेरले गेले आहे, ती पूर्ण असहाय आहे, तिला सत्ताधाऱ्यांसमोर गुडघे टेकवण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय उरलेला नाही. ही परिस्थिती हळूहळू इतरांचीही होऊ शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

जंतर-मंतरवरील आंदोलकांनी केंद्र सरकारला जेरीला आणले होते. या विद्यार्थ्यांनी सरकारची कोंडी केली होती. जवळपास दोन आठवडे केंद्र सरकारला या कोंडीतून बाहेर कसे पडायचे हे कळत नव्हते. म्हणून तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी एकप्रकारे दडी मारली होती असा आरोप होऊ लागला. शहा संसदेत येत होते मात्र, सभागृहात आले नाहीत. ते बैठका घेत होते पण, जाहीर विधाने करत नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या मोर्चामध्ये लाठीमार झाला, पॅलेट गनचा वापर झाला, विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली गेली. या सगळ्या क्रौर्याबद्दल शहांनी चकार शब्द काढला नाही. काँग्रेसने शहांच्या राजीनाम्याची मागणी करून केंद्र सरकारवर कधी नव्हे इतका दबाव वाढवला. शहांवर हल्लाबोल होत असेल तर सरकारमधील इतर मंत्री, भाजपचे नेत्यांची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पना करता येऊ शकते. कोणीच काही बोलत नाही, अशी भाजपची स्थिती फार कमी वेळा पाहायला मिळते. केंद्र सरकार गलितगात्र झाले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वतःच या लढाईमध्ये उतरावे लागल्याचे दिसले. मोदींनीच केंद्र सरकारसाठी मैदानात उतरून किल्ला लढवला. एका बाजूला इन्स्टाग्राम वगैरेवरून 'तहा'ची बोलणी केल्यासारखे दाखवले. त्यातून एकप्रकारे मोदींनी सरकारच्या वतीने लढण्यासाठी वेळ मागून घेतला असे म्हणता येईल. आपल्यावर झालेला हल्ला परतवून लावण्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागणार होती, त्यासाठी सरकारला थोडी उसंत हवी होती, ती मोदी 'इन्स्टा'वरून मिळवत आहेत असे दिसले. एका बाजूला तरुणांशी, जेन-झींशी सरकार संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दाखवले जात आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला आंदोलकांना घेरले जात आहे. जंतर-मंतरवर पुन्हा येऊन मोर्चा काढण्याची आणि आंदोलन करण्याची हिंमत कोणी जेन-झीने करू नये याची रणनीती आखली गेल्याचे दिसले. या रणनीतीनुसार अंमलही केला जाऊ लागला आहे. मोर्चामध्ये जखमी झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबातील सदस्यांची विशेषतः जेन-झी मुला-मुलींची पत्रकार परिषद घेतली गेली. सत्ताधाऱ्यांकडून हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची ही सुरुवात म्हणता येऊ शकते. या प्रत्युत्तराची तीव्रता हळूहळू वाढतही जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारविरोधातील लढाईचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याचे संकेतही सरकारी 'कारवायां'मधून मिळू लागले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'इन्स्टा'वरून तीन वेळा जेन-झींशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यातून खरोखरच संवाद साधला गेला असेल याबद्दल शंका घेता येऊ शकते. जेन-झींच्या भाषेवरून मोदींनी या तरुण-तरुणींना माफ केले आहे. वास्तविक, जेन-झींनी मोदींची माफी मागितली नव्हती, जंतर-मंतरवरील आंदोलन हा त्यांनी केलेला अपराध आहे, असे ते मुळात मानत नाहीत. त्यांना शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्या होत्या, त्यांना धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हवा होता, त्यासाठी त्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन केले. त्यासाठी त्यांनी माफी मागितलेली नाही. मोदींविरोधात वापरलेल्या भाषेबद्दलही त्यांनी माफी मागितलेली नाही. आपण चूक केली असे त्यांना वाटत नसेल, तर त्यांनी माफी कशासाठी मागावी आणि मोदींनी तरी त्यांना माफ केले, असे म्हणत उदार कशासाठी व्हायचे, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आपण तरुणांना माफ केले आहे, या मोदींच्या वक्तव्याबद्दल कॉक्रोच जनता पार्टीने त्यांना चपराक दिली आहे. तुम्हाला माफ करतो, ही मोदींची भाषा अत्यंत उद्दाम वाटू शकते. त्यातून केंद्र सरकारच्या मनात काय चालले आहे याची कल्पना येऊ शकते.

आता राहिला मुद्दा केंद्र सरकारमधील अंतर्गत संघर्षाचा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात काँग्रेसचे नेते संसदेमध्ये व संसदेच्या बाहेर आक्रमक झाले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी थेट शहांना लक्ष्य करतील असे सरकारला वाटले नसावे. अचानकपणे शहांना घेरण्याचा काँग्रेसचा डाव यशस्वी झाला हे खरे. आत्तापर्यंत शहांना आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभे करण्याची कोणीही हिंमत केलेली नव्हती. त्यामुळे सरकारमध्ये आणि भाजपमध्येही सत्ता खऱ्या अर्थाने शहांकडे होती. त्यांना आव्हान देण्याचे धाडस कोणामध्ये नव्हते. मोर्चातील पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांनंतर त्याची जबाबदारी थेट शहांवर येऊन पडली. केंद्रात सत्ता आल्यापासून राजकारणातील ही शहांची पहिली चूक म्हणता येईल. टीका करण्यासाठी शहांना नेहरू, इंदिरा गांधी वगैरे सगळे उपलब्ध होते. यावेळी नेहरू वा बाकी काँग्रेसवाले बचावासाठी उपयोगी पडले नाहीत. शहांना ही ढालही वापरता आली नाही. शहांवर स्वतःच स्वतःचा बचाव करण्याची वेळ येऊन ठेपली. अशा वेळी शहांनी विरोधकांना सामोरे न जाण्याचे ठरवले. मोदींनी 'इन्स्टा'वरून संदेश प्रसारित करून शहांसाठी ढाल बनण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल.

पण, येत्या आठवड्यापासून सरकार आपला बचावात्मक पवित्रा बाजूला टाकून देईल असे दिसते. संसदेच्या बाहेर सरकार जेन-झींविरोधात आक्रमक झाले आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमधून जेन-झींविरोधात हल्लाबोल केला जात आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांना जाब विचारला जात आहे. 'सीआरपीएफ'च्या अधिकाऱ्यांनी मोर्चातील कारवाईच्या समर्थनार्थ जाहीर विधाने केली आहेत. सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा संदेश पोलीस व निमलष्करी यंत्रणांपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. संसदेमध्येही सरकार हीच रणनीती वापरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या सभागृहांमध्ये येतील की नाही, हे माहीत नाही. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. सभागृहात ते विधेयकांवर बोलतील. त्यातून विरोधी पक्षांनाच नव्हे तर, जंतर-मंतरवरील आंदोलक, कॉक्रोच जनता पक्षाचे नेते, त्यांचे सहानुभूतीदार, डाव्या चळवळीतील नेते, विचारवंत या सगळ्यांविरोधात मोर्चा उघडतील असे दिसते. तसे शहांनी केले नाही तर त्यांची सरकारमधील आणि भाजपमधील जरब संपण्याचा धोका असेल. मोदी-शहांसारखे नेते राजकारणावरील, सत्तेवरील पकड कधीही सैल होऊ देत नाहीत. त्याचा प्रत्यय या आठवड्यामध्ये संसदेमध्ये येऊ शकेल.

अन्वयार्थ

कोसळत्या व्यवस्थेतील कोसळत्या इमारती...

मुंबईजवळच्या भिवंडीत एक बेकायदा व धोकादायक इमारत कोसळून दहा जणांचा मृत्यू झाला. याआधी मुंबईत मानखुर्दमध्येही अशीच दुर्घटना घडली होती. पावसाळा सुरू झाला की अशा बेकायदा तसेच अधिकृत धोकादायक इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतात. त्यात अनेकांचे जीव जातात. सरकार व प्रशासन अशा इमारतीत राहू नका असे आधीच सांगितल्याचा दावा करून जबाबदारी झटकते. माध्यमांमध्ये त्याची थोडा काळ चर्चा होते. पुढे काय, याच प्रश्नात या समस्येचे मूळ दडले आहे. हा प्रश्न केवळ मुंबई, ठाण्यापुरता मर्यादित नाही. मध्यंतरी नागपुरात वर्दळीच्या पंचशील चौकात धोकादायक इमारत कोसळून रस्त्यावरून जाणाऱ्या एकाचा मृत्यू झाला. अन्य शहरांतही अशा घटना घडत असतात. अशा इमारतींमधून आता रहिवाशांना सक्तीने बाहेर काढले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. कायद्यानुसार हे वक्तव्य योग्यच, पण हे बाहेर पडलेले लोक जाणार कुठे? राहणार कुठे? त्यांच्यासाठी सरकारजवळ काही ठोस कार्यक्रम आहे का?

मध्यंतरी सरकारने अशा बेकायदा व अधिकृत धोकादायक इमारतींसाठी समूह पुनर्विकासाची योजना आणली. प्रामुख्याने ठाणे परिसरात काही कामेही सुरू झाली. पण अशा कोणत्याही योजनेत सरकारी पातळीवर केवळ बिल्डरचे हित जोपासले जाते. त्याला जास्त मोठा भूखंड कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जातात. यात रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्यक्रम नसतोच. अशा योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेचे ध्येय बिल्डरचे भले हेच असेल तर योजनेतून फायद्याची आशा लावून बसलेल्या लाखो रहिवाशांचे काय? मोठ्या महानगरांमध्ये म्हाडा व सिडकोकडून परवडणारी घरे बांधून देण्याचा दावा सरकारकडून सतत केला जातो. तो किती खोटा हे गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने दाखवून दिले. अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी ७५ लाखांचे घर विक्रीसाठी कसे काय ठेवले जाऊ शकते हा न्यायालयाचा प्रश्न होता व सरकारला त्याचे उत्तर देता आले नाही. वर्षाला सात ते दहा लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्या मध्यम वर्गाला ही घरे परवडणार तरी कशी? मग हेच लोक नाईलाजाने बेकायदा इमारतींच्या आश्रयाला जातात. तिथे २५ ते ३० लाखांत मिळणारी घरे त्यांना सोयीची वाटतात. अशा इमारतींचे बांधकाम तकलादू असते. दहा-पंधरा वर्षांतच अशा इमारती धोकादायक श्रेणीत जातात. भिवंडीत हेच घडले. हे वास्तव सरकारच्या कधी लक्षात येणार?

मध्यंतरी उच्च न्यायालयाला ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा इमारतींची पाहणी करण्यासाठी सत्र न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमावी लागली. समितीने अहवाल दिला. त्याचे पुढे काय झाले? अशा बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बाहेर काढायचेच असे सरकारने ठरवले तर राज्यभरातून लाखो लोक रस्त्यावर येतील. सक्तीची भाषा करणाऱ्या सरकारला हे ठाऊक नसेल का? असे काही घडले तर जो काही आगडोंब उसळेल तो कोणत्याच सरकारला नको असतो. त्यामुळे अशी दुर्घटना घडली की सक्तीची भाषा करायची व नंतर त्या समस्येकडेच पूर्णपणे पाठ फिरवायची हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण राहिले आहे. याचा फटका सामान्यांना बसतो. त्यांचे जीव जातात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. मतांच्या राजकारणाला प्राधान्य देणे हेच सत्ताधाऱ्यांचे धोरण असते. झोपडपट्ट्यांना अधिकृत करणे, पुनर्विकासाचे कार्यक्रम आखणे याकडे केवळ मतांच्या दृष्टिकोनातून बघितले जाते. सर्व घटकांचा लाभ हे सूत्र मागे पडते ते त्यामुळेच. परिणामी योजना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी नीट होत नाही. समस्या कायम राहते.

प्रत्येक शहरात हेच घडते. भिवंडी हे त्यातले केवळ एक उदाहरण. किमान घरांच्या बाबतीत तरी सरकारचे धोरण अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांचा विचार करणारे असायला हवे. नेमकी त्याचीच आखणी होताना दिसत नाही. सरकारनेच पाठ फिरवल्याने पर्याय नसलेले लोक बेकायदा गोष्टींकडे वळतात. साध्या निवाऱ्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. हे लोक दुर्घटनेला सामोरे जातात ते या अगतिकतेतून. हे सत्य स्वीकारण्याची तयारी सरकार कधी दाखवत नाही. दुर्घटना घडली की त्याला जबाबदार कोण हे निश्चित करून गुन्हे दाखल करायचे, मृतांना मदत द्यायची व वास्तवाकडे पाठ करून पुढे वाटचाल करायची हाच दृष्टिकोन सत्ताधाऱ्यांनी अंगीकारला आहे. परिणामी इमारती पडत राहणार, माणसे मरत राहणार व त्यांच्या अधिकृत घरांच्या स्वप्नांचा असाच चुराडा होत राहणार.

पदोन्नतीला चालना की, स्पर्धा परीक्षार्थींच्या संधींवर गदा?

विश्लेषण

देवेश गोंडाणे
devesh.gondane@expressindia.com

> महसूल विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे संबंधित उमेदवारांच्या संधी कमी होणार का, तसेच आरक्षणाच्या प्रतिनिधित्वावर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

उपजिल्हाधिकारी पदांवरील थेट भरतीला कात्री?

महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम करण्यात आल्यानंतर आता सेवाप्रवेशाच्या नियमातही सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे थेट भरती करण्यात येणाऱ्या आणि पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या प्रमाणात बदल झाला आहे. याचा फटका परीक्षेद्वारे थेट भरण्यात येणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांवर होणार आहे. नव्या नियमात थेट भरतीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांना कात्री लावण्यात आली आहे. तर पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. याचा फायदा तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत होईल. तर नायब तहसीलदारांचे तहसीलदार पदावर पदोन्नतीचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत कमी करण्यात आले. महसूल विभागाच्या जुन्या सेवाप्रवेश नियमानुसार मंजूर आकृतिबंधातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदे हे थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत तर ५० टक्के पदे ही पदोन्नतीने भरली जात होती. परंतु आता ६० टक्के पदे पदोन्नतीने तर ४० टक्के पदे थेट भरण्यात येतील. उपजिल्हाधिकाऱ्यांची थेट भरण्यात येणारी पदे १० टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याने भरती प्रक्रियेला कात्री लागली आहे.

स्पर्धा परीक्षार्थ्यांना सुधारणांचा फायदा होणार का?

नव्या सेवाभरती नियमांचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांवर होणार आहे. पूर्वीच्या सेवा भरती नियमानुसार तहसीलदारांची ३३ टक्के पदे थेट परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येत होती. आता ती ४० टक्के करण्यात आली. तर पदोन्नतीने ६० टक्के पदे भरण्यात येतील. पूर्वी पदोन्नती आणि थेट भरतीचे प्रमाण ६७:३३ टक्के होते. त्यामुळे थेट तहसीलदार पदावर भरतीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर नायब तहसीलदारांना तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्याचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. मंडळ अधिकारी व सहायक महसूल अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदार पदावर देण्यात येणाऱ्या पदोन्नतीच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी पदोन्नती व थेट भरतीचे प्रमाणे ६७:३३ टक्के होते. ते आता ८०:२० करण्यात आले आहे. त्यामुळे तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदासाठी स्पर्धा परीक्षार्थींना संधी मिळणार आहे.

बदल करण्यामागची सरकारची भूमिका काय?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मते, महसूल विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडली होती. वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे मार्ग मोकळे करण्यासाठी आणि नव्या आकृतिबंधाशी सेवाभरतीचे नियम सुसंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच मंडळ अधिकारी आणि सहायक महसूल अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नतीचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने या संवर्गालाही फायदा होणार आहे. सरकारचा दावा प्रशासकीय सुधारणा आणि पदोन्नतीतील अडथळे दूर करण्याचा असला, तरी थेट भरती कमी केल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये नाराजी होण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा पदोन्नतीवर अधिक भर आहे का?

महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध येण्यापूर्वी राज्य सरकारने ५ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पात्रता निकष आणि अनुभवाच्या अटी लक्षात घेऊन सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित पदे थेट मुलाखतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असले, तरी थेट मुलाखतींऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला. या निर्णयामुळे विभागीय भरतीतील आरक्षणाला धक्का बसणार असल्याची भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

आरक्षणाच्या संधी कमी होतील का?

यापूर्वी अनेक पदांपैकी ५० टक्के पदे सरळ सेवा भरतीद्वारे, तर उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जात होती. सरळ सेवा भरतीमध्ये आरक्षणाचा नियम लागू होत होता. मात्र, ५ मेच्या शासन निर्णयानुसार, नव्या नियमांनुसार सहसंचालक, संचालक अधीक्षक, कारागृह उद्योग, सहायक सरकारी अभियोक्ता, विद्युत शुल्क निरीक्षक, वन सांख्यिकी अधिकारी आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी यांसारखी पदे पदोन्नतीद्वारे भरली जाणार आहेत. अशा पदांसाठी आरक्षण लागू नसल्याने या पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाच्या संधी कमी होतील, असा आक्षेप घेतला जात आहे.

चिंतन

नशामुक्त युवा विकसित भारत की मजबूत नींव

नशा किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करने वाला अभिशाप भर नहीं है, यह समाज और राष्ट्र की ताकत को भीतर से कमजोर करने वाला गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत करते हुए ड्रग्स की सप्लाई को दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा बताया है। उनका यह बयान नशे की समस्या को केवल स्वास्थ्य या कानून-व्यवस्था के सवाल से आगे ले जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ता है। यदि किसी देश के युवाओं को सुनियोजित तरीके से नशे की गिरफ्त में धकेलने की कोशिश होती है तो उसका मुकाबला भी उतनी ही गंभीरता और रणनीति के साथ करना होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना केवल आर्थिक विकास, आधुनिक तकनीक और मजबूत बुनियादी ढांचे से पूरा नहीं होगा। इसकी सबसे मजबूत नींव देश का स्वस्थ, शिक्षित, सक्षम और नशामुक्त युवा होगा। नशा युवाओं के सपनों पर सबसे पहले हमला करता है। जिस उम्र में युवा शिक्षा हासिल कर सकता है, हुनर विकसित कर सकता है, खेल में आगे बढ़ सकता है या अपना कारोबार शुरू कर सकता है, उसी उम्र में नशे की गिरफ्त उसका भविष्य रोक सकती है। नशा कुछ समय के लिए मानसिक उत्तेजना या राहत का भ्रम दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत स्वास्थ्य, पैसा, रिश्तों और करियर से चुकानी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने ड्रग्स की सप्लाई को दुश्मन देशों की आतंकी साजिश से जोड़ते हुए जिस खतरे की ओर संकेत किया है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। यदि नशीले पदार्थों की तस्करी के पीछे संगठित अपराध और देशविरोधी नेटवर्क सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई केवल कानून-व्यवस्था का अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई भी है। ड्रग्स के उत्पादन, तस्करी और वितरण से जुड़े पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। सीमाओं से लेकर शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी सप्लाई चेन पर लगातार और प्रभावी निगरानी जरूरी है। हालांकि केवल तस्करों पर कार्रवाई से नशे की समस्या खत्म नहीं होगी। जितनी जरूरी सप्लाई रोकना है, उतना ही जरूरी नशे की मांग को कम करना भी है। इसके लिए परिवारों, स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में केवल भाषण देने से बात नहीं बनेगी। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के ठोस अवसर देने होंगे। खेल के मैदान, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप, कला, संगीत और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दे सकती हैं। इसी दृष्टि से अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार नशामुक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की पहल को जनभागीदारी से जोड़ना जरूरी है। किसी अभियान की सफलता केवल शपथ लेने या कार्यक्रम आयोजित करने से नहीं मापी जा सकती। असली सफलता तब होगी, जब नशे की उपलब्धता घटे, युवाओं में जागरूकता बढ़े और नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को समय पर उपचार और पुनर्वास मिले। नशामुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा, जब सरकार की सख्ती और समाज की संवेदनशीलता साथ चलें। तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, खेल, रोजगार और स्वस्थ मनोरंजन के रास्ते भी खुलें। परिवार बच्चों से संवाद बढ़ाएं और शिक्षण संस्थान केवल परीक्षा परिणाम नहीं, विद्यार्थियों के मानसिक और सामाजिक विकास पर भी ध्यान दें। नशामुक्त युवा ही स्वस्थ समाज की ताकत और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव हैं।

राष्ट्रमंडल खेल

महेन्द्र तिवारी

भारतीय बॉक्सिंग में सुनहरा अध्याय

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने ठीक ऐसा ही एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। जब रिंग में भारत के मुक्केबाज उतर रहे थे तो उनके चेहरों पर एक अलग ही आत्मविश्वास और आंखों में जीत की अचूक चमक थी। यह चमक केवल एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सालों का पसीना, अनगिनत संघर्ष और वैश्विक पटल पर खुद को साबित करने की अदम्य इच्छाशक्ति छिपी थी। भारतीय दल ने इस बार बॉक्सिंग इवेंट के दस फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लिया और सभी दस में पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि भारतीय मुक्केबाजी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। सात स्वर्ण और तीन रजत पदक जीतना कोई सामान्य बात नहीं है।

खेलों की दुनिया में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाते हैं। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने ठीक ऐसा ही एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। जब रिंग में भारत के मुक्केबाज उतर रहे थे तो उनके चेहरों पर एक अलग ही आत्मविश्वास और आंखों में जीत की अचूक चमक थी। यह चमक केवल एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सालों का पसीना, अनगिनत संघर्ष और वैश्विक पटल पर खुद को साबित करने की अदम्य इच्छाशक्ति छिपी थी।

भारतीय दल ने इस बार बॉक्सिंग इवेंट के दस फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लिया और सभी दस में पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि भारतीय मुक्केबाजी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। सात स्वर्ण और तीन रजत पदक जीतना कोई सामान्य बात नहीं है। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन मुक्केबाजी प्रदर्शन है जिसने देश का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता को केवल पदकों की संख्या से नहीं आंका जा सकता है। इसके पीछे भारत के छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से निकलकर आई उन प्रतिभाओं की कहानी है जिन्होंने तमाम अभावों के बावजूद अपने सपनों को मरने नहीं दिया। जब हम मुक्केबाजी की बात करते हैं तो हरियाणा के भिवानी और रोहतक जैसे शहरों का जिक्र आना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार पदक विजेताओं की सूची इस बात की गवाही देती है कि अब खेल का यह जुनून पूरे देश में फैल चुका है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की दूरदर्शी नीतियां, सरकार का निरंतर समर्थन और प्रशिक्षकों की दिन-रात की मेहनत ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां अब केवल हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खिलाड़ी रिंग में उतरते हैं। इस बार का प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय मुक्केबाज अब तकनीकी और शारीरिक दोनों ही मोर्चों पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को धूल चटाने का माद्दा रखते हैं। इस अभूतपूर्व सफलता में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात भारतीय महिला मुक्केबाजों का दबदबा रहा है।

महिला वर्ग में भारत ने पांच अलग-अलग भार वर्गों में सीधे स्वर्ण पदक अपने नाम किए जो महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। 51 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घणघस और 70 किलोग्राम भार वर्ग में अरुंधति चौधरी ने जिस आक्रामकता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया उसने पूरी दुनिया के खेल पंडितों को चकित कर दिया। इन महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि भारतीय बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उनके घूंसे केवल विरोधी खिलाड़ियों पर ही नहीं पड़े, बल्कि समाज की उस रूढ़िवादी सोच पर भी पड़े हैं जो लड़कियों को चारदीवारी में सीमित रखना चाहती है। रिंग के अंदर उनकी फुर्ती, सटीक फुटवर्क और सही समय पर पंच मारने की कला ने उन्हें अजेय बना दिया। यह जीत भारत की हर उस युवा लड़की के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने लिए एक बड़ा सपना देखने की हिम्मत जुटा रही है। पुरुष वर्ग में भी भारतीय

मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से पदकों की झड़ी लगा दी। साठ किलोग्राम भार वर्ग में सचिन सिवाच और अस्सी किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीतकर यह संदेश दिया कि भारतीय पुरुष मुक्केबाजी का भविष्य अत्यंत सुरक्षित और उज्ज्वल है। इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने रिंग में जिस संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया, वह देखने लायक था। उन्होंने अपने विरोधियों को कोई मौका नहीं दिया और अपनी अचूक रणनीतियों से मुकाबलों को एकतरफा बना दिया। इसके अलावा, 55 किलोग्राम में जदुमणि सिंह और नब्बे प्लस किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल ने भी रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। यह रजत पदक भी सोने से कम नहीं हैं क्योंकि उन्होंने फाइनल तक के सफर में दुनिया के कई दिग्गज मुक्केबाजों को मात दी थी। उनका यह प्रदर्शन आने वाले विश्व कप और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी इस दल की एक बड़ी ताकत रहा। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर अपनी निरंतरता साबित की। खेल में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार फाइनल मुकाबले बहुत ही करीबी अंतर से छूट जाते हैं, लेकिन लवलीना का पोडियम तक पहुंचना यह बताता है कि उनके अंदर अभी भी खेल के प्रति वही पुरानी आग बाकी है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में उन्होंने पूरे दल का मार्गदर्शन किया और उनका यह अनुभव भविष्य की प्रतियोगिताओं में भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इस जीत के पीछे के विज्ञान और तकनीकी पहलुओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आज के दौर में मुक्केबाजी केवल ताकत का खेल नहीं रह गया है। यह दिमाग, तकनीक, स्पोर्ट्स साइंस और वीडियो एनालिटिक्स का एक जटिल मिश्रण बन चुका है। भारतीय मुक्केबाजों की इस सफलता के पीछे उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ का एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हर विरोधी खिलाड़ी की कमजोरियों का बारीकी से अध्ययन किया और उसी के अनुसार रणनीतियां बनाईं। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर उनकी मानसिक सेहत तक हर छोटी-छोटी बात का ख्याल रखा गया। हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है, उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने की जो मुहिम शुरू की गई थी, वह अब वटवृक्ष का रूप ले रही है। जब किसी एथलीट को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है और यही आत्मविश्वास हमें ग्लासगो के बॉक्सिंग अरीना में देखने को मिला। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी के इस स्वर्णिम प्रदर्शन ने भारत की समग्र पदक तालिका में भी एक बड़ा उछाल ला दिया है।

इसके कारण भारत अंक तालिका में शीर्ष देशों की कतार में मजबूती से खड़ा हो गया है। एक समय था जब भारत केवल शूटिंग या कुश्ती जैसे कुछ गिने-चुने खेलों पर ही पदकों के लिए निर्भर रहता था, लेकिन अब मुक्केबाजी ने भी खुद को एक प्रमुख खेल के रूप में स्थापित कर लिया है। यह बदलाव रातोंरात नहीं आया है। वर्ष दो हजार अठारह के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने तीन स्वर्ण सहित कुल सात पदक जीते थे, जो उस समय तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लेकिन अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दस पदक और उनमें भी सात स्वर्ण जीतना एक बहुत बड़ी छलांग है। भारतीय मुक्केबाजी का यह स्वर्णिम युग अभी बस शुरू ही हुआ है और आने वाले समय में यह खेल दुनिया भर में भारत का नाम और भी रोशन करेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

विचार

पंकज झा

गांधीवादियों द्वारा गांधी का अवमूल्यन

नीट पेपर लीक से संबंधित विवाद और कथित जेनजी के आंदोलन को अनेक अलग-अलग एंगल से देखा जा सकता है। बौद्धिक वर्ग अन्य तमाम आंदोलनों की तरह ही इसे भी अपनी-अपनी समझ अनुसार व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम व्याख्याओं में तथ्यों का सम्यक विश्लेषण कम, अपने-अपने पक्ष का पोषण अधिक दिखता है। यहां तक भी ठीक कहा जा सकता है क्योंकि नीर-क्षीर मूल्यांकन का युग अब बीत चुका। तटस्थता अब पूरी तरह से समय का अपराध जैसा हो गया है। निष्पक्षता का अब कोई पक्ष शेष शेष नहीं। अब तो बस आप इधर हैं या उधर। आप पक्ष में होते हैं या विरुद्ध। युग के इस चलन को अब 'न्यू नार्मल' माना जा रहा है। यह भी शायद ठीक हो, किंतु गलत यह हुआ है कि 'गांधीवाद' को भी अब इसका अपवाद नहीं रहने दिया गया। जिस तरह वर्तमान जंतर-मंतर प्रकरण में गंदी-गंदी गालियों का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया गया, वैसी सभी गालियों को जिस तरह ऐसे-ऐसे लोगों ने भी एंडोर्स किया, जिन्होंने स्वयं को गांधीवादी के रूप में स्थापित किया हुआ है, वह सबसे अधिक क्षोभ पैदा करने वाला है। ऐसे तत्वों ने गांधी विचार को इतना अधिक कमजोर कर दिया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में मुश्किल है। कुमार प्रशांत ने कथित जेनजी को संबोधित एक पत्रनुमा लेख में लिखा - 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक आदमी का इस्तीफा नहीं है, सत्ता के अहंकार को टूटने की गूंज है। वह टूटा यह अच्छा हुआ। लेकिन तुम याद रखना कि चोट खाया सांप ज्यादा खतरनाक होता है। राष्ट्र जब भीड़ में बदल दिया जाता है, तब वह हत्यारा हो उठता है, जिसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है।' क्या किसी कथित गांधीवादी से इस तरह की भाषा की अपेक्षा की जा सकती है? सीधे तौर पर उस सरकार या प्रधानमंत्री के लिए 'सांप' जैसे शब्द का उपयोग किया जा रहा है, जिन्होंने अधिकतम संयम का परिचय देते हुए न केवल पूरी शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए, आवश्यक नहीं होते भी अपने मंत्री का इस्तीफा लिया बल्कि स्वयं को और अपनी दिवंगत माता को मिल रही भद्दी-भद्दी गालियों को भी क्षमा कर दिया।

सवाल यहां केवल कुमार प्रशांत का ही नहीं है। तमाम ऐसे लोग जो स्वयंभू गांधीवादी कहे जाते हैं, उन्होंने इस दौरान गांधीवाद की ऐसी-ऐसी व्याख्या कर दी, कि आज अगर गांधी होते तो शर्म से डूब जाते। सवाल यहां एक पेपर लीक का था, जिसे रद्द कर नया परीक्षा भी हो गया, परिणाम भी आ गया, छात्रों ने प्रवेश भी ले लिए, किंतु इस बहाने जिस तरह बड़े कहे जाने वाले लोगों ने अपनी कुंठा का प्रदर्शन किया है, वह तकलीफदेह है। नीट पेपर लीक की खबर आयी। सरकार ने उसका संज्ञान लिया। परीक्षाएं रद्द हुईं। अपराधियों पर कारवाई हुई। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के टिप्पणी से उत्पन्न बवाल से पैदा हुए एक मजाकिया पेज वायरल कर दिया गया। मीडिया की पढ़ाई करने अमेरिका जा कर वहीं नौकरी तलाश रहे एक बेरोजगार युवक ने इसे एक मौके के रूप में देखा, उसे एक मुद्दे के तलाश थी, जो नीट पर जा कर पूरी हुई। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, उपद्रवियों के भीड़ का संसद तक जाने की कोशिश। उपद्रवियों को रोका जाना। वांगचुक के भूख हड़ताल की समाप्ति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। शिक्षा सुधार पर नए कानून को संसद की स्वीकृति। इस तमाम घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उन्हें इस तरह लांछित किया जाय? फेस रिकग्निशन समेत तमाम तरह के उपकरण इस बात की गवाही देते हैं कि भद्दी-भद्दी गालियां देने वाले न तो छात्र थे और न ही कथित जेनजी।

छात्रों के जीवन को कभी आंकड़ों से नहीं तौला जाना चाहिए। किंतु सामाजिक अध्ययन आप बिना आंकड़े के कर भी नही सकते। अभी बार-बार नीट लीक के कारण कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या की बात को विषय बनाया जा रहा है। निस्संदेह दुखद है किसी एक भी छात्र-छात्रा का इस तरह जाना, लेकिन क्या यह संभव है कि नीट की परीक्षा दुबारा आयोजित होने के कारण कोई छात्र जान दे दे? जिस परीक्षा में लगभग 95प्रतिशत छात्र को विफल ही होना हो, वे डॉक्टर नहीं बन सकते, जहां इस मंशा से ही छात्र आते हों कि उन्हें अनेक अटेम्प्ट देने होंगे, वे माह भर बाद दुबारा होने वाले परीक्षा से पहले आत्महत्या कर लेंगे? ऐसी आत्महत्याओं के अलग समाजशात्रीय कारण होते हैं, विशेषकर अभिभावकों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाने की चिंता इसका सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसी दुखद घटनाओं को समाजशास्त्रीय-मणिवैज्ञानिक नजरिये से देखने, इसका अध्ययन किए जाने के आवश्यकता है। किंतु आज इस पेपर लीक को ऐसा आक्रोश का कारण बना देना और इस बहाने समाज में हर तरह का विभेद पैदा करना, गांधीवाद के नाम पर हिंसक आचरण और भाषा का समर्थन करना अजीब है। जहां इस प्रकरण में अप्रत्याशित रूप से शासन ने मूल गांधीवाद को अपने आचरण में जीया है, बार-बार पूर्ण बहुमत से चुना जाना, अधिकांश राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें समेत तमाम प्रकार की शक्तियां होने, फिर भी लगातार संदिग्ध तत्वों द्वारा उकसाए जाने के बावजूद जैसे संयम, अहिंसा, शालीनता और बड़े हृदय का परिचयसरकार ने दिया है, निःसंदेह आज गांधी होते तो इस पर प्रसन्न होते। इसके उलट पेशेवर गांधीवादियों ने जितना निराश किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों और कृत्यों से हिंसा को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, वह शर्मनाक है। सवाल केवल किसी एक कुमार प्रशांत का नहीं है। ऐसे तमाम लोग जिनका दाना-पानी आज भी 'गांधी' हैं, उन सबने अपने कृत्यों से गांधी को कलंकित किया है। आज गांधी होते तो यही प्रार्थना करते ईश्वर से कि उन्हें ऐसे कथित गांधीवादियों से मुक्ति दे दें। शायद वे इनके विरुद्ध अनशन पर ही बैठ जाते। जंतर-मंतर के हालिया प्रकरण के अनेक निहितार्थ होंगे, किंतु गांधीवाद का इस तरह अवमूल्यन अन्य सभी परिणामों से अधिक भयंकर है। भारत अपने इस पहचान को इस ताड़ खो कर तो सचमुच विपन्न हो जाएगा। गांधीवादियों ने समाज को वास्तव में बेतरह निराश किया है। इनको सन्मति दे भगवान।

आध्यात्मिक चेतना आखिर क्या है?

संकलित

दर्शन

आज मनुष्य अत्यधिक भौतिकवादी तथा लालची हो गया है। बलिदान, त्याग, संतोष, प्रज्ञा, चिंतन-मनन, मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक मूल्यों के द्योतक रहे हैं। व्यापक उपभोगवादी संस्कृति तथा भोग-विलास से पोषित भौतिकवाद की नई उभरी संस्कृति ने आध्यात्मिक चेतना पर पर्दा डाल दिया है। धन-अर्जन, सत्ता तथा प्रसिद्धि की लालसा और सुखवादी जीवन-प्रणाली आज जीवन का परम लक्ष्य है। सभी धर्मों ने लालच को महापाप कहा है, परंतु आज लालच ही मुख्य प्रेरणा-द्वार है। ऋषि-मुनि आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देते हैं। हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों का अनुक्रम है-धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। अर्थ तथा काम संसारिक मूल्य हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य हैं, परंतु धर्म का स्थान सर्वदा प्रथम है। यह अर्थ तथा काम दोनों का प्रेरक तथा नियंत्रक है। जीवन के हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, सात्विक सर्वाधिक ऊंचा आदर्श है। इसके बाद राजसी का स्थान है, जो एक आदर्श नहीं, परंतु सामाजिक आवश्यकता है। तामसिक सबसे अधिक अपमानजनक वृत्ति है, जिससे सभी बुद्धिमान दूर रहते हैं। मनु की पद्धति में सतत्व को न्याय की संज्ञा दी गई है, राजस को आकांक्षा की तथा तमस को इच्छाओं की। महापुरुषों ने चिंतन-मनन को मनुष्य के परम आनंद के रूप में देखा। आंतरिक शांति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित जीवन ही मानव गतिविधियों का सवरेत्तम रूप है।

कोयल- अपनी वाणी को मधुर बना लेना

संकलित

प्रेरणा

एक बार वसंत ऋतु में एक कोयल वृक्ष पर बैठी कूक रही थी। आते-जाते लोग उसकी कूक को सुनते और उसकी सुरीली आवाज का आनंद लेते हुए उसकी तारीफ के पुल बांधते। कुछ देर बाद कोयल के सामने एक कौआ तेज गति से आया। कोयल ने उससे पूछाः इतनी तेज गति से कहां जा रहे हो? कुछ देर बैठो, बातें करते हैं। कौए ने उत्तर दियाः कि वह जरा जल्दी में है और देश को छोड़कर परदेस जा रहा है। कोयल ने इसका कारण पूछा तो कौआ बोलाः यहां के लोग बहुत खराब हैं। सब तुम्हें ही चाहते हैं। सभी लोग सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं। वह यही चाहते हैं कि तुम हमेशा की तरह इसी प्रकार से उनके क्षेत्र में गाती रहो। वहीं जहां तक मेरी बात है तो मुझे कोई देखना तक नहीं चाहता। यहां तक कि मैं किसी की मुंडेर पर बैठता हूं तो मुझे कंकड़ मारकर वहां से भगा दिया जाता है। मेरी आवाज भी कोई नहीं सुनना चाहता। जहां मेरा अपमान हो, मैं ऐसे स्थान पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। ज्ञानियों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि अपमान की जगह पर नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर कोयल बोली, परदेस जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ। यह पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना कि वहां जाने से पहले अपनी आवाज को बदल लेना। अपनी वाणी को मधुर बना लेना। यदि तुम्हारी वाणी ठीक वैसी ही कठोर रही, जैसी यहां पर है तो परदेस में भी लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो अभी हो रहा है। संसार जो है, जैसा भी है, उसे बदला नहीं जा सकता। ल

अंतर्मन

आज की पाती

डिजिटल तकनीक का करें सही उपयोग

आज बच्चों के सामने सबसे बड़ा खतरा केवल इंटरनेट का बढ़ता उपयोग नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित और असुरक्षित उपयोग है। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा, ज्ञान और संवाद के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही बच्चों का बचपन साइबर खतरों की गिरफ्त में आता जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर बीतने वाला बढ़ता समय उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। डिजिटल युग से बच्चों को दूर रखना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार, तकनीकी कंपनियां, विद्यालय, अभिभावक और समाज यदि मिलकर प्रयास करें, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां बच्चे इंटरनेट के उपभोक्ता नहीं, बल्कि सुरक्षित, जागरूक, सम्मानित और सशक्त नागरिक बनकर देश के भविष्य को नई दिशा दें। *- संतोष उपाध्याय, दुर्ग*

ट्रेंड

जयंती पर श्रद्धांजलि

पिंगली वेंकय्या को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्हें हमारे देश को तिरंगा देने में उनकी अमूल्य भूमिका के लिए याद किया जाता है। उनकी कोशिशें लोगों को देशसेवा करने के लिए प्रेरित करती रहें।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कॉमनवेल्थ गेम्स

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दोनों इवेंट्स में कॉमनवेल्थ पोडियम पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप कई यादगार जीत हासिल करेंगे।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

जर्सी का रंग

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने का फैसला सिर्फ खेल से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और हमारी खेल परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज इस ऐतिहासिक पहचान को बदलने की जरूरत क्यों महसूस की गई।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष, कांग्रेस

इथेनॉल का आयात

सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी जी हमारे देश पर जबरदस्ती इथेनॉल थोप रहे हैं। अमेरिका दुनिया में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ई 20 लागू होने के बाद, भारत पिछले साल के मुकाबले अमेरिका से 5 गुना ज्यादा इथेनॉल आयात करेगा।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

एम्स्टर्डम में आयोजित प्राइस बोट परेड में पीएम हुए शामिल

नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में शनिवार को 'प्राइड बोट परेड' आयोजित किया गया जिसे देखने के लिए शहर की मुख्य नहर के किनारे हजारों लोग जमा हुए। यह आयोजन ऐसे समय हुआ, जब ठीक एक सप्ताह पहले जर्मनी के बर्लिन में प्राइड कार्यक्रम पर जानलेवा हमला हुआ था। सफेद शर्ट, काले लाइफ जैकेट और सुनहरे आभूषण पहने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन रंग-बिरंगी 80 नौकाओं की परेड में एक छोटी नाव पर सवार हुए थे और लोगों का अभिवादन किया। जेटन ने सार्वजनिक रूप से स्वयं के समलैंगिक होने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम बर्लिन में हुए हमले के महज एक सप्ताह बाद आयोजित किया गया। उस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 अन्य घायल हुए थे। अधिकारियों के अनुसार, बर्लिन में संदिग्ध अब्दुल बल्लौत ने 'एलजीबीटीक्यू+' समुदाय के प्राइड महोत्सव के दौरान भीड़ को वैन से रौंद दिया था और बाद में कथित तौर पर दाव से कई लोगों पर हमला किया था। अधिकारियों का मानना है कि यह इस्लामी चरमपंथ से प्रेरित हमला था। रविवार को शहर के बाहरी इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बल्लौत मारा गया। बर्लिन हमले के मद्देनजर एम्स्टर्डम में प्राइड बोड परेड के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे।

ऑफ बीट

प्रकृति के बीच बिताए कुछ पल मानसिक स्वास्थ्य रहेगा बेहतर

आज की कामकाजी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा चारदीवारी के भीतर गुजरता है। घंटों का सफर, लगातार बैठकें और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बीतता दिन- इन सबके बीच प्रकृति के लिए समय निकालना किसी विलासिता जैसा लगने लगता है। कई लोगों को लगता है कि प्रकृति का आनंद तभी मिलता है, जब लंबी छुट्टी लेकर पहाड़ों पर 'ट्रैकिंग' की जाए या जंगलों में 'कैंप' लगाया जाए। लेकिन अब शोध कुछ और ही कहानी कहते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति का लाभ उठाने के लिए किसी रोमांचक यात्रा पर जाना जरूरी नहीं है। घर या दफ्तर के आसपास मौजूद किसी पार्क या हरियाली के बीच रोज कुछ मिनट बिताना भी तनाव कम करने, मन को शांत रखने और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए काफी हो सकता है। साल 2026 की वसंत ऋतु में मुझे डेनमार्क में शहरी परिदृश्य के बारे में पढ़ाने और उनका अध्ययन करने का अवसर मिला। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिने जाने वाले डेनमार्क से मुझे पहले से ही सुंदर पार्क, खुले आंगनों और साइकिल चलाने के लिए बने रास्तों की उम्मीद थी। वहां यह सब तो मिला ही, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह यह था कि लोग इन हरित स्थानों का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं।

संपादकीय

गडकरी सुटले, इथेनॉलचे काय?

पेपरफुटीच्या प्रश्नाचे कवित्व सुरू असतानाच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विरोधी पक्षांनी दंडबैठका सुरू केल्या आहेत. वाहनधारकांच्या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यातील राजकारणावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. कारण, हा विषय बऱ्यापैकी तांत्रिक तसेच वाहनमालकांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. राष्ट्रीय हितासाठी या स्वातंत्र्याचा संकोच केला जाऊ शकतो, हे खरे. परंतु, त्याआधी इथेनॉलविषयीच्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. या मुद्द्यावर सोशल मीडियातून टीका होऊ नये म्हणून परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, मुळात हा विषय आपल्या मंत्रालयाच्या अखत्यारित नाहीच. गडकरींचे बोट हरदीप सिंग पुरी यांच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे आहे. खरे तर, गडकरी या विषयाचे जाणकार आहेत आणि गेली वीस-पंचवीस वर्षे ते इथेनॉलचा प्रचार व प्रसार करताहेत, हे वास्तव आहे. अर्थात, न्यायालयाने गडकरींना दिलासा दिला आहे. परिणामी, याविषयी कोणी टीका केली तर पोलिसांचा दंडुका उगारला जाईल. पण, त्यामुळे इथेनॉलचा मुद्दा संपत नाही. उलट, गडकरींनी न्यायालयाच्या माध्यमातून स्वतःचा बचाव करून घेतल्यामुळे आता हा मुद्दा सरकारसाठी अडचणीचा ठरला आहे. त्यातून अंग काढून घेणे सोपे नाही. कारण, हा विषय मंत्री किंवा मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून एकूणच सरकारच्या जैव-इंधनविषयीच्या धोरणाशी संबंधित आहे. भारताने २३ वर्षांपूर्वी, २००३मध्ये चार राज्ये व चार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रयोग म्हणून पेट्रोलमध्ये जैवइंधन मिसळण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. याविषयी पुरेसा अभ्यास नसल्याने दहा वर्षे हे धोरण कागदावरच होते. २०१३-१४पर्यंत इंधनात जेमतेम दीड टक्क्यापेक्षा कमी इथेनॉल मिसळले जायचे. २०१८मध्ये जैव-इंधनाविषयीचे स्पष्ट धोरण आले. त्यानुसार सुरुवातीला दहा टक्के आणि २०३०पर्यंत वीस टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे ध्येय ठरविण्यात आले. एप्रिल २०१९ मध्ये दहा टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या वापराला सुरुवात झाली. त्यासाठी गाड्यांच्या इंजिनमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले. खरे तर, पुढचा टप्पा या वापराचे सगळे फायदे-तोटे अभ्यासून सुरू करायला हवा होता. हा अभ्यास अद्याप पूर्ण झाला की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने सांगितले की, इथेनॉलचा वापर प्रायोगिक स्तरावर आहे आणि त्याचे निष्कर्ष वर्षभरानंतर हाती येतील. अशा इंधनामुळे इंजिनातील रबराचे काही भाग खराब होऊ शकतात, अशी दुसरी कबुली संसदेत देण्यात आली आहे. असे असूनही वीस टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय निर्धारित लक्ष्यपूर्ती कालावधीच्या पाच वर्षे आधीच जुलै २०२५मध्ये अंमलात आणला गेला. एप्रिल २०२३पासून बनविलेल्या गाड्यांच्या इंजिनांमध्ये ई-२० अनुरूप बदल वाहनउत्पादक कंपन्यांनी केले. म्हणजेच आता रस्त्यांवर २०१९च्या आधीच्या म्हणजे शुद्ध पेट्रोलवर चालणाऱ्या, २०१९ ते २०२३ या कालावधीत बनलेल्या ई-१० अनुरूप आणि एप्रिल २०२३ नंतरच्या ई-२० अनुरूप अशा तीन प्रकारच्या गाड्या धावताहेत. त्यांच्यासाठी पंपावर तीन प्रकारचे आउटलेट हवेत. पण, व्यावहारिकदृष्ट्या ते शक्य नाही आणि शुद्ध, इथेनॉलविरहित पेट्रोलचा लिटरचा दर तब्बल १७० रुपये ठेवून सरकारने वाहनमालकांची कोंडी केली आहे. स्पष्टपणे सांगायचे तर या गाड्या नागरिकांनी स्वतःच्या पैशाने खरेदी केल्या आहेत. त्यावर सगळा कर आधीच भरला आहे. त्या पूर्णपणे नागरिकांच्या मालकीच्या आहेत. त्याविषयी परस्पर निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही. असे निर्णय घेण्याआधी पुरेसा अभ्यास करायला हवा. सर्व शंकांचे निरसन करायला हवे. त्याऐवजी मंत्र्यांनी हा संवेदनशील मुद्दा राष्ट्रकार्याशी जोडण्याचा प्रयोग केला आहे. भारत तब्बल ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यासाठी विदेशी चलन खर्च होते, हे खरे आहे. इथेनॉलमुळे देशाचे काही हजार कोटींचे परकीय चलन वाचले हेदेखील खरे. तथापि, या दाव्याला दुसरीही बाजू आहे. मोटार स्पिरीटचा एकूण वापर लक्षात घेता पेट्रोलच्या तुलनेत ३३ टक्के कमी ज्वलनक्षमता असलेले इथेनॉल पेट्रोलच्या दराने लोकांनी खरेदी केले आणि त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत वाहनधारकांनी बचतीच्या कैक पटीने अधिक खर्च केला आहे. सोबतच सरकार तसेच नीति आयोगाने कबूल केलेय की, इथेनॉलच्या वापरामुळे गाड्यांच्या मायलेजमध्ये ६ ते ७ टक्के घट होईल. प्रत्यक्षात ही घट १५-२० टक्के असल्याचा अनुभव आहे. सामान्य माणूस देशविरोधी नसतो. पण, दुर्दैवाने त्याला तसे ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मृत्यूचे तांडव का सुरू आहे?

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने अमानुषता गाठली आहे. तेथील लोकांचा गुन्हा काय? - तर त्यांना भारतातल्या लोकांसारखे जगावेसे वाटते !

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सैन्य करीत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना अतीव दुःखदायक आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून केवळ रावळकोटमध्येच दीडशेपेक्षा जास्त लोक मारले गेले. हजारो लोकांना जेरबंद केले गेले. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या कारवायांनी कळस गाठला आहे. तेथील लोकांचा गुन्हा काय? तर त्यांना भारतातील काश्मीरमध्ये लोक ज्या प्रकारचे जीवन जगतात तसे जगावे असे वाटते.

पाकव्याप्त काश्मीर आणि भारतीय काश्मीर यांच्यात केवळ काही डोंगर आणि नद्यांचे अंतर आहे. पाकिस्तान दौऱ्यावर असताना मी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती; परंतु पुरेसा वेळ नसल्याचे मला सांगण्यात आले. माझ्या पाकिस्तानी मित्रांनी सांगितले की, त्या संपूर्ण प्रदेशाला निसर्गाने नंदनवनासारखे सौंदर्य बहाल केले आहे. ज्या रावळकोटमध्ये पाकिस्तानी सैन्य लोकांचे रक्त सांडत आहे त्या प्रदेशाला 'पर्ल व्हॅली' अर्थात मोत्यांचे खोरे असेही संबोधले जाते; परंतु पाकिस्तानी सैन्याने या खोऱ्याचे रूपांतर नरकात करून टाकले आहे. संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये महागाईने कहर केला आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये तर आवश्यक तेवढे पीठ आणि स्वयंपाकाचा गॅसही पोहोचत नाही. तेथील गावात कित्येक दिवस वीज नसते. पाकिस्तानमधील मंगला धरण आणि नीलम झेलम जलविद्युत प्रकल्पामुळे पाकिस्तानात उजेड पडत असताना हे घडते आहे.

पाकिस्तानी दहशतवादी देत असलेला त्रास सहन करूनही भारतीय काश्मीर विकास, सुख आणि शांततेच्या रस्त्यावर पुढे जात आहे हे या लोकांना ठाऊक आहे. ३७० वे कलम हटवल्यानंतर परिस्थिती आणखी सुधारली. काश्मीर खोऱ्यात 'वंदे भारत' रेल्वेही पोहोचली. चिनाब नदीवर जगातील सर्वांत उंच रेल्वेचा पूल झाला. पाकव्याप्त काश्मीरमधले लोक मात्र तूर्तास भाकरी, वीज मिळावी आणि पाकिस्तानी सैन्याचे अत्याचार थांबवावेत एवढीच मागणी करीत आहेत; परंतु त्यांना पाकिस्तानी सैन्याकडून मिळतात बंदुकीच्या गोळ्या आणि घाणेरड्या शिव्या. खरे तर भारतात विलीन होण्याची त्यांची इच्छा आहे. भारताच्या स्वतःच्या काही राजनैतिक अडचणी असल्या तरी पाकव्याप्त काश्मीर भारतात सामील व्हावे अशी इच्छा या बाजूलाही आहेच.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि योगी आदित्यनाथ यांनी उघडपणे ही इच्छा व्यक्त केलेली आहे. भारत एक घर असेल तर बाहेरच्यांनी बळकावलेली त्या घरातली एक खोली म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर असून, एक ना एक दिवस ती परत मिळवावी लागेल, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत

पाकव्याप्त काश्मीरसाठी २४ जागा आरक्षित केल्या गेल्या आहेत. भारत प्रत्येक व्यक्तीला चांगले जीवन जगण्याचा हक्क देण्यासाठी माणुसकीला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. अशा परिस्थितीत पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतात येण्याची व्याकूळता असणारच! पाकिस्तानलाही हे उत्तम प्रकारे समजते. म्हणूनच भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न हा देश सातत्याने करीत असतो. भारतात होत असलेली प्रगती ज्यांच्यासाठी धोका उत्पन्न करू शकते अशा विघातक शक्तीही त्यात आहेत. यातूनच नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव यासारख्या देशांचा भारताविरुद्ध वापर करण्याचा प्रयत्न झाला. नेपाळमध्ये जेन-झीने त्यांच्या आशा धुळीस मिळवल्या आणि नेपाळला चीनच्या छायेतून बाहेर काढले. श्रीलंका आपला मित्र आहे; परंतु चीनने भरमसाठ कर्ज देऊन श्रीलंकेला दाबून ठेवले आहे. गावपातळीवर जे राजकारण चालते ते सगळ्या जगाच्या स्तरावरही चालू असते; परंतु आजचा भारत दूरदृष्टी आणि पक्के इरादे बाळगणारा आहे. पहलगामचे उत्तर 'ऑपरेशन सिंदूर'ने कसे द्यावे, हे हा देश जाणतो.

स्वादिष्ट खिचडी शिजते आहे...

'डिसेंबरपर्यंत आपण आपल्या मायदेशात परतू' असे गेल्या महिन्यात बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी म्हटले, त्याचे लोकांना आश्चर्य वाटले. फाशीची शिक्षा सुनावली गेलेली असताना हसीना स्वतःच परतीची भाषा कशी करतात? - परंतु जे दिसते ते नेहमी घडतेच असे नाही.

बांगलादेशात सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न जहालवाद्यांनी पाहिले होते; परंतु अमेरिकेच्या सहकार्याने भारताचे राजनैतिक डावपेच उपयोगी पडले आणि तारिक रहमान बांगलादेशात परत आले, तिथले पंतप्रधानही झाले. मात्र, काळाच्या दोन गरजा आहेत. विरोधी पक्षांचा झेंडा जहाल मतवाद्यांच्या हातातून काढून घेणे ही पहिली गरज आणि पाकिस्तानच्या मदतीने जगातील दहशतवादी संघटना बांगलादेशमध्ये ज्या दहशतवादी छावण्या चालवतात त्या नष्ट करणे ही दुसरी. याचा उत्तम अनुभव हसीना यांना आहे. त्यांच्या काळात अनेक दहशतवाद्यांना फासावर चढवले गेले.

- हाच तो खेळ! खेळाडूंनी कंबर कसली असून, हसीना बांगलादेशमध्ये परततील आणि जहालवाद्यांना नष्ट करण्यासाठी पुढे येतील ही शक्यता आहे. राजकारण आणि कूटनीतीत केव्हाही काहीही अशक्य नसते. आणखी एक गोष्ट. आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल अलीकडे काही खास कामात जरा जास्तच व्यग्र दिसतात. जयशंकर यांनी अलीकडेच मध्यपूर्वेतील देशांचा दौरा का केला, हे मला ठाऊक नाही; परंतु काहीतरी खिचडी शिजते आहे, हे नक्की! तूर्तास वाट पाहूया.

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

अन्वयार्थ

राज्यातले पशुवैद्यक महत्त्वाचे आहेत, त्यांची नाराजी दूर करा!

महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेतर्फे पदवीधरांकडून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी शुल्क आकारले जाते, जे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत जास्त आहे.

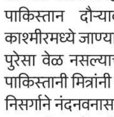

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली

आज पशुवैद्यकीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येत आहेत. राज्याच्या एकूण सकल उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ करायची असेल तर पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे, ही बाब सर्वच धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आली आहे. याच भूमिकेतून शासकीय खात्याची पुनर्रचना, रिक्त पदांची भरती, जिल्हा पातळीवर प्रशासकीय एकत्रीकरण, सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांच्या प्रमुखपदी पदवीधरांची नियुक्ती आणि अर्थसंकल्पामध्ये भरीव निधीची तरतूद, अशा अनेक सकारात्मक बाबींवर निर्णय घेतले जात आहेत.

या सर्व उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पशुवैद्यकीय पदवीधरांची गरज भासणार आहे. ही गरज भागवण्यासाठी नवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर केली जात आहेत. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्रातही पदवीधरांना मोठी मागणी आहे. लहान पाळीव प्राणी व मोठ्या जनावरांसाठी अनेक तरुण पदवीधर स्वतःचे खासगी दवाखाने उभारून सेवा देत आहेत.

पशुवैद्यकीय पदवीधरांना कायदेशीर ओळख मिळवून देण्यासाठी व त्यांना प्रॅक्टिसचा अधिकृत अधिकार प्रदान करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात 'पशुवैद्यक परिषद' कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात १ ऑगस्ट १९९७ रोजी 'भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम, १९८४' लागू झाला. या कायद्यानुसार २६ जून १९९८ रोजी पुण्यात 'महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद' (MSVC) सुरू झाली. त्यानंतर ६ जुलै २००१ रोजी शासन निर्णयानुसार हे मुख्यालय नागपूर येथे स्थलांतरित करण्यात आले आणि २६ ऑगस्ट २००९ रोजी सर्व नोंदणीकृत डॉक्टरांनी निवडलेली पहिली अधिकृत बॉडी अस्तित्वात आली. राज्यातील पशुवैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करणे, अनधिकृत व बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करणे आणि व्यावसायिक गुणवत्तेसह आचारसंहिता जपणे हे परिषदेचे मुख्य कर्तव्य आहे. शासकीय वा खासगी नोकरीत पात्रता पडताळणीसाठी ही नोंदणी अनिवार्य असते. पदवीधरांची व्यावसायिक सुरक्षा, तक्रार निवारण आणि निरंतर शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत नवीन आजार व आधुनिक शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण देणे ही कामेही परिषद करते.

देशातील सर्व राज्य परिषदा दिल्लीस्थित भारतीय पशुवैद्यक परिषदेशी (VCI) जोडलेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित VCI देशभरासाठी आचारसंहिता व नियम बनवते, तर राज्य परिषद त्याची अंमलबजावणी करते. राज्य परिषदेत नोंदणी झाल्यानंतर डॉक्टरांना देशभरात कुठेही काम करण्याचा कायदेशीर परवाना मिळतो. दर ५ वर्षांनी नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असते.

सध्या MSVC कडून पदवीधरांकडून ₹५,००० इतके नोंदणी शुल्क आकारले जाते, जे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत जास्त आहे. फी ठरवण्याचे अधिकार राज्य परिषदांकडे असल्याने भारतात यात मोठी तफावत दिसते. उदाहरणार्थ- तामिळनाडूमध्ये ₹५००, कर्नाटकात ₹१५००, गुजरातमध्ये ₹२०००, राजस्थानमध्ये ₹१५०० आणि दिल्लीत नाममात्र ₹५०० शुल्क घेतले जाते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील फी ३ ते १० पट जास्त असणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. इतर राज्यांत केंद्र व राज्य सरकारच्या 'प्रोफेशनल एफिशियन्सी डेव्हलपमेंट' योजनेतून प्रशासकीय खर्चासाठी अनुदान मिळते. महाराष्ट्रात मात्र स्वतःचा कार्यालयीन खर्च, पगार व निवडणुकांचा खर्च भागवण्यासाठी नोंदी व नूतनीकरण शुल्कावरच जास्त अवलंबून राहावे लागते.

वास्तविक, या शुल्कातून 'डॉक्टर्स वेल्फेअर फंड' (कल्याणकारी निधी) उभारून विमा संरक्षण किंवा थेट आर्थिक मदतीसारख्या योजना सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, बहुतांश रक्कम केवळ प्रशासकीय व कायदेशीर कामांवरच खर्च होताना दिसते. याशिवाय, सेवानिवृत्त डॉक्टरांकडूनही पूर्ण ₹५००० फी आकारणे, नूतनीकरणास किंचित उशीर झाल्यास अवाढव्य विलंबशुल्क आकारणे आणि नूतनीकरणाची मुदत संपण्यापूर्वी एसएमएस, मेल किंवा पत्राद्वारे कोणतीही पूर्वसूचना न देणे, यामुळे राज्यातील पदवीधरांमध्ये मोठी नाराजी आहे.

राज्यातील पदवीधरांची वाढती संख्या, महाविद्यालये आणि पशुसंवर्धन विभागातील डॉक्टरांचे योगदान लक्षात घेता, नोंदणी शुल्कात कपात करण्याबाबत शासन स्तरावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी आणि परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक इच्छाशक्ती दाखवून योग्य निर्णय घेतल्यास पशुवैद्यकांमधील हा नाराजीचा सूर नक्कीच कायमचा दूर होऊ शकेल.

vyankatrao.ghorpade@gmail.com

जगभर

टोक्योचा विनाश? जपान उभारतोय दुसरी राजधानी !

टोक्यो. जपानची राजधानी म्हणून हे शहर अख्ख्या जगात परिचित आहे. हे शहर जगातील सर्वात मोठ्या महानगरांपैकी एक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, समृद्ध संस्कृती, स्वच्छता आणि उत्कृष्ट सार्वजनिक वाहतूक यांसाठीही या शहराचं नाव जगभरात आदरानं घेतलं जातं. पण जपाननं टोक्योसंदर्भात नुकताच एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आहे. जपानची शान असलेलं टोक्यो आता देशाची एकमेव राजधानी राहणार नाही.

जपानी संसदेनं देशाची 'दुसरी राजधानी' उभारण्याच्या ऐतिहासिक कायद्याला मंजुरी दिली आहे. का? काय कारण आहे त्यामागे? - जपानचे वैज्ञानिक आणि ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार पुढील ३० वर्षांत टोक्योमध्ये ७ रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचा भीषण भूकंप होण्याची ७० टक्के शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. असं झाल्यास संपूर्ण टोक्यो काही क्षणांत उद्ध्वस्त होऊ शकतं. पंतप्रधान कार्यालय, संसद आणि देशाची संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था एका झटक्यात ठप्प होऊ शकते. या संभाव्य संकटापासून देशाला वाचवण्यासाठी जपानी सरकारनं बॅकअप म्हणून 'दुसऱ्या राजधानी'चा मास्टरप्लॅन तयार केला आहे.

संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक अत्यंत कमी मतांच्या फरकानं नुकतंच मंजूर झालं.

हा निर्णय केवळ भूकंपाच्या भीतीमुळंच घेतलेला नाही. टोक्योमध्ये झपाट्यानं वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळं वाढलेला ताण हेदेखील त्यामागचं मोठं कारण आहे. सध्या एकट्या टोक्योमध्ये जपानची सुमारे ३० टक्के लोकसंख्या राहते आणि देशाच्या उत्पन्नाचा पाचवा हिस्सा याच शहरातून मिळतो. सरकारची इच्छा आहे की देशाची आर्थिक आणि प्रशासकीय ताकद केवळ टोक्योपुरती मर्यादित राहू नये. दुसरी राजधानी उभारल्यानंतर त्या शहरात अब्जावधी रुपयांची नवी गुंतवणूक केली जाणार असून, त्यामुळे इतर शहरांचाही वेगानं विकास होण्याची अपेक्षा आहे.

संसदेत कायदा मंजूर होताच जपानमधील अनेक

मोठे आणि समृद्ध प्रांत दुसऱ्या राजधानीचा मान मिळवण्यासाठी स्पर्धेत उतरले आहेत. कायद्यानुसार नवी राजधानी त्या शहराला घोषित केलं जाईल, जे भूकंपाच्या दृष्टीनं सुरक्षित असेल आणि देशाचं प्रशासन चालवण्याची पूर्ण क्षमता बाळगत असेल. ओसाका, आइची आणि नागोया, फुकुओका आणि सपोरो ही चार शहरं राजधानी बनण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.

टोक्योनंतर ओसाका हे जपानमधील सर्वांत मोठं आणि प्रभावशाली शहर मानलं जातं. अनेक शतकांपासून ते देशाचं आर्थिक केंद्र आहे. आइची प्रांताच्या राज्यपालांनी त्यांच्या प्रांताकडं सर्व आवश्यक सुविधा आणि क्षमता असल्याचा दावा सर्वप्रथम केला आहे. फुकुओकाच्या राज्यपालांनीही स्थानिक उद्योगपतींना सोबत घेत या शर्यतीत उडी घेतली आहे, तर सपोरोचं म्हणणं आहे, त्सुनामी किंवा भूकंप झाला तरी सपोरो पूर्णपणं सुरक्षित राहील.

या नव्या कायद्यावरून जपानमध्ये मोठा राजकीय संघर्षही सुरू झाला आहे. विरोधक आणि टीकाकारांचा आरोप आहे की पंतप्रधान सानाए ताकाइची या आपली सत्ता टिकवण्यासाठी आघाडीतील सहकारी 'जपान इनोव्हेशन पार्टी' (JIP)च्या दबावाखाली काम करत आहेत. ओसाका हा JIPचा बालेकिल्ला मानला जातो आणि या कायद्याच्या माध्यमातून पक्षाचा ओसाकावरील प्रभाव आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

जपानची नवी राजधानी नेमकी कोणती असेल आणि सरकारी कार्यालयं या नव्या शहरात नेमकी कधी आणि कशी हलवली जाणार, हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. मात्र या निर्णयानं टोक्योचं अनेक वर्षांचं वर्चस्व निश्चितच हादरलं आहे.

करनीती

३१ ऑगस्टपूर्वी रिटर्न कोणाला भरावा लागेल?

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, ३१ जुलैची अंतिम तारीख संपली आणि ५.९२ कोटी करदात्यांनी आयकर रिटर्न भरला. पण, आता काही व्यापारी आणि व्यावसायिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत रिटर्न भरायचा आहे, असे सांगितले जात आहे. ही अंतिम तारीख नेमकी कोणासाठी आहे?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, यंदा प्रथमच व्यावसायिकांसाठी वेगळी अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेकांचा गोंधळ होत आहे. ITR-1 आणि ITR-2 भरणाऱ्यांची अंतिम तारीख ३१ जुलै होती. तर टॅक्स ऑडिट लागू नसलेल्या ITR-3, ITR-4 आणि ITR-5 भरणाऱ्या व्यापारी व व्यावसायिकांची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट आहे.

अर्जुन : मग नेमके कोणत्या करदात्यांनी ३१ ऑगस्टपूर्वी रिटर्न भरावा?

कृष्ण : ITR-3 : व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती किंवा HUF, जी नियमित खात्यांची पुस्तके ठेवते त्यांना अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट आहे.

ITR-4 (सुगम) : कलम 44AD, 44ADA किंवा 44AE अंतर्गत प्रिझम्प्टिव्ह कर योजना निवडणारा रहिवासी करदाता त्यांना अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट आहे.

ITR-5 : भागीदारी फर्म, LLP किंवा काही इतर संस्था त्यांना अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट आहे, म्हणजे टॅक्स ऑडिट लागू नसलेल्या ITR-3, ITR-4 आणि ITR-5 भरणाऱ्या सर्व करदात्यांसाठी ३१ ऑगस्ट ही अंतिम तारीख आहे.

- उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटंट

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

जेन झी

जेन झीनं वापरलेली आणि त्यांच्यासाठी वापरली गेलेली भाषा...

उतरंडीमध्ये वरून खालच्या दिशेला जाणाऱ्या शिव्या ही हिंसा असते, मात्र खालून वर जाणारे अपशब्द हा असभ्यपणा असतो...

राही श्रु. ग.
सीनिअर रिसर्च फेलो
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेन झीसाठी वेगवेगळी नावं वापरली गेली. कोणी त्यांना झुरळं, किडे म्हटलं तर कोणी 'गटारातली पिढी'. ज्या देशात भर संसदेत शिव्या दिल्या जातात आणि जे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधकांना अश्लाघ्य भाषेत हिणवत राहतात, त्या देशातली तरुण पिढी अपशब्द वापरते म्हणून माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि नेतेमंडळी आश्चर्यचकीत होतात, हे अनाकलनीय आहे. दिल्लीत आणि देशभरात विविध ठिकाणी जेन झीने शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारच्या अपयशाच्या विरोधात आंदोलन केलं. पेपरफुटी आणि प्रवेश परीक्षांमधल्या इतर घोटाळ्यांची जबाबदारी घ्यायला लावत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावला. अगदी काही महिन्यांपर्यंत अकल्पनीय असलेला हा बदल ज्या जेन झीने घडवून आणला, त्यांना आज त्यांच्या भाषेविषयी प्रश्न विचारले जात आहेत.

सरकारच्या नीतीला, नेतेमंडळींना विरोध करताना जेन झीने भान सोडून शिव्या दिल्या, अश्लील भाषेत हेटाळणी आणि चेष्टामस्करी केली, हे सगळ्या बातम्यांच्या चॅनल्सवर पुन्हा पुन्हा दाखवलं जातंय. आंदोलन करणाऱ्या सगळ्याच तरुणांनी अशी भाषा वापरली, हे खरं नसलं तरी काही तरुणांनी पेपर 'लीक' थांबवण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्त्यावर डायपर पाठवले. विविध प्रकारे तरुणांनी सरकारची, नेत्यांची हेटाळणी केली, थट्टा केली आणि त्यांना थेट शिव्याही दिल्या. इटालियन पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना मोदींनी त्यांच्या अलिकडच्या भेटीत 'मेलडी' चॉकलेट दिलं, या घटनेवर कितीतरी फलक आंदोलक तरुणांनी केले होते.

म्हटलं तर तरुणांनी असभ्य, उद्धट भाषा वापरणं, हे काही नवीन नाही. मात्र, तरीही जेन झींना सत्ताधाऱ्यांनी 'गटारातली पिढी' म्हणावं इतका राग येण्यामागे कारण आहे. गेल्या बारा वर्षांमधल्या भाजप सरकारच्या काळात जेवढी मोठी आंदोलनं झाली, त्यांच्यात वापरल्या गेलेल्या भाषेमध्ये भारतातल्या जनआंदोलनांच्या इतिहासातल्या क्रांतिकारी घोषणा होत्या, गाणी आणि कविता होत्या. व्यंगही होती. मात्र, शिव्या देणं, हे कोणाच्याही कल्पनेबाहेर होतं. ज्या सरकारात सभ्य भाषेत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने विचारलेल्या प्रश्नांवरही हिंसक उत्तरं दिली जातात तिथे लाखोंच्या संख्येच्या बळावर हे व्यंग, प्रसंगी असभ्य भाषा वापरून तरुणांनी ज्यांची अनेक लोक 'भक्ती' करतात, अशा दैवी पातळीवर पोचलेल्या सरकाराला माणसात आणलं. सामान्य माणसांना दहशतीमुळे अप्राप्य वाटणाऱ्या सत्तेला या तरुणांनी स्पर्श करून त्याचं पावित्र्य भंग करून टाकलं.

याच सत्ताधीश सरकारातल्या मंत्र्यांच्या मुस्लिमविरोधी विखारी भाषणांमुळे दिल्लीत सहा वर्षांपूर्वी भीषण नरसंहार झाला होता. सत्ताधीशांच्या मर्जीतले 'गोदी' पत्रकार अनेकदा अश्लाघ्य भाषेत विरोधकांना शिव्या देतात. या प्रत्येक हल्ल्याचं उत्तर त्याच शब्दकोषातून द्यायला हवं असं नाही. आनंद तेलतुंबडे म्हणतात, त्याप्रमाणे, उतरंडीमध्ये वरून खालच्या दिशेला जाणाऱ्या शिव्या ही हिंसा असते, मात्र खालून वर जाणारे अपशब्द हा असभ्यपणा असतो. शब्दांमधली ही ताकद आता जेन झींना कळली असेल. सत्तेला विरोध करताना शिव्यांमध्येही लपलेली जात आणि लिंगभावाच्या उतरंडींबाबतची हिंसा त्यांना दिसेल. मात्र, तोवर सभ्य- असभ्य, पवित्र-अपवित्र, शुद्ध-अशुद्ध या द्वैतांना त्यांच्यासह बाकीच्यांनीही प्रश्न विचारायला हरकत नाही.

raheeshrutiganesh@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२-२७७८०२४६
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२-२४९०८८५३-५८ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४
● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : २७७५६८८८ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही एकमात्र रास्ता है। - महात्मा गांधी

दक्षिण कश्मीर में दो प्रवासी मजदूरों की नाम पूछकर हत्या वहां सामान्य होते जन-जीवन पर एक और सुनियोजित आतंकी हमला है। जब-जब पाकिस्तान आंतरिक संकटों से घिरता है या पीओके से जुड़े प्रश्न अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आने लगते हैं, तब-तब वह ऐसे हमले करता है, जो उसकी हताशा ही दर्शाते हैं।

हताशा और हमले

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की नाम पूछकर की गई हत्या सिर्फ एक और आतंकी वारदात नहीं, बल्कि देश के सामाजिक सद्भाव और जम्मू-कश्मीर में सामान्य होते जन-जीवन पर एक सुनियोजित हमला है। पिछले वर्ष अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की पहचान पूछकर हत्या कर दी गई थी, की तरह ताजा हमले की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा के मुखौटा समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी आतंकी समूहों के इरादे वही पुराने हैं- कश्मीर में भय का वातावरण बनाना, विकास की प्रक्रिया को बाधित करना और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच अविश्वास पैदा करना। पिछले छह वर्षों में टारगेट किलिंग की ऐसी वारदातों में जिन छियालीस लोगों की जानें गई हैं, उससे आतंकियों की मंशा का पता चलता है। वे जानते हैं कि निर्दोष लोगों की हत्या से भय का प्रभाव अधिक व्यापक होता है और उसकी अंतरराष्ट्रीय चर्चा भी होती है। आतंकियों की रणनीति भी यही होती है कि कम संसाधनों में अधिकतम दहशत पैदा की जाए। इन सभी घटनाओं को पाकिस्तान की व्यापक रणनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और सीमा पार आतंकी ढांचे पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के अलावा भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अपनाई गई कठोर नीति के बीच पाकिस्तान लगातार ऐसे प्रॉक्सी संगठनों का सहारा लेता रहा है, जो उसकी बढ़ती हताशा को दर्शाता है। टीआरएफ जैसे नामों का उपयोग ही पाकिस्तानी आतंकी फैक्टरी ने इसलिए किया, ताकि आतंकवाद को स्थानीय असंतोष का रूप देकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया जा सके। जबकि, हकीकत यह है कि इन संगठनों के प्रशिक्षण, हथियार, पैसा और वैचारिक समर्थन की डोर आज भी सीमा पार से ही संचालित होती है। यह भी गौरतलब है कि जब-जब पाकिस्तान आंतरिक संकटों से घिरता है या पीओके से जुड़े प्रश्न अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आने लगते हैं, तब-तब सीमा पार से आतंकी गतिविधियों में भी तेजी देखी जाती है। दरअसल, आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक व कूटनीतिक उपकरण रहा है। ऐसे में इन आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस पूरी संरचना को कमजोर किया जाए, जिसके बल पर आतंकी संगठन सक्रिय बने रहते हैं। इसके लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पाकिस्तान का असल चेहरा सामने लाने की कोशिशें करते रहना होगा। इसके अतिरिक्त, भारत को अपने सुरक्षा तंत्र को और अधिक सक्षम बनाना होगा, वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में विकास, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता की प्रक्रिया को बिना रुके आगे बढ़ाते रहना होगा और यही आतंकवाद का सबसे प्रभावी उत्तर भी होगा।

क्या हमास वाकई हथियार छोड़ेगा

ट्रंप का दावा है कि हमास और गाजा के अन्य चरमपंथी संगठन हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई संभव है, क्योंकि हमास के लिए सशस्त्र संघर्ष केवल उसकी नीति नहीं, बल्कि फलस्तीनियों के बीच उसकी वैधता का सबसे बड़ा आधार भी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास और गाजा के अन्य चरमपंथी संगठन हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने इसे गाजा में स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक 'महत्वपूर्ण कदम' बताया है। ट्रंप के अनुसार, हमास के निरस्त्रीकरण से फलस्तीनी समिति गाजा का प्रशासन संभाल सकेगी और इस्राइली सेना को वहां से हटने का रास्ता मिलेगा। यह कदम उनकी 20-सूत्री शांति योजना का हिस्सा है, जिस पर पिछले साल अक्तूबर में हमास और इस्राइल ने सहमति जताई थी।

हालांकि, हमास के अधिकारियों ने कहा है कि वे इस प्रक्रिया पर सहमत हैं, लेकिन बातचीत में शामिल एक सदस्य ने चेतावनी दी कि उनका हथियार छोड़ना तभी संभव होगा, जब इस्राइल गाजा से पूरी तरह अपनी सेना वापस बुला ले। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वास्तव में शांति की दिशा में निर्णायक कदम है, या अब भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं?

मार्टिन कीर
प्रोफेसर,
सिडनी यूनिवर्सिटी

यदि हमास वास्तव में पूरी तरह हथियार छोड़ने पर सहमत हो जाता है, तो यह वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम पर इस्राइली कब्जे के खिलाफ करीब चार दशक से चल रहे संघर्ष में उसकी ओर से एक बड़ी रियायत होगी। हमास की शुरुआत 1987 में दो लक्ष्यों के साथ हुई थी-इस्राइली कब्जे का विरोध करना और फलस्तीनी राजनीति में फतह पार्टी के वर्चस्व को चुनौती देना।

अपने 2017 के चार्टर में हमास ने स्पष्ट कहा था कि वह 'प्रतिरोध और उसके हथियारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है।' संगठन के अनुसार, 'सशस्त्र संघर्ष फलस्तीनी जनता के सिद्धांतों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक विकल्प है।' इसके अलावा, फलस्तीनियों के बीच हमास की वैधता का मुख्य आधार उसका सशस्त्र प्रतिरोध ही है। फलस्तीनियों के लिए, यह प्रतिरोध एक स्वतंत्र देश का दर्जा हासिल करने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है। यानी भले ही कई फलस्तीनी राजनीतिक रूप से हमास या उसके इस्लामी एजेंडे का समर्थन न करते हों, फिर भी वे इस आंदोलन का सम्मान करते हैं। उनके लिए इस्राइली कब्जे के खिलाफ हमास का लगातार सशस्त्र प्रतिरोध या तो फलस्तीनी राष्ट्र की मांग को मजबूत करता है या फिर इस्राइल के स्थायी कब्जे की कोशिशों को चुनौती देता है।

अक्तूबर 2025 में 'पीपल्स सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च' (पीसीपीएसआर) के सर्वे के अनुसार, 60 फीसदी फलस्तीनियों (वेस्ट बैंक में 66 प्रतिशत और गाजा में 51 फीसदी) ने हमास के प्रदर्शन पर संतोष जताया। वहीं, 69 प्रतिशत लोग (वेस्ट बैंक में 87 फीसदी और गाजा में 55 प्रतिशत) गाजा पट्टी में हमास के हथियार छोड़ने के खिलाफ थे। इसे देखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि हमास फलस्तीनियों के बीच अपने इस समर्थन को जोखिम में डालेगा।

शुरुआती मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हमास के निरस्त्रीकरण का मतलब केवल हथियार सौंपना नहीं होगा, बल्कि गाजा में उसके पूरे सैन्य ढांचे को खत्म करना भी होगा। इसमें सुरंगों का नेटवर्क, भारी हथियार, हथियार बनाने के केंद्र और गोला-बारूद के भंडार भी शामिल हैं। हालांकि, गाजा में हुई व्यापक तबाही को देखते हुए यह साफ नहीं है कि इस सैन्य ढांचे का कितना हिस्सा अब भी बचा है। इसी तरह, हमास के पास फिलहाल कितने हथियार हैं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उसके पास अब भी हजारों ऑटोमैटिक राइफलें और एंटी-टैंक रॉकेट जैसे भारी हथियार हो सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक संख्या पहले के मुकाबले काफी कम मानी जा रही है। कई अन्य अहम सवाल भी अभी अनुत्तरित हैं। मसलन, हमास से हथियार कौन लेगा और यह कैसे तय होगा कि उसने वास्तव में सभी हथियार सौंप दिए हैं? एक अमेरिकी अधिकारी ने *बीबीसी* से कहा कि उसके लिए किसी तीसरे पक्ष की समिति यह जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई।

इसके अलावा, हमास सिर्फ गाजा पट्टी तक सीमित नहीं है। उसकी मौजूदगी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में भी है। ऐसे में, यह स्पष्ट नहीं है कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया संगठन के उन हिस्सों पर भी लागू होगी या नहीं। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में कट्टरपंथी यहूदियों की ओर से फलस्तीनियों पर लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमास या अन्य फलस्तीनी सशस्त्र आंदोलनों के सदस्य अपनी हिंसा के जरिये इस हिंसा का विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में, हथियार छोड़ने और गाजा का प्रशासन किसी अन्य व्यवस्था को सौंपने पर सहमत होना हमास की ओर से एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इससे समूह को इस्राइल से मिली भारी शिकस्त के बाद संगठनात्मक रूप से उबरने में मदद मिल सकती है, साथ ही व्यापक फलस्तीनी आबादी के बीच अपने प्रतिरोध के एजेंडे को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है।

इस समझौते पर इस्राइल की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, इस्राइली सरकार ट्रंप की इस शांति योजना पर आपत्ति जता रही है। सिर्फ दो सप्ताह पहले ही इस्राइल के कट्टर दक्षिणपंथी रक्षा और वित्त मंत्रियों ने उत्तरी गाजा में तीन नए 'नाहल' आउटपोस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। दरअसल, नाहल आउटपोस्ट ऐसे ठिकाने होते हैं, जहां सैन्य मौजूदगी के साथ खेती और सामुदायिक गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। अतीत में ऐसे कई आउटपोस्ट बाद में स्थायी इस्राइली बस्तियों में बदल चुके हैं। इस्राइल के इस विरोध के कारण समझौता टूट सकता है, जब तक कि ट्रंप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर शांति प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उचित दबाव न डालें। हाल ही में यह दबाव बढ़ना शुरू हो गया था, जब एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर इस्राइल इसमें बाधा डालता है, तो ट्रंप 'बेहद निराश' होंगे। (द कन्वर्सेशन)

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जिद्दू कृष्णमूर्ति

जब तक आप केवल सतह पर जीते हैं, तब तक हर छोटी बात आपको विचलित करेगी। लेकिन यदि मन में गहराई है, तो बाहरी लहरें आपको हिला नहीं सकतीं। समुद्र हमें यही सिखाता है- गहराई, न कि विस्तार।

समुद्र की महानता तो उसकी गहराई में है

क्या आपने कभी समुद्र को देखा है? यदि आप वास्तव में समुद्र को देखें, तो पाएंगे कि उसमें एक विलक्षण व्यवस्था है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, गर्जना करती हैं, लेकिन तब भी उसके भीतर एक गहरा मौन मौजूद रहता है। वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित है, फिर भी अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। अब प्रश्न यह नहीं है कि समुद्र अपनी सीमा क्यों नहीं लांघता। प्रश्न यह है कि मनुष्य अपनी सीमा क्यों लांघता है? हमारे भीतर आखिर ऐसा क्या घटित होता है कि हम निरंतर ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लेने की होड़ में लगे रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा धन, सत्ता, ज्ञान और सुरक्षा। यह 'ज्यादा से ज्यादा' की इच्छा ही हमारे भीतर अशांति पैदा करती है। और जहां अशांति है, वहां अतिक्रमण है। समुद्र महत्त्वाकांक्षी नहीं है। उसने कभी पर्वत, नदी या आकाश बनने की इच्छा नहीं की। वह जो है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। लेकिन मनुष्य स्वयं से कभी संतुष्ट नहीं होता। वह निरंतर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है। और यह 'बनने' की प्रक्रिया ही संघर्ष का स्रोत है।

जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं, तभी ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या से महत्त्वाकांक्षी आती है, महत्वाकांक्षा से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा से भय और भय से मनुष्य अपनी सारी सीमाएं तोड़ डालता है। इसलिए समस्या सीमा की नहीं है। समस्या उस मन की है, जो स्वयं को नहीं जानता। समुद्र को किसी ने अनुशासन नहीं सिखाया। फिर भी उसमें व्यवस्था है, क्योंकि उसकी व्यवस्था भीतर से आती है, बाहर से थोपी नहीं गई है। यही बात मनुष्य के लिए भी सत्य है। यदि आपका अनुशासन भय पर टिका है, तो वह वास्तविक अनुशासन नहीं है। यदि आप सजा के खौफ से मर्यादा में रहते हैं, तो वह मर्यादा नहीं, कैद है। सच्ची मर्यादा तो तब जन्म लेती है, जब मन स्वयं को स्पष्ट रूप से देख लेता है। बिना निर्णय के, बिना निंदा के और बिना औचित्य सिद्ध किए देखना ही ध्यान है। और जब देखने वाला तथा देखा जाने वाला अलग नहीं रह जाते, तब मन में एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। उस शांति में अतिक्रमण संभव नहीं। समुद्र की गहराई को देखिए। सतह पर तूफान हो सकता है, लेकिन गहराई शांत रहती है। हमारा जीवन ठीक इसके विपरीत है। सतह पर हम मुस्कुराते हैं, मगर भीतर तो बड़ा तूफान है। हम सम्मान, प्रेम और सुरक्षा चाहते हैं और इसी खोज में खुद को खो बैठते हैं। जब तक आप केवल सतह पर जीते हैं, तब तक हर छोटी बात आपको विचलित करेगी। किसी की आलोचना, प्रशंसा, सफलता या असफलता- ये सब आपको प्रभावित करते हैं। लेकिन यदि मन में गहराई है, तो बाहरी लहरें आपको हिला नहीं सकतीं। समुद्र हमें यही सिखाता है- गहराई, न कि विस्तार। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ऐसी गहराई खोज लेगा, उस दिन वह भी समुद्र की तरह होगा- असीम होकर भी मर्यादित, शक्तिशाली होते हुए भी शांत और स्वतंत्र रहते हुए भी व्यवस्था से परिपूर्ण।

दुनिया से पहले खुद को जानें

सूत्र

इन्सान को समुद्र की तरह अपनी गहराई को पहचानना चाहिए। जब मन सजा के दबाव से मुक्त होकर स्वयं को स्पष्ट रूप से देखता है, तब सच्ची मर्यादा का जन्म होता है। बाहरी आलोचना या प्रशंसा से विचलित हुए बिना यदि हम अपनी सतह से परे भीतर की शांति को खोज लें, तो हम भी असीम और मर्यादित बन सकते हैं। दुनिया से पहले खुद को जानें।

दूसरा पहलू

गुवाहाटी विवि के शोधकर्ताओं ने खोजी भारतीय जुगनू की ऐसी प्रजाति, जो कैंसर ट्यूमर को ट्रैक करने की तकनीक में सुधार कर सकती है।

कैंसर को भी ट्रैक कर सकते हैं जुगनू

■ *अमित मुद्गल*

बृंदावन में एक जगह है निधिवन। मान्यता है कि निधिवन में आज भी हर रात भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी गोपियों संग रासलीला करते हैं। केवल जुगनू रातभर यहां चमकते हैं और अपना प्रकाश बिखेरते हैं। जुगनू अपने आप में प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है। लैम्पिरिडी परिवार का यह कीट अपनी जैविक चमक के लिए जाना जाता है। इनके शरीर के पिछले हिस्से में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे 'बायोल्यूमिनेसेंस' कहा जाता है। इनमें 'ल्यूसिफरेज' एंजाइम व 'ल्यूसिफेरिन' तत्व होता है, जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रकाश पैदा करता है। खास बात यह है कि जुगनू की रोशनी पूरी तरह ठंडी होती है, जिससे यह खुद नहीं जलता।

इस सर्वे में पाया गया कि रेगिस्तानी इलाकों में जुगनुओं की एक भी प्रजाति नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इनकी भरमार है।

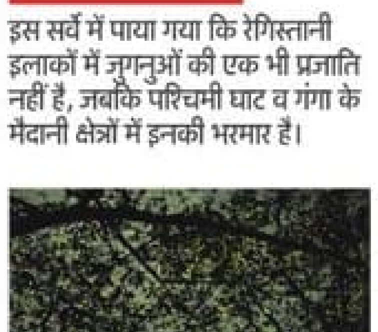

खास बात यह है कि जुगनू की रोशनी पूरी तरह ठंडी होती है, जिससे यह खुद नहीं जलता। यह प्रकाश मुख्य रूप से साथी को आकर्षित करने व दुश्मन से बचाव के लिए होता है, जिसे 'लव सिग्नल' कहते हैं।

यह प्रकाश मुख्य रूप से साथी को आकर्षित करने व दुश्मन से बचाव के लिए होता है, जिसे 'लव सिग्नल' कहते हैं। यह प्रकाश कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। कैंसर रिसर्च में 'बायोल्यूमिनेसेंस इमेजिंग' का अहम रोल है, जिसमें पहले मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिकी जुगनू की प्रजाति फोटिनस पाइरालिस का इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका का दावा था कि केवल यही प्रजाति इस तकनीक पर सबसे ठोस काम करती है। हालांकि, इसी साल गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि भारतीय प्रजाति के जुगनू 'एसिमेट्रिका सरकमडेटा' का भी इस तकनीक में बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। शोधकर्ता ए.जे बोराह व प्रोफेसर ए. गोहैन बरुआ ने इस प्रजाति के जुगनुओं की तरंगदैर्ध्य यानी वेव लेंथ में 9 नैनोमीटर का बदलाव भी दर्ज कराया और बताया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस जुगनू की चमक की अवधि व सीमा तुरंत बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने भारत की पहली जुगनू चेकलिस्ट 2026 तैयार की है, जिसमें 92 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। *जूटैक्सा* जर्नल में प्रकाशित इस सूची के अनुसार, इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। इस सर्वे में पाया गया कि रेगिस्तानी इलाकों में जुगनुओं की एक भी प्रजाति नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इनकी भरमार है। साथ ही, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते प्रकाश प्रदूषण के कारण जुगनू खतरे में हैं। अंत में यह गलतफहमी दूर करना जरूरी है कि जुगनू गोबर में पैदा होता है, गोबर में पैदा होने वाला कीट अलग होता है। यह कुदरत की ऐसी अद्भुत रचना है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत कारगर है।

आंकड़े

भारत में पर्यटक

भारत अपनी समृद्ध सभ्यता, प्राकृतिक विविधता और आध्यात्मिक आकर्षण के बल पर वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।

महाराष्ट्र	37.10
पश्चिम बंगाल	31.20
गुजरात	22.70
उत्तर प्रदेश	22.60
राजस्थान	20.70

आंकड़े भारत में आए विदेशी पर्यटकों के, लाख में। | स्रोत : पर्यटन मंत्रालय

शुक्राचार्य की तपस्या इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। लेकिन वही वरदान आगे चलकर ऐसा संकट बना कि शिव को कठोर निर्णय लेना पड़ा।

भगवान शिव की कृपा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और महान तपस्वी थे। बाल्यकाल में उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के साथ महर्षि अंगिरस के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, पर उन्हें लगा कि आचार्य अंगिरस बृहस्पति की अपेक्षा उनके प्रति समान भाव नहीं रखते। इससे आहत होकर उन्होंने आश्रम छोड़ दिया व महर्षि गौतम की शरण में पहुंचे। गौतम ऋषि ने उन्हें समझाया कि समस्त विद्याओं के वास्तविक स्रोत भगवान शिव हैं। यदि वे शिव की आराधना करेंगे, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा।

इसके बाद शुक्राचार्य गौतमी नदी के तट पर पहुंचे और कठोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक चले उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें मृत-संजीवनी विद्या का वरदान दिया। इस दिव्य विद्या की सहायता से शुक्राचार्य युद्ध में मारे गए दैत्यों को पुनर्जीवित करने लगे।

अंतर्यात्रा
संकलित

अंततः देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी दी हुई विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। यह सुनकर शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। किंतु शिव के भीतर भी शुक्राचार्य का तप व भक्ति अक्षुण्ण रही। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने शरीर से दिव्य तेज के रूप में बाहर आने का अवसर दिया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से —— 3 अगस्त, 1954

गोरखपुर व देवरिया जिलों की नदियों में भीषण बाढ़

गोरखपुर व देवरिया जिलों की नदियों में भीषण बाढ़

अत्यधिक वर्षा होने के कारण गोरखपुर, देवरिया जिलों की नदियों में भारी बाढ़ आ गई है। नारायणी व बड़ी गंडक नदियों का पानी काफी क्षेत्र में फैल गया है। जानवर भारी तादाद में नदी में बह गए। जिलाधिकारी लोगों की सहायता कर रहे हैं।

एक गठबंधन, कई चुनौतियां

आज नाटो एक साथ कई रणनीतिक और राजनीतिक उलझनों से जूझ रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा संकट है गठबंधन की एकता बनाए रखना।

केएस तोमर | **मुद्दा**

नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) अपने 77 साल के इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा को फिर से मजबूत करने, रक्षा पर ज्यादा खर्च करने का वादा करने और यूक्रेन को लगातार समर्थन देने की बात कहकर संगठन ने अपना भरोसा दिखाया। फिर भी, इस गठबंधन के सामने चुनौती अब सिर्फ रूस से नहीं, बल्कि खुद अमेरिका की राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर बनी अनिश्चितता से ज्यादा पैदा हो रही है।

नाटो को बार-बार 'कागजी शेर' कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल उठाया है कि क्या वाशिंगटन को यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना जारी रखना चाहिए, अगर सहयोगी यूरोपीय देश सुरक्षा का ज्यादा बोझ उठाने में नाकाम रहते हैं। हालांकि, अमेरिका नाटो का सबसे जरूरी सैन्य आधार बना हुआ है, लेकिन ट्रंप के बार-बार अमेरिकी प्रतिबद्धता को कम करने की चेतावनी ने यूरोप को ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। हालांकि यह शिखर सम्मेलन सिर्फ यूक्रेन या रक्षा बजट के बारे में नहीं, बल्कि तेजी से बदलती बहुध्रुवीय दुनिया में नाटो की दीर्घकालिक विश्वसनीयता के बारे में था।

आज नाटो एक साथ कई रणनीतिक, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों से जूझ रहा है। पहली चुनौती गठबंधन की एकता बनाए रखना है। जहां पूर्वी यूरोप के सदस्य देश रूस को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, वहीं दक्षिणी यूरोप के कई देशों की प्राथमिकता अवैध प्रवासन, आतंकवाद और उत्तरी अफ्रीका की अस्थिरता है। दूसरी चुनौती जिम्मेदारी बांटने को लेकर है। दशकों से, अमेरिकी सरकारों का कहना है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना पर अत्यधिक निर्भर है। हालांकि, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कई देशों ने रक्षा खर्च में काफी बढ़ोतरी की है, पर अब भी काफी अंतर बना हुआ है। तीसरी चुनौती यूक्रेन को लंबे समय तक समर्थन जारी रखना है। चौथी चुनौती तकनीकी प्रतिस्पर्धा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, अंतरिक्ष सुरक्षा, हाइपरसोनिक हथियार और क्वांटम टेक्नोलॉजी तेजी से सैन्य रणनीतियों को बदल रही हैं। पांचवीं चुनौती सदस्य देशों के भीतर ही राजनीतिक अनिश्चितता है। बढ़ता राष्ट्रवाद, आर्थिक दबाव, सरकारों का बदलना और विदेशों में सैन्य गतिविधियों को लेकर जनता का बढ़ता संदेह समय के साथ गठबंधन की एकता को कमजोर कर सकता है।

नाटो के बदलते स्वरूप से भारत के सामने नए अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखी है और औपचारिक सैन्य गठबंधनों का हिस्सा बनने से बचा है। आज के बंटे हुए भू-राजनैतिक माहौल में भी यह नीति सही साबित होती है। हालांकि, नई दिल्ली को ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा, जहां अमेरिका का रणनीतिक ध्यान यूरोप और हिंद-प्रशांत के बीच बंटता रहता है। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता किए बिना अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय ताकतों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करते रहना चाहिए। रक्षा विनिर्माण बढ़ाना, रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनना, समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और खुफिया सहयोग बढ़ाना भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिए। साथ ही, उसे रूस के साथ बातचीत के स्थिर रास्ते बनाए रखने होंगे और चीन के साथ तेजी से जटिल होते अपने रिश्तों को भी संभालना होगा। हालांकि, नाटो मुख्यतः यूरो-अटलांटिक गठबंधन है, लेकिन इसके निर्णय हिंद-प्रशांत क्षेत्र को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं।

नाटो का भविष्य केवल शिखर सम्मेलन में किए गए वादों पर नहीं, बल्कि ठोस और दीर्घकालिक सुधारों पर निर्भर करेगा। यूरोपीय देशों को रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा। नाटो के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया में भी ज्यादा तेजी लाने और लचीलेपन की जरूरत है। सबसे अहम जरूरत एक ऐसे राजनीतिक भरोसे की है, जो चुनावी बदलावों से प्रभावित न हो।

नाटो शिखर सम्मेलन ने यह दिखाया है कि गठबंधन आज भी सैद्धांतिक रूप से एकजुट है। इस एकजुटता को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावी सैन्य क्षमता और जनता के भरोसे में बदलना ही इसकी असली परीक्षा होगी। आने वाले समय में नाटो दुनिया का सबसे सफल सैन्य गठबंधन बना रहेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी मजबूती से उठाता है और अमेरिका इस गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कितनी दृढ़ता से निभाता है।

अमर उजाला Job Alert
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन

कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों पर रिक्तियां

11403 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 21 अगस्त, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : ibps.in

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ■ 130 पद

सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 10 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : mphc.gov.in

आरसीएफ लिमिटेड में मौके ■ 94 पद

मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 24 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : rcfltd.com

आईआरईएल में आवेदन आमंत्रित ■ 73 पद

एग्जीक्यूटिव के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 10 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : irel.co.in

इसरो एनआरएससी में अवसर ■ 48 पद

रिसर्च साइंटिस्ट व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 21 अगस्त, 2026
योग्यताएं : एमई, एमटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : nrsc.gov.in

एनसीआरटीसी में निकली भर्ती ■ 17 पद

असिस्टेंट मैनेजर व अन्य पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 24 अगस्त, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : ncrtc.co.in

यहां भी रोजगार के अवसर...

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान : आईटी असिस्टेंट के लिए करें आवेदन।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 24 अगस्त, 2026
- niperraebareli.edu.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर : जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर रिक्तियां।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 24 अगस्त, 2026
- erp.iitkgp.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

कॉरपोरेट एथलीट

हार्वर्ड से पढ़ाई कर चुकी हैं। मां से प्रेरणा लेकर हमेशा कुछ नया सीखने की ललक को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती हैं। नई चुनौतियां लेने के जुनून के कारण उन्हें 'कॉरपोरेट एथलीट' कहा जाता है। 'कान खजूरा टेसन' जैसे अभियान की सूत्रधार प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ भी बनी हैं।

पहचान

शख्स
प्रिया नायर
चर्चा
कैंडेर हुरुन इंडिया वूमेन लीडर्स लिस्ट 2026 में 'प्रोफेशनल सीईओ' श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला।
क्यों
हिंदुस्तान यूनिलीवर के 90 साल से ज्यादा लंबे इतिहास में पहली महिला सीईओ बनीं।

2013-14 का दौर। बिहार व झारखंड के सैकड़ों गांवों में घंटों बिजली गायब रहती थी। न टीवी था, न एफएम रेडियो की पहुंच। बड़ी-बड़ी मार्केटिंग रणनीतियां यहां आकर बेअसर हो जाती थीं। लेकिन, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) की मार्केटिंग टीम में एक ऐसी नेतृत्वकर्ता थीं, जिन्होंने गौर किया कि यहां के लगभग हर ग्रामीण की जेब में एक कीपैड फोन जरूर है। बस, इसी सोच से जन्म हुआ ऐतिहासिक विचार 'कान खजूरा टेसन' (कनखजूरा स्टेशन) का। योजना बेहद सरल थी। ग्रामीणों को एक टोल-फ्री नंबर पर मिस कॉल देनी होती थी। कुछ ही सेकंड में उनके फोन पर वापस कॉल आती और गाने, चुटकुले व खेती-बाड़ी संबंधी उपयोगी जानकारी सुनाई जाती। इन्हीं के बीच एचयूएल के उत्पादों के विज्ञापनों का प्रचार भी होता। कुछ ही महीनों में यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा मोबाइल एंटरटेनमेंट चैनल बन गया और विज्ञापन जगत के प्रतिष्ठित कांस लायंस में तीन गोल्डन अवॉर्ड भी जीते। इस सफलता के पीछे का दिमाग था प्रिया नायर का, जो फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वह एचयूएल के 92 साल के इतिहास में पहली महिला सीईओ बनीं और 'कैंडेर हुरुन इंडिया वूमेन लीडर्स लिस्ट-2026' में शीर्ष 'प्रोफेशनल सीईओ' चुनी गईं।

1995 में शुरू हुआ सफर

प्रिया नायर का जन्म 31 मार्च, 1972 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। उनके पिता सुकुमार विश्वनाथ नायर थे, जिनका अब निधन हो चुका है, जबकि उनकी मां डॉ. सुधा सुकुमार नायर पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से बीकॉम और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पुणे से एमबीए किया। 1995 में उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) में अपने कॅरिअर की शुरुआत की और डव, रिन, एक्स व पेप्सोडेंट जैसे ब्रांड्स की मार्केटिंग में अहम भूमिका निभाई। प्रिया ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम को भी पूरा किया है। उनके पति मनमोहन नायर बिजनेसमैन हैं और उनकी एक बेटी, महक है।

फील्ड से सीखी मार्केटिंग की बारीकियां

होम केयर डिवीजन की जिम्मेदारी संभालते हुए प्रिया नायर ने सिर्फ लैब रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया। वह गांवों में जाकर उपभोक्ताओं की जरूरतों और उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों को करीब से समझती थीं, जिसके आधार पर 'कम पानी में ज्यादा सफाई' वाला फॉर्मूला सफल हुआ। उन्हें भारत में फैब्रिक सॉफ्टनर श्रेणी को लोकप्रिय बनाने और 'लक्मे' को डिजिटल जेनरेशन के हिसाब से री-ब्रांड करने का भी श्रेय दिया जाता है।

30 साल का सफर, एक ही कंपनी के साथ

प्रिया नायर ने करीब 30 वर्षों तक हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) में काम किया। एंट्री-लेवल मैनेजर के रूप में शुरुआत कर वह अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के दम पर सीईओ बनीं। वह उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने पर जोर देती हैं, इसलिए उन्हें 'कंज्यूमर फर्स्ट लीडर' कहा जाता है। एचयूएल से पहले वह यूनिलीवर की ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और ब्यूटी एंड वेलबीइंग की ग्लोबल प्रेसिडेंट भी रहीं, जहां उन्होंने अरबों यूरो के कारोबार का नेतृत्व किया।

लंदन का 'कल्चरल शॉक' व भारतीय जड़ें

जब प्रिया यूनिलीवर के वैश्विक मुख्यालय (लंदन) पहुंचीं, तो वहां काम करने का तरीका काफी फॉर्मल और डाटा-ओरिएंटेड था। प्रिया ने 'डाटा विद एम्पैथी' के जरिये अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने बोर्ड मीटिंग्स में सिर्फ ग्राफ दिखाने के बजाय उपभोक्ताओं की असल कहानियां सुनाईं, जिससे उनके फैसले ज्यादा असरदार साबित हुए। उनके सहयोगियों के अनुसार, प्रिया नई-नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां लेने से कभी पीछे नहीं हटतीं, इसलिए उन्हें कई लोग 'कॉरपोरेट एथलीट' भी कहते हैं।

25 साल नौकरी, फिर पढ़ाई

प्रिया नायर 'लाइफलॉन्ग लर्निंग' में गहरा विश्वास रखती हैं। करीब 25 साल कॉरपोरेट जगत में बिताने के बाद भी उन्होंने अपनी मां के प्रोत्साहन पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लीडरशिप प्रोग्राम में दाखिला लिया। दिलचस्प बात यह है कि इसी समय उनकी बेटी भी विश्वविद्यालय में कदम रखने जा रही थीं। उनकी मां आज भी मुंबई में कम शुल्क पर क्लिनिक चलाती हैं, जबकि उनकी बहन टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर सर्जन हैं। प्रिया कई बार कह चुकी हैं कि उनकी मां उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं।

पेंटिंग और सिनेमा की शौकीन

कॉरपोरेट जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद प्रिया नायर को पेंटिंग (चित्रकारी) करना और कैनवास पर रंग बिखेरना बेहद पसंद है। इसके अलावा, वह बिजनेस और लीडरशिप की किताबें पढ़ने और सिनेमा की शौकीन हैं। उन्हें पॉडकास्ट सुनना, खासकर राज शमानी के पसंद है। कला और सिनेमा से प्रिया नायर को इंसानी सोच और कहानियों को समझने में मदद मिलती है, जो मार्केटिंग में काम आती है। कूनूर में उनका पसंदीदा स्थान 'कैफे कॉफी बीन' है।

आज का दिन

3 अगस्त, 1984

मैरी लू रेटन लॉस एंजिल्स ओलंपिक में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक की व्यक्तिगत ऑल-अराउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनीं।

- 1914 : जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
- 1936 : भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का जन्म आजमगढ़ में हुआ था।
- 2007 : अमेरिकी अंतरिक्ष यान फीनिक्स को लॉन्च किया गया था।
- 2022 : भारतीय फिल्म व टीवी कलाकार मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी
कल : वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक

- सूर्योदय : 05.48
- सूर्यास्त : 19.06

(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 13 श्रावण मास शक 1948, श्रावण मास 20 प्रविष्टे, 20 सफर हिजरी 1448, श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी 22.03 तक उपरांत सप्तमी, रेवती नक्षत्र 21.53 तक उपरांत अश्विनी नक्षत्र, धृति योग 19.32 तक उपरांत शूल योग, गर करण 10.28 तक उपरांत वणिज करण, चंद्रमा मेष राशि में 21.53 बजे।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : सहोदरों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। न्याय क्षेत्र में सफलता मिलेगी।

वृष : वाणी पर संयम रखें। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यवसाय विस्तार की योजना बन सकती है।

मिथुन : अचानक कोई उपलब्धि हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है। व्यवसाय में लाभ कम होगा।

कर्क : आत्मबल बना रहेगा। संतान से सुख मिलेगा। नौकरी में धैर्य बनाए रखें। आर्थिक दबाव में कमी आएगी।

सिंह : लक्ष्य प्राप्ति में सफल रहेंगे। बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा।

कन्या : धैर्य बनाए रखें। योजना में सामान्य विलंब संभव है। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें।

तुला : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में कार्य कुशलता बनी रहेगी। विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें।

वृश्चिक : भाग्य सहायक रहेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। उतावलेपन पर नियंत्रण रखें।

धनु : पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में सावधानी बरतें। व्यवसाय में लाभ होगा।

मकर : मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में कुशल प्रबंधन का लाभ मिलेगा। विरोधी नतमस्तक रहेंगे।

कुंभ : स्वजनों से मतभेद बने रहेंगे। नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

मीन : मान प्रतिष्ठा को नया आकार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे।

सुडोकू

				4		3		
5	2			8	6			
			2		1		5	
2						6		
7			4	2	9			8
		5						7
	6		8		2			
			7	6			4	9
		9		1				

उत्तर

1	8	7	9	4	5	3	6	2
5	2	4	3	8	6	9	7	1
6	9	3	2	7	1	8	5	4
2	4	8	1	5	7	6	9	3
7	3	6	4	2	9	5	1	8
9	1	5	6	3	8	4	2	7
4	6	1	8	9	2	7	3	5
8	5	2	7	6	3	1	4	9
3	7	9	5	1	4	2	8	6

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे है और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

देश-दुनिया

न्यूज डायरी

झारखंड में बिजली गिरने से 5 महिलाओं की मौत

रामगढ़/गोड्डा। झारखंड के रामगढ़ और गोड्डा जिलों में रविवार को बिजली गिरने से पांच महिलाओं की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुई हैं। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रामगढ़ के पतरातू ब्लॉक में तीन और गोड्डा जिले के बसंतराय ब्लॉक में दो मौतें हुई हैं। ये सभी महिलाएं धान की बुआई कर रही थीं। आकाशकीय बिजली की चपेट में आने से झुलसी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एजेंसी

ड्रोन से पहुंची 10 किलो हेरोइन व हथियार जब्त

जयपुर। राजस्थान के बीकानेर जिले में पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये भेजी गई 10 किलो हेरोइन, 11 विदेशी हथियार और बड़ी मात्रा में कारतूस की खेप जब्त कर ली है। अधिकारियों ने बताया इस मामले में शनिवार देर रात खेप लेने पहुंचे एक संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। जब्त की गई खेप की कीमत करोड़ों रुपये है। बरामद हेरोइन का संबंध अफगानिस्तान से है और इसे पंजाब पहुंचाया जाना था। ब्यूरो

एसीएफ की संदिग्ध मौत पर डीएफओ निलंबित

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) सौम्य रंजन महापात्रा की संदिग्ध मौत मामले में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) संग्राम केसरी बेहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बेहरा वर्तमान में ओडिशा वन विकास निगम (ओएफडीसी) में निदेशक (व्यापार) के पद पर तैनात थे। मामला जुलाई 2021 का है। एजेंसी

केरल : आठ किलो सोना जब्त, 9 तस्कर गिरफ्तार

कोच्चि। केरल के विभिन्न हवाईअड्डों पर सीमा शुल्क विभाग ने एक सप्ताह में तस्करी कर लाया गया आठ किलो सोना जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत 11 करोड़ रुपये से अधिक है। आयुक्त टी. तिजू ने रविवार को बताया कि इस अवधि में कुल 14 मामले दर्ज किए और नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में 6 केरल व 3 तमिलनाडु के निवासी हैं। एजेंसी

बिहार : कानून-व्यवस्था पर फिर सवाल

सरकारी अफसर को पीट-पीटकर मार डाला, ड्राइवर गिरफ्तार

पत्नी ने हत्या में विधायक सोनू सिंह का हाथ बताया | राज्य भर में ईओ का काम ठप, हड़ताल का एलान | पुलिस अन्य हमलावरों की तलाश के लिए मार रही छापे

अमर उजाला ब्यूरो

पटना। बिहार में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की अज्ञात अपराधियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी।

यह वारदात औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में शनिवार की रात घटी जब वे डेहरी से पटना आ रहे थे। इस मामले की जांच करने पहुंचे मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि कार्यपालक अधिकारी के ड्राइवर ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मृतका की पत्नी ने डेहरी के लोजपा (रामविलास) विधायक सोनू सिंह पर आरोप लगाया है कि विधायक बार-बार ही मेरे पति से पैसे की मांग कर रहे थे। इसमें विधायक का भी हाथ है। घटना से अधिकारियों में गहरा रोष है। घटना के विरोध में बिहारभर के कार्यपालक पदाधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। ईओ संघ ने तत्काल प्रभाव से कामकाज ठप कर हड़ताल की घोषणा कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा से जुड़ी मांगें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। गुस्साए अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है।

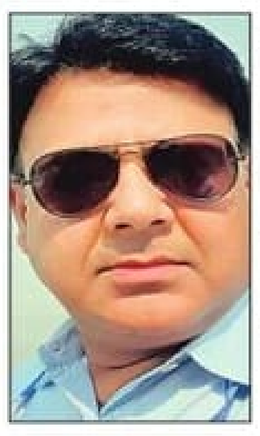

ईओ विमल कुमार का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते परिवारीजन व ईओ संघ के पदाधिकारी।

शव लेकर सीएम आवास तक पहुंचे, किया प्रदर्शन

विमल का शव जैसे ही दानापुर पहुंचा, बिहार अर्बन सर्विस एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में जुट गए। एंबुलेंस से शव लेकर वे मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हो गए, जहां सुरक्षा और कार्रवाई की मांग को लेकर दबाव बनाया गया।

शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने थाने में खाया जहर, मौत

छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में सल्फास खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित की पहचान लहेरा पुरवा गांव निवासी राजकुमार कुशवाहा (35) के रूप में हुई है। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने जमीन विवाद से जुड़ी उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर राजकुमार ने जहर खा लिया। पिछले दो दिनों में यह दूसरी घटना है, जिसमें किसी व्यक्ति ने थाना परिसर में जहर खा लिया।

पुलिस के अनुसार, राजकुमार का पैतृक संपत्ति को लेकर अपने बड़े भाई और अन्य रिश्तेदारों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई को एहतियाती कार्रवाई शुरू की गई थी। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि राजकुमार शनिवार शाम अपने बेटे और बेटी के साथ नौगांव पुलिस थाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी गाड़ी से कोई चीज निकाली और उसे खा लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। यह घटना थाने के सीसीटीवी में कैद हो गई। एसपी ने बताया कि राजकुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो

सिंधु जल समझौते पर भारत की दो टूक

पहले आतंकवाद खत्म करे पाकिस्तान, तब होगी बात

नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। क्वात्रा ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला पाकिस्तान के व्यवहार की वजह से लिया है। उन्होंने कहा कि जिस सद्भावना और दोस्ती की भावना के साथ 1960 में यह संधि हुई थी, पाकिस्तान ने पिछले 50 वर्षों में उसी भावना को खत्म कर दिया।

सिंधु जल समझौते पर अपने पड़ोसी मुल्क को सख्त संदेश देते हुए क्वात्रा ने कहा कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक में लिखे लेख में क्वात्रा ने कहा, भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का कदम उठाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय राजदूत ने कहा, यह 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अगर पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे पर सहयोग चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। उन्होंने पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, पानी और खून साथ नहीं बह सकते। ब्यूरो

मनमानी पर एफएसएसएआई ने भेजा नोटिस

शराब में अतिरिक्त फ्लेवर पर 11 कंपनियों पर शिकंजा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनब्रू बेवरेजेज एवं एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज सहित 11 शराब निर्माताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें महाराष्ट्र की छह और गोवा की एक कंपनी शामिल है।

आरोप है कि इन सभी कंपनियों ने ऐसे अतिरिक्त फ्लेवर का इस्तेमाल किया जो उत्पादों के प्राकृतिक स्वाद और खुशबू की नकल करते हैं, जबकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते। कंपनियां शराब की उम्र से जुड़े भ्रामक दावे भी कर रही थीं। खाद्य सुरक्षा नियामक ने स्पष्ट किया कि रम, ब्रांडी, जिन, माल्ट/ग्रेन व्हिस्की, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में केवल उनका प्राकृतिक स्वाद और सुगंध होनी चाहिए। कृत्रिम रूप से उसी स्वाद की नकल करने वाले फ्लेवर मिलाना खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2018 का उल्लंघन है। एफएसएसएआई ने 10 जुलाई को भी शराब कंपनियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उस समय नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे।

पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश...क्रू सदस्य समेत 13 की मौत

लीमा। पेरू के नाज्का शहर के पास एक टूरिस्ट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 11 यूरोपीय पर्यटकों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। विमान के पायलट और को-पायलट की भी जान चली गई। यह विमान इका शहर से उड़ान भरकर पर्यटकों को 2000 साल पुरानी नाज्का लाइन्स दिखाने जा रहा था। एजेंसी

नौसेना को मिला एक और पोत, बढ़ेगी ताकत

कोलकाता। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए कोलकाता में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (डीएससी) प्रोजेक्ट के पांचवें जहाज डीएससी ए24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को एक और बड़ी मजबूती देता है। जहाज का निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लि. (टीआरएसएल) ने किया है। लॉन्चिंग समारोह में नौसेना के कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ब्यूरो

रांची में लगातार 5वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन, निकाला मशाल जुलूस

जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रविवार को लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। रविवार शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्र 29 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और मामले की सीबीआई जांच के साथ भर्ती एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। एजेंसी

प्रदर्शनकारी छात्रों का मुकदमा वापस लेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के विरुद्ध दर्ज केस वापस लेगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा, यह फैसला मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मिले निर्देशों के बाद लिया गया है।

राजमोहन ने सोशल मीडिया में लिखा, सीएम के निर्देशानुसार नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही दी जाएगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया, जब सरकार को नीट-विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर कुछ वर्गों से आलोचना झेलनी पड़ी। इन प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के बाद आंदोलन किया था। एजेंसी

आज पेश होंगे सांख्यिकी संस्थान और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल

लोकसभा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पेश करेगी। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बयान भी सदन के पटल पर रखेंगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) से जुड़े कामकाज, उसकी शक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा आधुनिक बनाने के लिए लाया जा रहा है। वहीं, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल से अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड को वैध सबूत के रूप में पेश करना और आसान तथा सुरक्षित हो जाएगा। इससे वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से सुनवाई होगी। ब्यूरो

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बेटियों का कमाल

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन हर्षित करने वाला तो है ही, यह भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें भी देता है। पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत उस स्थिति में खड़ा है, जब भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे वाले कई खेल इस बार के आयोजन में शामिल ही नहीं किए गए थे। बावजूद इसके भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो में तिरंगे को बार-बार शिखर पर पहुंचाया और 140 करोड़ से अधिक देशवासियों को गौरवान्वित किया। हमारे खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और जूडो में शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि पहली बार बॉक्सिंग में सात स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे अहम बात यह है कि बेटियों ने स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी। मीरा बाई चानू से जो शुरुआत हुई, तो फिर इस कतार में शर्मिला, अस्मिता, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया धंधास, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन जैसे नाम जुड़ते चले गए। अब ये सिर्फ नाम नहीं हैं, देश की हजारों-लाखों बेटियों की प्रेरणा-स्रोत हैं। इनमें से एकाधिक लड़कियां तो बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आई हैं। उनका सबसे ऊंचे पोडियम पर खड़ा होना खास गौरवशाली है। वे न सिर्फ अपने जैसी अनगिनत प्रतिभाओं को प्रेरित करेंगी, बल्कि हमारे खेल से जुड़े कर्ता-धर्ताओं को और उत्साहित करेंगी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दें।

इसमें कोई दोराय नहीं कि बीते कुछ वर्षों में देश में खेल-संस्कृति का तेजी से विकास हुआ है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी दिलचस्पी और 'खेलो इंडिया' जैसे कार्यक्रमों का इसमें अहम योगदान है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश भी बढ़ा है और बड़े पैमाने पर युवा अब इसे करियर के तौर पर अपनाने लगे हैं। हालांकि, इस संस्कृति के निर्माण में क्रिकेट का सबसे बड़ा योगदान है। आईपीएल की शुरुआत ने देश के छोटे-छोटे शहरों को कई सितारे दिए और उन पर पैसों की बरसात ने समाज की पूरी मनोदशा बदल दी। परिवार अवरोधक के बजाय सहायक की भूमिका में आने लगे। सबसे बड़ा बदलाव तो लड़कियों के मामले में आया है। पहले बेटियों के लिए खेल-क्षेत्र में बहुत बाधाएं थीं, मगर अब वे भी सपने देख रही हैं और उनको साकार कर रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका उनकी प्रतिभा और जिजीविषा की कहानी खुद कह रही है।

राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका भारतीय लड़कियों की अप्रतिम प्रतिभा और जिजीविषा की कहानी खुद-ब-खुद कह रही है। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता।

इस बड़े बदलाव का एक पहलू यह भी है कि अब भी हिंदी हृदयस्थल के सूबों से एथलेटिक्स में उतने खिलाड़ी उभरकर सामने नहीं आ रहे, जितने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, असम और मणिपुर जैसे प्रदेशों से निकल रहे हैं और यह बात इन राज्य सरकारों को चुनौती के रूप में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन राज्यों के पास प्रतिभाएं नहीं हैं। झारखंड ने क्रिकेट से इतर हॉकी, तीरंदाजी आदि खेल विधाओं में कई राष्ट्रीय सितारे दिए हैं। राज्य अगर खेल-संस्कृति को प्रोत्साहन दे, तो वहां से कई नए नाम देश को मिल सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश को खेलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा शॉटपुट में बिहार के सोमन राणा का स्वर्ण पदक इस बात का सुबूत है कि अगर सही तलाश की जाए, तो इन दोनों सूबों के पास ऐसे युवाओं की कोई कमी नहीं, जो वैश्विक खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में देश-प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें। अगले राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होने वाले हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 2010 कॉमनवेल्थ खेलों की पदक संख्या से आगे निकल सकें। फिलहाल देश अपनी उन बेटियों के स्वागत की तैयारी करे, जिन्होंने ग्लासगो में भारत का परचम बुलंद किया है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 03 अगस्त, 1951

निर्यात नीति

भारत सरकार के उद्योग और व्यापार मंत्री श्री हरेकृष्ण मेहताब ने निर्यात सलाहकार कौंसिल के सामने भारत सरकार की निर्यात नीति पर विशद प्रकाश डाला है। प्रत्येक देश को आयात और निर्यात करना होता है। यदि कोई देश आयात अधिक करता है और निर्यात कम तो व्यापारिक दृष्टि से उसकी स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती है। उसे अपने आयात का मूल्य चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी पड़ जायेगी जो निर्यात द्वारा अर्जित की जाती है। इसलिए प्रत्येक देश का आयात और निर्यात कम से कम संतुलित अवश्य होना चाहिए।

इस देश में रुपये का अवमूल्यन किया गया, उसके पहले हमारा निर्यात सन्तोषजनक परिमाण में नहीं हो रहा था। हम आयात अधिक कर रहे थे और निर्यात कम; और इस कारण हमने अपने पौण्ड पावने की संचित राशि का बहुत-सा भाग खर्च कर डाला। हमारे रुपये का अवमूल्यन होने के बाद हमारे निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन मिला। विदेशी बाजारों में हमारे माल की मांग काफी बढ़ गयी और हम विदेशी मुद्रा के अपने संचित कोष को बढ़ा पायें। निर्यात की मात्रा बढ़ने का यह कारण तो था ही कि मूल्य की दृष्टि से हमारा माल अन्य देशों की सफल प्रतिद्वन्द्विता करने में समर्थ था। इसके अतिरिक्त कोरिया में युद्ध छिड़ जाने के कारण दुनिया के देशों ने माल संग्रह करना प्रारंभ किया और भारतीय माल की मांग बढ़ गयी। ... कोरिया में युद्धबन्दी की संभावना के फलस्वरूप विदेशी मंडियों में वस्तुओं के भाव गिरे हैं। हमको विदेशी बाजारों की स्थिति पर सतत निगाह रखनी होगी और अपने माल की कीमत ऐसे स्तर पर रखने की कोशिश करनी होगी कि हमारे माल की मांग विदेशी बाजारों में बनी रहे और हमारे निर्यात की मात्रा में उल्लेखनीय कमी न हो। जो निर्यात-कर वसूल किया जाता है, उसका मूल्य-स्तर पर काफी असर पड़ता है। हमारे निर्यात व्यापार के हित में आवश्यक होने पर सरकार निर्यात-करों में उचित संशोधन करने के लिए प्रस्तुत रहेगी, ऐसी आशा की जा सकती है।

सरकार को अपनी निर्यात-नीति स्थिर करने में एक और बात का खयाल रखना पड़ता है। देश के भीतर जो माल उत्पादन होता है, उसका हम अंधाधुंध निर्यात नहीं कर सकते। यदि निर्यात अनियंत्रित हो तो देश के आर्थिक जीवन में संकट पैदा हो सकता है।

बड़े काम के होंगे छोटे प्लास्टिक नोट

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अनेक ऐसे देश पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम और पर्यावरण भारत जैसे हैं। हमारे पड़ोस में भी ये प्रचलित हैं।

अब चलेंगे प्लास्टिक के नोट। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है कि दस और बीस रुपये के सौ-सौ करोड़ प्लास्टिक के नोट छापे जाएं। इन नोटों के आने के साथ ही भारत की मुद्रा व्यवस्था में एक नए दौर की शुरुआत हो जाएगी।

हालांकि, यह नया विचार नहीं है। इस पर पहले से ही काम चल रहा है और 2010-12 के दौरान तो रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, शिमला, कोच्चि, मैसूर, भुवनेश्वर और जयपुर सहित कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में दस रुपये के ऐसे नोटों को परीक्षण के तौर पर चलाकर भी देखा था। पता चला है कि तब कुछ शिकायतें मिली थीं। इनमें ज्यादा गर्मी से इन नोटों के सिकुड़ने या चिपकने की आशंका थी और एटीएम या नोट गिनने वाली मशीनों में इन नोटों के लिए जरूरी इंतजाम की कमी भी। नोटों की लागत भी एक समस्या लग रही थी। हालांकि, रिजर्व बैंक की तरफ से इस परीक्षण की कोई ऐसी रिपोर्ट या समस्याओं की सूची सामने नहीं आई। अब काफी अध्ययन और तैयारी के बाद बड़े पैमाने पर ट्रायल की योजना सामने रखी गई है।

यहां प्लास्टिक शब्द का इस्तेमाल भ्रामक हो सकता है, क्योंकि मुद्रा या खर्च के संदर्भ में प्लास्टिक का अर्थ अभी तक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे भुगतान के तरीके ही माने जाते रहे हैं। यहां जिन करेंसी नोटों का जिक्र हो रहा है, वे रासायनिक तौर पर भी प्लास्टिक के नहीं, बल्कि एक खास किस्म के पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिमर से बने नोट होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलिमर नोट कहना बेहतर होगा। ये नोट बेहद उन्नत और बारीक तकनीक से तैयार होते हैं, जिसके कारण इनको बहुत मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ माना जाता है।

बहुत से देशों में ये नोट सफलतापूर्वक चल भी रहे हैं। इनमें भारत के पड़ोसी भूटान और मालदीव जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अनेक ऐसे देश पॉलिमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम और पर्यावरण भारत जैसे हैं। असल में, नए पॉलिमर नोट पर विशेष कोटिंग होती है, जिससे ये आसानी से आपस में चिपकते नहीं हैं और इनकी सतह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।

इस दौरान बैंकिंग कारोबार में भी काफी तरक्की हो चुकी है और नए एटीएम, पैसा जमा करने वाली मशीनें, करेंसी गिनने व छांटनेवाली मशीनें भी पॉलिमर नोटों को पहचानने, गिनने और छांटने के काम कर सकती हैं। यानी, पिछले पायलट प्रोजेक्ट के सामने जो अड़चनें आईं, उनमें से ज्यादातर अब दूर हो चुकी हैं। जाहिर है, अगर भारत बड़े पैमाने पर इन नोटों को अपनाता है, तो फिर बैंकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, उसके लिए वक्त है, क्योंकि अभी जो दस और बीस रुपये वाले नोट जारी होने हैं, वे एटीएम में नहीं डाले जाते।

पॉलिमर नोटों की सबसे बड़ी खासियत उनकी लंबी उम्र, यानी टिकाऊपन है। खासकर, छोटे नोट, जैसे दस और बीस रुपये वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या फिर धूल, पसीने व नमी से खराब हो जाते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश में दस-बीस रुपये के नोटों की औसत उम्र काफी कम हो जाती है। पॉलिमर नोट कागज के नोटों के मुकाबले ढाई से चार गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये नोट अगर कुछ महंगे भी पड़ते हैं, तब भी सरकार और रिजर्व बैंक का खर्च आखिरकार कम हो जाएगा, क्योंकि नए नोट छापने की जरूरत धीरे-धीरे कम होने लगेगी।

पॉलिमर नोटों का एक और बड़ा फायदा है नकली नोटों से मुकाबला। अभी छोटे नोटों का परीक्षण है, जिसमें नकली नोटों की समस्या कम होती है, पर पॉलिमर नोटों में कुछ हिस्सा एकदम खिड़की की तरह पारदर्शी हो जाता है। इनमें काफी पेचीदा 'होलोग्राफिक इफेक्ट' इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्नत किस्म की सुरक्षा के लिए ऑप्टिकल और दूसरे तत्व भी काफी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे नोटों की नकल करना कागजी नोटों के मुकाबले काफी मुश्किल है और महंगा भी।

अब एक बड़ा सवाल उठता है कि पॉलिमर नोट अपनाना क्या पर्यावरण के साथ छल नहीं होगा? इसके दो अहम पहलू हैं। एक तो यह कि कागज के नोट भी पर्यावरण के लिए खास लाभदायक नहीं हैं। कागज के लिए पेड़ों की बलि देनी पड़ती है। दूसरे, पॉलिमर नोट क्योंकि लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत कम नोट छापने से गुजारा हो जाएगा। पॉलिथीन के बेरोकटोक फैलाव जैसा डर भी नहीं है, क्योंकि नोट की कीमत इतनी होती है कि लोग इसे संभालकर ही रखेंगे। इनकी 'रीसाइक्लिंग' भी की जा सकती है। हालांकि, प्लास्टिक के इस्तेमाल से जुड़ी आशंकाएं बेबुनियाद नहीं हैं, मगर तमीज से इनका इस्तेमाल हो और रिजर्व बैंक इनकी रीसाइक्लिंग का पक्का इंतजाम करे, तो फिर पर्यावरण को होने वाला नुकसान शायद कागज के नोटों के मुकाबले कम हो सकता है।

सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सन् 1988 में पहला पूर्ण पॉलिमर नोट जारी किया था। उसका अनुभव काफी सफल माना जाता है। उसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे देशों ने ही नहीं, बल्कि ब्रुनेई, वियतनाम, रोमानिया, नाइजीरिया, चिली, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी और निकारागुआ ने भी आंशिक या पूरी तरह पॉलिमर नोट इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान भी इनको आजमाने की राह पर है।

पिछले वित्त वर्ष के आखिर में भारत में 41 लाख, 68 हजार करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलन में थी। अभी जो पॉलिमर नोट छापे जाने का प्रस्ताव है, उसमें कुल तीन हजार करोड़ रुपये के नोट छपेंगे। रिजर्व बैंक यह नहीं बताता है कि अलग-अलग मूल्य के नोटों को छापने पर उसका कितना खर्च होता है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में करेंसी नोट छापने पर कुल 4,875 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशों और इसमें मिली अपार सफलता के बाद भी नोटबंदी से अब तक करेंसी में करीब ढाई गुना बढ़त क्या कहती है?

जो भी हो, बदलती दुनिया और बदलते वक्त के साथ चलने के लिए जरूरी है कि भारत इस मोर्चे पर गंभीरता से विचार करे, ठोक-पीटकर परीक्षण करे और फिर चरणबद्ध तरीके से बदलाव पर काम करे। ऐसा हुआ, तो उम्मीद है कि जल्द ही पॉलिमर नोट आपकी अपनी जेब में भी होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जेन-अल्फा की शिकायतों से आंखें फेरना गलत होगा

यहां स्कैन करें

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

देश में जेन-जी आंदोलन की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि खबर आई कि जेन-अल्फा (2010-2024 तक जन्मे) के बच्चे अब मैदान में आ गए हैं। ये 21वीं सदी के सूचना-समाज के बच्चे हैं। दुनिया भर की खबरें मोबाइल, टीवी के जरिये देखते हैं। इनके बारे में अब मजाक किया जाने लगा है कि ये तो मोबाइल हाथ में ही लेकर पैदा हुए हैं। जेन-जी के आंदोलन से इन्हें लगा कि वह शासन को झुका सकती है, तो हम क्यों नहीं? इसीलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब आंदोलन करने लगे हैं।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सरकारी इंटर कॉलेज की कक्षा छह से लेकर 12 तक के करीब 1,500 बच्चे अपने संस्थान के सामने धरने पर बैठ गए। उनकी यह शिकायत थी कि कॉलेज में उन्हें मामूली सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों की मांग थी कि बिजली रहे, टूटे पंखे ठीक किए जाएं। स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो। कक्षा के लिए पर्याप्त कमरे हों। पीने को साफ पानी मिले। खेल सुविधाएं हों। कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया। इसमें उसे छह घंटे लगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कुछ बड़े बच्चों ने, जो हालिया जेन-जी आंदोलन में शामिल हुए थे, इसे शुरू किया।

फतेहपुर में इंटर कॉलेज के बच्चे जिन बातों के लिए सड़क पर उतर आए, क्या वे चीजें इतनी बड़ी थीं, जो उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही थीं?

जालौर और बाड़मेर, राजस्थान में भी स्कूली बच्चों ने विरोध-प्रदर्शन किए। जालौर में उन्होंने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। उनकी शिकायत थी कि प्राइमरी कक्षाओं में अध्यापकों की कमी है। बाड़मेर के बच्चों की भी यही मांग थी। उनका कहना था कि न जाने कब से कई विषयों के अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, इसलिए उनकी ढंग से पढ़ाई ही नहीं हो पा रही। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी भाग लिया। सरकार ने बच्चों की मांगों पर ध्यान देते हुए 80 स्कूलों में, जहां अध्यापकों की कमी थी, फौरन अध्यापक नियुक्त किए।

बिहार के गया में एक स्कूल के दर्जनों बच्चे एसडीएम के दफ्तर तक बाकायदा जुलूस लेकर निकल पड़े। वे स्कूल में चापाकल खराब होने, शौचालय की साफ-सफाई और विद्यालय में खेल के उपकरणों की कमी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। एसडीएम ने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की और निर्देश दिया कि पांच दिनों में बच्चों की सारी मांगें पूरी की जाएं। कर्नाटक में बच्चों ने चार घंटे तक राजमार्ग को जाम कर दिया था, क्योंकि वहां सरकारी बसें उनके गांव के बस स्टॉप पर न रुककर, कहीं दूर रुका करती थीं, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते थे।

ध्यान से देखें, तो बच्चे जिन सुविधाओं के लिए आंदोलित हैं, वे उन्हें मिलनी ही चाहिए। आखिर वे क्यों नहीं उन्हें मिलतीं? यदि स्कूलों में साफ पानी, पर्याप्त कक्ष, खेलने के मैदान व उपकरण व अध्यापक ही नहीं होंगे, तो वे क्या करेंगे? स्कूल प्रशासन व अधिकारी तब तक ध्यान क्यों नहीं देते, जब तक कि शिकायत न हो या बच्चे अपना गुस्सा प्रदर्शित न करने लगें?

अक्सर यह शिकायत की जाती है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उनमें बच्चे आते ही नहीं। जाएं भी तो कैसे, यदि उनमें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं? सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा सस्ती है, हालांकि उनमें पढ़ाने वाले नियमित अध्यापक-अध्यापिकाओं के वेतन ठीकठाक हैं। इनके मुकाबले निजी स्कूलों में शिक्षा महंगी है, पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के वेतन सरकारी स्कूलों से कम है। विडंबना देखिए, जहां वेतन ज्यादा है, वहां से शिक्षकों की शिकायतें आती रहती हैं कि उनमें से कई स्कूल ही नहीं आते, अपने दायित्व को 'आउटसोर्स' कर देते हैं या जो विषय वे पढ़ाने आए हैं, वही उन्हें नहीं आता। निजी स्कूलों में ऐसा संभव नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि अध्यापकों की भर्ती करते समय वह योग्यता की बहुस्तरीय परख करे, ताकि शिक्षक अपने विषय तो पढ़ा सकें। समय पर स्कूल आ सकें।

गौर करने की बात है कि जेन-अल्फा के बच्चे उस उम्र के हैं, जहां 'एडवेंचर' बहुत भाता है। मान लीजिए, धरना-प्रदर्शन करते ये कुछ ऐसा कर बैठें, जिससे इनकी जान को खतरा पैदा हो जाए अथवा किसी और को नुकसान पहुंचे, तब क्या होगा? इन दिनों राजनीति के बड़े खिलाड़ी इन्हें भड़का रहे हैं और इन्हें भी औरों की तरह उकसा रहे हैं कि वे सड़क पर आ जाएं। इसलिए इन नौनिहालों को स्कूल के अहाते में पढ़ने के लिए माकूल सुविधाएं मुहैया कराना बहुत जरूरी है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सफलता का असली अर्थ

बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा को लेकर देश में बड़ी उथल-पुथल मची है। इसी मंथन से नया ढांचा तैयार होगा। अब तक हम बड़े आत्म-संतुष्ट थे कि हमारी शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके जो परिणाम निकल रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि कहीं कोई बुनियादी चूक है, अन्यथा इतना असंतुष्ट नई पीढ़ी तैयार नहीं होती। सवाल है, युवाओं में इतना आक्रोश कहां से आता है?

ओशो स्वयं एक शिक्षक थे और उन्होंने उस समय भी शिक्षा की स्थिति से व्यथित होकर आमूल-चूल बदलाव के सुझाव दिए थे। आज भी वे उतने ही मौजूं हैं, जितने उस समय थे, क्योंकि समाज में कुछ भी नहीं बदला है। ओशो कहते हैं कि महत्वाकांक्षा से बड़ा दूसरा कोई जहर नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा के सिवाय हम और क्या सिखाते हैं? पहले ही वर्ष से बच्चों को हम आगे निकलने की होड़ सिखाते हैं। प्रतिस्पर्द्धा में प्रथम आना। ये उपदेश बड़े मीठे मालूम पड़ते हैं, पर प्रथम आने की दौड़ मनुष्य को विक्षिप्त करती रही है, यह हमें ख्याल भी नहीं है। मनुष्य के मन को महत्वाकांक्षा कहां पहुंचाती है? जब कोई व्यक्ति प्रथम आने की कोशिश में लगा होता है, तब वह प्रथम आने की खुशी नहीं होती, बल्कि वह दूसरों को दुखी करने का सुख होता है। जो पीछे छूट गए हैं और जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, उन्हीं से वह मुस्कराहट निर्मित होती है, जो प्रथम आने वाले की थी।

महत्वाकांक्षा इसलिए अनिवार्य रूप से हिंसा सिखाती है। वह हिंसा का गहरे से गहरा परिणाम है। ऊपर से दिखाते हैं सब कि दोस्त हैं, लेकिन अंदर से सभी दुश्मन मालूम होते हैं, और फिर जब एक बार युवा होते-होते तक चित्त इसमें दीक्षित हो जाता है, तो फिर जीवन भर इसी दौड़ में दौड़ता है। फिर किनके कंधों पर पैर रखने पड़ते हैं, किनकी लाशों को सीढ़ियां बनानी पड़ती है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे हर बीज फूल बनने के लिए पैदा होता है, ठीक उसी तरह हर व्यक्ति अपने गुणों की खिलावट के लिए पैदा होता है। अपनी संभावनाओं को वास्तविक करने के लिए पैदा होता है। इसलिए दो बच्चों की तुलना करना बंद करें। तुलना बहुत घातक है। यह बच्चे के आत्म-विश्वास को कमजोर कर देती है। यहां हरेक मनुष्य अनूठा है, कोई इंसान दूसरे जैसा हो भी नहीं सकता।

हमेशा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करके ही सफलता नहीं मिलती। असली विकास तो तब होता है, जब स्वयं के साथ स्पर्द्धा करें कि मन रोज-रोज नया हो जाए, सुबह का सूरज हमें नया देखे।

इसके विपरीत, सीखना इसलिए भी हो सकता है कि बच्चों को उसमें आनंद आए। गणित कोई इसलिए सीखे कि गणित सीखना उसका आनंद है। कोई काव्य इसलिए सीखे कि काव्य करने में उसे आनंद आता है। *स्वांतः सुखाय।* हमेशा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करके ही सफलता नहीं मिलती। असली विकास तो तब होता है, जब स्वयं के साथ स्पर्द्धा करें कि मन रोज-रोज नया हो जाए, सुबह का सूरज हमें बिल्कुल नया दिखे।

अमृत साधना

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

जो बस्तर कभी नक्सली हिंसा के कारण अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति व परंपराओं को खोता जा रहा था, वह आज नक्सल मुक्त होकर अपनी धरोहरों को सहेज रहा है।... आने वाले वर्षों में यह छत्तीसगढ़ में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

अनुलोम-विलोम

सारनाथ

विश्व धरोहर बनने से और बढ़ेगा मान

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ का शामिल होना भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यही वह स्थान है, जहां से बौद्ध धर्म का व्यवस्थित प्रचार-प्रसार प्रारंभ हुआ। सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप, अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूप, प्राचीन विहारों के अवशेष और पुरातात्विक संग्रहालय विश्व भर के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं व श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। यूनेस्को द्वारा इस स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाना भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की साझा सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता मिलना है।

विश्व धरोहर सूची में किसी भी स्थल का चयन उसकी असाधारण सार्वभौमिक महत्ता के आधार पर किया जाता है। इसके लिए उस स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य, धार्मिक अथवा प्राकृतिक विशिष्टता का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। किसी स्थल के चयन के बाद उसके संरक्षण, रखरखाव व प्रबंधन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। जहां तक भारत की बात है, तो यह देश सांस्कृतिक विरासतों का धनी है। यही कारण है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का स्थान विश्व के अग्रणी देशों में है। सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। इन तीर्थ स्थलों को जोड़कर पर्यटन का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जा सकता है। इससे भारत आने वाले बौद्ध देशों- श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया के श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी नई शक्ति मिलेगी। यह उपलब्धि भारत की बौद्ध विरासत को विश्व मंच पर कहीं अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेगी। इसके साथ ही *वसुधैव कुटुम्बकम्* और शांति, करुणा और अहिंसा के भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। यह एक ऐतिहासिक स्थल की नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत व मानव सभ्यता को सम्मानित करने जैसा है। निस्संदेह, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का समय है।

सत्यभामा सिंह, गृहिणी

केवल दर्जा मिलने से कुछ नहीं होगा

सारनाथ को विश्व धरोहर का हिस्सा बनाना सुखद है, लेकिन सिर्फ धरोहर बनने से क्या किसी स्मारक की बदहाली दूर हो सकती है? सारनाथ को शामिल कर लें, तो फिलहाल देश में 45 विश्व धरोहर स्मारक हैं। इनमें से चार तो अकेले उत्तर प्रदेश में हैं- ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के साथ अब सारनाथ। अब इन स्मारकों की दशा क्या है, यह कोई छिपा रहस्य नहीं है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है।

भारत में विश्व धरोहरों की बदहाली का मुख्य कारण अतिक्रमण, प्रदूषण और कमजोर रखरखाव है। प्रशासनिक लापरवाही और बढ़ती भीड़ के कारण तो कई ऐतिहासिक स्थल खतरे में हैं। संरक्षित क्षेत्रों के आसपास नियमों को ताक पर रखकर गैर-कानूनी इमारतें बनाई जा रही हैं। हवा और पानी के प्रदूषण से ऐतिहासिक पत्थरों और कलाकृतियों का मूल स्वरूप बिगड़ रहा है। स्मारकों के पास बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। यहां आने वाले घरेलू पर्यटकों द्वारा ठोस नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

यकीन न हो, तो कर्नाटक घूम आइए। वहां हम्पी की धरोहर अवैध निर्माण, अनियोजित पर्यटन विकास और सुरक्षा की कमी के कारण गंभीर बदहाली का सामना कर रही है। संरक्षित क्षेत्र के पास बिना अनुमति के चल रहे व्यावसायिक रिसॉर्ट और निर्माण-कार्य बड़ी समस्या हैं। इसके साथ असामाजिक गतिविधियों से भी इन स्थलों को जूझना पड़ता है। यहां के मंदिरों और स्तंभों को उपद्रवियों द्वारा नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी हुई हैं। अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों से धरोहर के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। गौरतलब है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार के बाद आक्रांताओं ने राजधानी को पांच महीने तक लूटा और तहस-नहस किया, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर परिसर, राजमहल की नक्काशी और भगवान नरसिंह की भव्य मूर्ति को खंडित किया गया। इसके बाद साल 2019 में पर्यटकों द्वारा विष्णु मंदिर के पास प्राचीन ग्रेनाइट स्तंभों को धक्का देकर तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। स्थानीय लोगों और पूर्व शाही परिवार ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर कम सुरक्षा और दूरदराज के खंडहरों में असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग भी की है।

साफ है, विश्व धरोहर का महत्व न सिर्फ आम लोगों को, बल्कि सरकारों को भी समझना होगा। कहने को लिए कई तरह के मानक बनाए गए हैं, लेकिन उन मानकों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। हमें इन स्थलों का महत्व समझना होगा।

सुमन पांडेय, शिक्षिका

खुशियों के रास्ते खुले रखिए

जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। किसी अपने को हमेशा के लिए खो देना, आर्थिक तंगी, कुछ करीबी रिश्तों में खटास या अन्य कोई बड़ी उथल-पुथल... ये सब हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। यह भी लगता है कि अब फिर कभी जीवन पटरी पर नहीं आएगा। याद रखें, जीवन में फिर से खुशियां लौट सकती हैं, बशर्ते आप खुद को मौके देने के लिए तैयार रहें।

मार्क चेरनॉफ
लेखक और ब्लॉगर।
आत्म प्रेरक विषयों पर लेखन।

एक सुबह मैं पार्क में बेंच पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग जोड़ा अपनी कार से उतरा। कार के भीतर धीमी-धीमी पुरानी धुन बज रही थी। बुजुर्ग सज्जन ने बड़े स्नेह से अपनी पत्नी का हाथ थामा, उन्हें कार से उतरने में मदद की और पास ही पेड़ की छांव में दोनों धीरे-धीरे नृत्य करने लगे। वह दृश्य इतना सुंदर था कि अनायास ही मैं तालियां बजाने लगा।

वे दोनों मुस्कराते हुए मेरे पास आए और तालियों के लिए शुक्रिया अदा किया। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों को देखकर यह उम्मीद नजर आती है कि जीवन हर उम्र में खूबसूरत हो सकता है। उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा, 'अभी आपने जीवन को दिए जाने वाले दूसरे, तीसरे मौके की सुंदरता और ताकत को देखा है। हमारा यह संबंध पिछले 10 सालों से है। इससे पहले हम दोनों ही अपने प्रिय जीवनसाथियों को खो चुके थे। हम दोनों जीवन के गहरे दुखों से गुजर रहे थे, पर हमने कभी जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। एक-दूसरे का हाथ थामा और फिर से जीना सीख लिया। ऐसा तब होता है, जब हम खुद को जीवन में मौके देने के लिए तैयार रहते हैं।

नजरिया ही सब कुछ है

जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हालात नहीं, बल्कि हमारा नजरिया होता है। शोक व निराशा के बावजूद आगे बढ़ने, प्रेम करने और जीवन जीते रहने की प्रेरणा कहां से मिलती है? यह सवाल मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले हम पति-पत्नी ने बहुत कम समय के भीतर कई हिला देने वाले हालातों का सामना किया था।

हर किसी के जीवन में मुश्किल दौर आता है। शोक की ऐसी घड़ी में कई बार लोग खुद को अलग-थलग कर लेते हैं। साथ देने वालों से ही दूरी बना लेते हैं। लोगों की सही मंशा को गलत समझ लेते हैं या फिर नशे आदि गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। नतीजा, दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और हम जिंदगी से और जिंदगी हम से हताश होने लगी।

मुश्किल दौर में सबसे कठिन काम परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने मन को संभालना होता है। सबसे बड़ी बात अपनी सोच को संतुलित बनाए रखना होता है। जब हम तकलीफों का सामना खुले मन से करते हैं, तो धीरे-धीरे जरूर आगे बढ़ते हैं। खुले मन का मतलब है, तुरंत यह न मानना कि सब खत्म हो गया है, बल्कि यह स्वीकारना कि हम नहीं जानते कि आने वाला पल कैसा होगा।

मृत्यु जीवन का एक सच

जीवन का एक बड़ा सच है- किसी प्रियजन को खोना। हालांकि, कोई भी शब्द इस दुख को कम नहीं कर सकता, पर एक अंत ही एक नई शुरुआत होती है। बीती बात में अटके रह जाने से बेहतर है, आगे के सफर की तैयारी करना। किसी प्रिय को खोना ही हमें जीवन और अपनों की कीमत समझाता है। सीमाएं ही सुंदरता बढ़ाती हैं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो इंसान या पल हैं, वे सीमित हैं। हम उनका सम्मान करें। खुद को मौके देना यानी नई उम्मीदों की कहानी। दिल से किए गए डांस की कहानी।

खुद को यह याद दिलाते रहें

खुद को चुनौती दें और नीचे दी गई बातों में से किसी एक को हर सुबह चुनें। दो मिनट शांत बैठकर, इसे बार-बार अपने मन में दोहराएं। आप देखेंगे कि यह छोटा-सा अभ्यास हमारे जीवन के उतार-चढ़ाव को संभालने का आपका तरीका बदल देगा-

1 आज जहां हैं, हमेशा वहीं फंसे नहीं रहेंगे जिंदगी हर सेकंड बदलती है और आप भी बदल सकते हैं। जब बुरा वक्त आता है, तो हम मान लेते हैं कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। अगर आप बीती बातों और दुखों को पकड़कर रखेंगे, उसी चश्मे से देखते रहेंगे, तो भविष्य भी धुंधला ही दिखाई देगा।

2 जो है, उसे स्वीकारें, सीखें और आगे बढ़ें ज्यादातर लोग सिर्फ, इसलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान हालात को स्वीकार नहीं कर पाते। जो हो चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। मायने यह रखता है कि आप यहां से आगे क्या करते हैं। परिस्थितियों को एक नए नजरिये से देखें और अगला कदम बढ़ाएं।

3 तकलीफ को गुस्सा नहीं, प्रेरणा बनाएं गुस्सा होने के बजाय सबक सीखें। चिंता करने के बजाय अगला कदम उठाएं। जीवन का बहुत छोटा हिस्सा उन चीजों से तय होता है, जो आपके बस में नहीं हैं। बड़ा हिस्सा इस बात से तय होता है कि आप उन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

4 जो चाहिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाएं छोटे-छोटे दैनिक नियम बनाएं। जब बुरा वक्त आता है, तो हम तुरंत सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और जल्दबाजी में कुछ नहीं कर पाते। याद रखें, आप एक साथ बहुत भारी वजन नहीं उठा सकते, लेकिन छोटे-छोटे प्रयासों से मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं।

5 मेहनत बेकार नहीं जाती, नतीजे भले मनचाहे न हों अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। सफलता समय मांगती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि काम करते हुए अपना रवैया सकारात्मक बनाए रखना है।

6 अपने मानदंड छोटे न करें, खुद पर भरोसा बनाए रखें जीवन में हर तरह के लोग मिलेंगे। किसी का कड़वा व्यवहार आपको उतना दर्द नहीं देता, जितना आपकी सोच उसे महत्व देकर देती है। मानसिक शांति तब शुरू होती है, जब आप दूसरों की बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते।

7 उम्र के साथ समझ आएगी समय, संबंध और शांति की अहमियत सब बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं। बेवजह की चिंताओं और दिखावे में ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। आज से 10 साल बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन-से कपड़े या जूते पहने थे। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने कैसे जिया, कितना प्यार बांटा और क्या सीखा। जो मायने रखता है, उस पर ही अपनी ऊर्जा बनाए रखें। अपने समय, संबंध और मानसिक सेहत का हमेशा ध्यान रखें।

विविध

रिश्तों को मजबूत बनाएंगे ये तीन सूत्र

रिश्ता कोई भी हो, वह एक दिन में मजबूत नहीं बन जाता। रोजमर्रा के छोटे-छोटे व्यवहार, आपसी सम्मान और एक-दूसरे के प्रति सही रवैये से ही रिश्ते गहरे बनते हैं।

हर रिश्ता अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीवन-मूल्य हैं, जो हर संबंध को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यहां नीचे दिए सूत्र आपके जीवन के हर रिश्ते को अधिक अर्थपूर्ण और मजबूत बना सकते हैं।

1. कठिन समय में जिन्होंने साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलिए

जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं, जब कोई हमारा हाथ थाम लेता है। कोई मित्र कठिन समय में हमारा संबल बनता है। परिवार का कोई सदस्य हम पर विश्वास जताता है या कोई गुरु सही दिशा दिखाकर आगे बढ़ने का साहस देता है।

हो सकता है, उनका योगदान आज आपको छोटा लग रहा हो, पर कई बार ऐसी छोटी-छोटी मदद ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। किसी के प्रति आभार केवल बड़े उपहारों से ही नहीं निभाया जाता। समय-समय पर दिल से कहा गया 'धन्यवाद', एक आत्मीय संदेश, हालचाल पूछ लेना या जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होना भी रिश्तों को गहरा बना देता है। लोग यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा एहसास कराया था।

2. अपने शुभचिंतकों से कभी दूरी मत बनाइए

हर वह व्यक्ति जो आपकी गलती बताता है, आपका विरोधी नहीं होता। जो लोग वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं, वे कई बार ऐसी बातें भी कह देते हैं, जो सुनने में अच्छी नहीं लगतीं। वे आपकी किसी आदत पर सवाल उठा सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं या आपकी भूल की ओर ध्यान दिला सकते हैं।

ऐसे क्षणों में उनकी बात को आलोचना समझने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे चिंता और अपनापन भी हो सकता है। हर असहमति रिश्ते की कमजोरी नहीं होती। कई बार वही ईमानदार संवाद रिश्ते को और मजबूत बना देता है।

यदि हम सामने वाले के इरादों को समझने की कोशिश करें और संवाद बनाए रखें, तो गलतफहमियां पनपने से पहले ही दूर हो जाती हैं। यही परिपक्वता रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ाती है।

3. किसी के विश्वास को कभी मत तोड़िए

हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है- विश्वास। जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करता है, अपनी निजी बातें आपसे साझा करता है या आपकी ईमानदारी पर विश्वास जताता है, तो यह बहुत बड़ी बात है।

इस भरोसे का अर्थ है-सच बोलना, अपने वादे निभाना, दूसरे की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना तथा हर हालात में ईमानदारी से व्यवहार करना। यदि आप लगातार भरोसेमंद बने रहते हैं, तो दूसरे आपके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और रिश्ते में मजबूती बढ़ती जाती है।

जिंदगी में कम न हो जोश और जुनून

जिंदगी केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन को पूरे मन से महसूस कर पाना भी जरूरी है। क्यों सब कुछ होने के बावजूद जीवन में खालीपन और भावनात्मक जड़ता बढ़ रही है? जीवन में उत्साह कैसे पैदा करें, आइए जानें...

पिछले कुछ वर्षों से एक सवाल लगातार मेरे काम के केंद्र में बना हुआ है- क्या है, जो इंसान को भीतर से जीवंत महसूस कराता है?

एक मनोचिकित्सक के रूप में मेरे पास ऐसे अनेक लोग आते हैं, जिन्होंने जीवन में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है। अच्छी नौकरी, आर्थिक सुरक्षा, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा। सब होने के बावजूद वे एक गहरे खालीपन से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं।

47 वर्षीय एक क्लाइंट कहते हैं, 'मेरे पास मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है। पूरा दिन काम में निकल जाता है। सप्ताहांत परिवार के साथ, पर भीतर से लगता है, मानो मैं मर चुका हूं। मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार कब किसी बात पर दिल से खुशी हुई थी। मैं बस जिंदगी काट रहा हूं।'

वहीं, करीब 28 वर्ष की एक युवती बताती हैं, 'मुझे दस साल पहले वाली अपनी जिंदगी याद आती है, जब मैं हर अनुभव में पूरी तरह डूब जाती थी। आज सोशल मीडिया देखकर लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूं, लेकिन अधिकांश दिन, मैं खुद को भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस करती हूं।'

धीरे-धीरे कम होता उत्साह

आज स्क्रीन, सोशल मीडिया और भागदौड़ ने हमारी दिनचर्या पर कब्जा कर लिया है। संवेदनशीलता का गुण धीरे-धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। उसकी जगह उदासीनता, थकान और आत्मकेंद्रित सोच बढ़ती जा रही है। जीवंतता का अर्थ हर समय उत्साहित रहना नहीं है। इसका असल अर्थ है, जीवन को महसूस करने की क्षमता और जीवन के प्रति सजगता का एहसास।

मेरी नजर में जीवन शक्ति पांच गुणों से मिलकर बनती है। ये गुण हैं-जीवन के प्रति उत्साह, नई चीजों के प्रति खुलापन, फैसले लेने की आजादी, लोगों से सहज जुड़ाव, भावनात्मक लचीलापन और हालात के बीच भी आशावादी सोच बनाए रखने की क्षमता। जीवन के प्रति उत्साह हमेशा किसी बड़े रोमांच या उपलब्धि से नहीं आता। कई बार छोटे-छोटे अनुभव ही हमारे जीवन को सार्थक महसूस कराते हैं।

> साठ से सत्तर की उम्र के कई लोग हर काम पूरे मन से करते हुए देखे जा सकते हैं। कई लोग कठिन हालातों के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं। बच्चों-सी जिज्ञासा और सहजता ही हमारी जीवंतता के सबसे सहज रूप हैं।

कैसे लौटे जीवन की ओर

शोध बताते हैं कि जीवन के प्रति उत्साह का होना व्यक्ति की मानसिक सेहत, प्रेरणा और समग्र खुशहाली पर सीधा असर डालता है। जब यह उत्साह कम होने लगता है, तो व्यक्ति नए अवसरों को अपनाने, रिश्तों को निभाने और पहल करने की इच्छा भी खोने लगता है। लंबे समय में यही स्थिति बर्नआउट, निराशा व उद्देश्यहीनता को जन्म देती है।

अच्छी बात यह है कि जीवन में उत्साह फिर से पैदा किया जा सकता है। मेरे लिए किसी कला प्रदर्शनी में जाना, किसी फिल्म को पूरे मन से देखना या किसी सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना मुझे जीवंत महसूस कराता है। वहीं, किसी के लिए पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना और प्रकृति के बीच समय बिताना वही एहसास पैदा करता है।

यह भी जरूरी है कि हम समय-समय पर अपने मूल्यों को याद करें। वे कारण जिनकी वजह से हमने अपना पेशा चुना था या जीवन के बड़े फैसले लिए थे। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ हम इन्हें भूल जाते हैं। कई बार किसी उत्साही या आशावादी व्यक्ति के साथ समय बिताना भी हमारे भीतर खोई हुई ऊर्जा को फिर से जगा देता है।

सोनाली गुप्ता

एकदा आशा

चार वृद्ध महिलाएं थीं। एक दिन वह बहस कर रही थीं कि हम में से बड़ी कौन है? बहस जब लंबी खिंच गई, तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो समझदार बहू आई है, उससे फैसला करवाते हैं।

वे चारों उस बहू के पास गईं। बहू ने उनकी बात सुनी और कहा, 'पहले आप चारों मुझे अपना परिचय तो दें।

पहली महिला ने कहा, 'मैं भूख हूं, मैं बड़ी हूं न?'

बहू ने कहा, 'भूख में विकल्प है। भूख 56 व्यंजनों से भी मिट सकती है और बासी रोटी से भी।'

दूसरी महिला ने कहा, 'मैं प्यास हूं, तो मैं बड़ी हूं न?'

बहू ने कहा, 'प्यास में भी विकल्प है। प्यास गंगाजल से भी शांत हो जाती है, मधुर रस से भी और बुरे वक्त में तालाब का पानी भी काम आ जाता है।'

तीसरी वृद्ध महिला ने कहा, 'मैं नींद हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं न?'

बहू ने कहा, 'नींद में भी विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर तो आती ही है, किन्तु मेहनत से थके हुए शरीर को टूटी घाट और जमीन पर भी नींद आ जाती है।

चौथी महिला ने कहा, 'मैं आस (आशा) हूं।' इसके आगे वह कुछ कहती, बहू ने उस महिला के पैर छू लिए, 'मैया! आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य सौ बरस भी जीवित रह सकता है, पर आशा ही न रहे, तो जीवन बिखर जाता है। अभाव न होने पर भी जीवन में खालीपन भर जाता है।'

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन परेशान रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। कारोबार में भी भागदौड़ बढ़ सकती है।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। लेखनादि कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

मिथुन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ भी बढ़ेगा।

कर्क : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की भी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि तथा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। संतान व जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। पढ़ाई में सफलता मिलेगी।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। सेहत का ध्यान भी रखें। किसी मित्र के सहयोग से कोई नया करोबार शुरु हो सकता है। यात्रा खर्च बढ़ेंगे।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

धनु : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ बढ़ेगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

मकर : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से व्यस्तता बढ़ सकती है। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार की सेहत का भी ध्यान रखें। आय में कमी व खर्च की अधिकता रहेगी। यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

3 अगस्त, सोमवार, **शक संवत्** : 12 श्रावण (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 19 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 19 सफर, 1448, **विक्रमी संवत्** : श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि रात्रि 10.55 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10.01 मिनट तक पश्चात रेवती नक्षत्र, कौलव करण, चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)। **सूर्य दक्षिणायन।** सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। नाग पंचमी। श्रावण सोमवार व्रत प्रारंभ। गंडमूल रात्रि 10.01 बजे से। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मंदिर में प्रवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें :

- मंदिर में भगवान की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में यानी बायें से दायें करनी चाहिए।
- मंदिर के बाहर चप्पल एकदम भगवान के सामने नहीं उतारें। चप्पलों को इस प्रकार उतारें कि कोई दूसरा उन्हें लांघ न सके। मंदिर में मोजे पहनकर न जाएं।
- मंदिर से आने के तुरंत बाद हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए।
- मंदिर से आने के बाद एकदम सबसे पहले शौचालय नहीं जाना चाहिए।
- मंदिर से आने के बाद स्नान भी नहीं करना चाहिए।
- जब भी मंदिर जाएं, तो मंदिर की चौखट को छूकर प्रणाम करके ही अंदर जाएं।

वर्ग पहेली : 8409

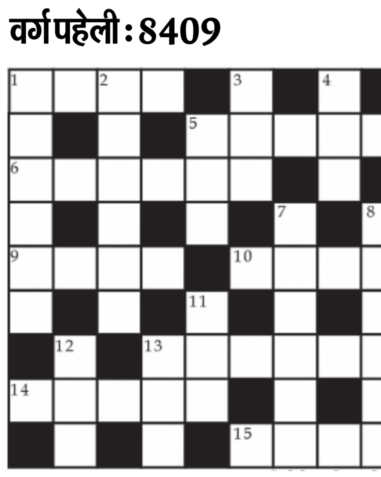

बाएं से दाएं

1. साधारण व्यक्ति; आम व्यक्ति (2,2)
5. उद्धार करने वाला; तारने वाला; नाविक; संकटमोचक (5)
6. रक्षा करना; बचाना; बचा कर चलना (3,3)
9. अध्यक्षता; सभापतित्व; सदर का पद (4)
10. बोलचाल के वाक्यांश; विलक्षण अर्थों वाला शब्द समूह (4)
13. घोलना; मिलाना; समामेलन करना (3,3)
14. आलिंगन करना; पाश में लेना; लिपटना; शबाशी देना (2,3)
15. आमद रफ्त; मिलना-जुलना; आवागमन (2,2)

ऊपर से नीचे

1. कड़ी गरमी होना; तेज धूप पड़ना; गोले/गोलियों की बौछार होना (2,4)
2. जहाज का पहली बार पानी में प्रवेश (6)
3. रोकना; अगोटना; घेरे में लाना (3)
4. पानी भरने वाला; पालकी उठाने वाला (3)
5. तारा; नक्षत्र; कर्णधार; तारने वाला; (3)
7. अंत करना; कहर ढाना; विनाश करना (3,3)
8. प्रशंसा होना; तारीफ होना; बड़ाई होना (4,2)
11. दग्ध होना; आग लगना; ईर्ष्या करना (3)
12. धन; राशि; संपत्ति (3)
13. जो घना न हो; दुर्लभ; पतला (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली

(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8408

1 ब	र	2 क	त	3 हो	ना		4 भ	
त		न		न		5 ग	र	ल
6 र	सि	क	बि	हा	री		भ	
स		ना		र		7 चौ	रा	हा
	8 ल	ह	र		9 रो	क	ना	
10 क	प	ट		11 च		ड़ी		12 खा
	ल		13 चु	ट	की	भ	र	ना
14 सी	पा	न		की		र		पी
	ना		15 उ	ला	ह	ना	दे	ना

सुडोकू : 8363

* मध्यम

		1	6		5	3		
6	2						8	5
	4			9			6	
		6	8		7	2		
	8			2			7	
4	7						3	1
		2	5		3	6		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8362

3	1	9	8	6	7	2	4	5
8	6	4	3	2	5	1	9	7
2	5	7	9	4	1	6	3	8
5	3	6	2	8	4	9	7	1
7	4	1	5	3	9	8	6	2
9	8	2	1	7	6	4	5	3
1	2	5	6	9	3	7	8	4
4	9	8	7	5	2	3	1	6
6	7	3	4	1	8	5	2	9

कल्पमेधा

हमें उस जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए, जिसकी हमने अपने लिए कल्पना की है, ताकि उसको स्वीकार कर सकें जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।

– जोसेफ कैम्पबेल

आतंक का चेहरा

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए लक्षित आतंकी हमले में दो प्रवासी मजदूरों की मौत ने एक बार फिर यही सवाल उठाया है कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए की जा रही तमाम कवायदों का क्या हासिल है और आज भी अक्सर यह बेलगाम क्यों दिखता है। गौरतलब है कि कुलगाम में आतंकियों ने शुक्रवार शाम दो प्रवासी मजदूरों की गोली मार कर हत्या कर दी। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ से दक्षिण कश्मीर के केल्लम इलाके में ईंट-भट्ठे पर काम करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन चला रहे थे। खबरों के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के ही एक छाया संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। जाहिर है, इस घटना के बाद फिर से सरकार सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने की ओर नए कदम उठाने की बात करेगी और लोगों को यह भरोसा दिया जाएगा कि भविष्य में आतंकियों की हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। मगर अफसोस की बात यह है कि घाटी में सिर्फ दस दिनों के भीतर लक्षित आतंकी हमले की यह दूसरी घटना है। हाल ही में अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी।

इसमें कोई दोराय नहीं कि सीमा पार स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा लेने के क्रम में सुरक्षा बलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और हर कुछ समय बाद रणनीति में भी बदलाव किया जाता रहता है। इसी वजह से आतंकी हमलों को पूरी तरह रोक पाने में फिलहाल भले ही कामयाबी न मिली हो, लेकिन ऐसी घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है। इसके बावजूद यह सच है कि अक्सर आतंकी संगठनों की ओर से कुछ लोगों को चुन कर निशाना बनाया जाता है और इस तरह अपनी मौजूदगी का संकेत देने की कोशिश होती है। यह साफ है कि आज भी जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में आतंकी संगठनों के पांव जमे हुए हैं और वे कई बार सिर्फ इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, ताकि उनका खौफ बना रहे। इसके समांतर यह भी गौर करने वाली बात है कि सुरक्षा बलों से लेकर पुलिस महकमे के व्यापक तंत्र की मौजूदगी के बावजूद आम लोगों के भीतर हर वक्त एक परोक्ष असुरक्षाबोध काम करता रहता है।

सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के अंतराल पर आतंकवादी बिना किसी रोकटोक के आबादी के बीच घुसपैठ करते हैं और कभी अराजक तरीके से, तो कभी पहलगाम जैसे हमले को अंजाम देकर आसानी से भाग जाते हैं। त्रासद नतीजों का दंश आम लोगों को झेलना पड़ता है। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान खुफिया विभाग, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल की वजह से आतंकियों के खिलाफ एक ठोस मोर्चा कायम किया गया है और आतंकवादियों के प्रत्यक्ष हमलों पर अंकुश लगा है। कई बार स्थानीय आबादी के बीच से भी पुलिस को सहयोग मिल जाता है। इसके बावजूद यह तथ्य है कि घाटी आतंकी हमलों से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से अब आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब उन्होंने लक्षित हमलों को अपना मुख्य जरिया बनाया है। जाहिर है, सरकार और सुरक्षा बलों को अब इसी मुताबिक आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति के साथ मोर्चा लेने की जरूरत है।

अधूरी शिक्षा

शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार स्तंभ होती है। यह भी जरूरी है कि शिक्षा में अमीर-गरीब, जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि सबको सामान अवसर मिल सके। यह सच है कि भारत के शिक्षित समाज में पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन चुनौतियां अभी बरकरार हैं। हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में देश भर में नौवीं और दसवीं कक्षा के स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर आठ फीसद रही, जो अन्य कक्षाओं के मुकाबले सबसे अधिक है। यह हाल तब है, जब सरकार की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। सवाल है कि जब सबको शिक्षा के समान और सुलभ अवसर मुहैया कराने की नीतियां लागू की जाती हैं, तो लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता बीच रास्ते में ही दम क्यों तोड़ देती है?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब एक महिला शिक्षित होती है, तो इसका प्रकाश पूरे परिवार को आलोकित करता है। योग्यता की बात की जाए, तो देश में हर साल स्कूली बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियां अव्वल रहती हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें किसी कारणवश माध्यमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ने को विवश होना पड़े, तो इसे व्यवस्था की नाकामी नहीं, तो और क्या कहा जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष लद्दाख में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक 15.6 फीसद दर्ज की गई। इसके बाद असम और कर्नाटक का स्थान है, जहां यह दर 13.9 फीसद रही। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें लड़कियों का घरेलू कार्यों और आर्थिक मामलों में परिवार का सहयोग करने के लिए स्कूल छोड़ देना या फिर माता-पिता का उनकी आगे की शिक्षा को जरूरी न समझना भी शामिल है। अहम सवाल यही है कि क्या सरकार की ओर से इन कारणों को समझने और उनका समाधान करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी लड़की आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे?

अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मंडराता खतरा

खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने बनाने का अमेरिका का मकसद ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना है। मगर इन ठिकानों पर अब ईरान के लक्षित हमलों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है।

पुष्परंजन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने अमेरिकी नीति के एक ऐसे पहलू को उजागर किया है, जिस पर पहले बहुत कम ध्यान दिया गया। वह है मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों की स्थिति। इस इलाके में मौजूद अमेरिकी अड्डे अब ईरानी हमलों के निशाने पर हैं। खबरों के मुताबिक, इस साल 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से करीब उन्नीस अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और 624 घायल हुए हैं। अरबों डालर के सैन्य साजो-सामान का नुकसान हुआ है और इसके केंद्र में यही सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका युद्ध तो चाहता है, मगर अपना नुकसान नहीं चाहता। इस नुकसान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो आगामी तीन नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव तक पीछा करेगा।

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध छेड़ने से पहले अपने नुकसान का आकलन नहीं किया था। फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका के कई ऐसे सैन्य अड्डे हैं, जो ईरान के बहुत करीब हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर स्थित अल-उदीद एयर बेस है, जहां मौजूदा युद्ध से पहले लगभग दस हजार अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय भी है और यहीं 'कंबाइंड एअर आपरेशन' केंद्र भी स्थित है, जो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी वायु सेना की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पांचवें बेड़े और अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय बहरीन में है। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के महत्त्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं। ओमान और सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ये सभी ईरान की प्रहार पहुंच में आते हैं।

सैन्य अड्डों की यह व्यवस्था तब तर्कसंगत थी, जब अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में ऐसे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा था, जिनके पास उन अड्डों पर हमला करने की क्षमता नहीं थी। वर्ष 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, तब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे बेहद उपयोगी और लगभग अभेद्य थे। वर्ष 2003 में शुरू हुए इराक संघर्ष के दौरान भी स्थिति ऐसी ही थी, कोई भी विरोधी पक्ष अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला करने में सक्षम नहीं था और उस समय ड्रोन का इस्तेमाल शुरू ही हुआ था। तब के ड्रोन से आज की तुलना करें, तो इनकी मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है।

ईरान के साथ टकराव में अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदा व्यवस्था अब अभेद्य नहीं है। ईरान के जखीरे में मौजूद मिसाइलों और ड्रोन की मारक क्षमता को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सैन्य अड्डे अब खतरे में हैं। उदाहरण के लिए, कुवैत स्थित कैंप आरिफजान, जो सेंट्रल कमांड की जमीनी सेनाओं के लिए अग्रिम मुख्यालय है, वह ईरान से केवल 62 मील की दूरी पर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का बेस ईरान

से लगभग 128 मील दूर है, जबकि अल-उदीद सैन्य ठिकाना करीब 170 मील दूर है। ये सभी ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं। इसकी तुलना में ईरान से इजराइल की दूरी लगभग 1,100 मील है।

खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे तब विकसित किए गए, जब

> **खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे तब विकसित किए गए, जब सोवियत संघ के मुकाबिल अमेरिका के सहयोगियों को सुरक्षा की जरूरत थी। हो सकता है कि अफगानिस्तान और इराक युद्धों के दौरान यह नाकेबंदी सफल तरीके से काम कर रही थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक सुरक्षित नहीं हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों को अब ईरान से दूर भेजा जा रहा है। अमेरिकी सैनिक कतर में मौजूद अल-उदीद एअर बेस को खाली कर रहे हैं और यहां से अमेरिकी विमानों को भी दूसरी जगह भेजा गया है। ऐसे में अब दुनियाभर में सैन्य ठिकाने बनाने की अमेरिकी रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं।**

सोवियत संघ के मुकाबिल अमेरिकी सहयोगियों की सुरक्षा की जरूरत थी। हो सकता है कि अफगानिस्तान और इराक युद्धों के दौरान यह नाकेबंदी सफल तरीके से काम कर रही थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों को अब ईरान से दूर भेजा जा रहा है। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि कुछ अमेरिकी सैनिक कतर में मौजूद अल-उदीद एअर बेस को खाली कर रहे हैं और अमेरिकी विमानों को भी दूसरी जगह भेजा गया है। बाद में पता चला कि दर्जनों अमेरिकी विमानों को इजराइल के बेन गुरियन हवाईअड्डे और रेमन एअर बेस पर भेजा गया है। इससे साफ है कि अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डों को लेकर चिंतित है।

सेवानिवृत्त जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जो केंद्रीय कमान (सेंटकाम) के पूर्व कमांडर थे, उनका मानना है कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान और खाड़ी क्षेत्र से और दूर जाने की जरूरत है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका की केंद्रीय कमान का अग्रिम मुख्यालय ईरान से सौ मील दूर कतर में नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक, अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाने की रणनीति जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। हमें पश्चिम की ओर देखना होगा। हमें इजराइल में सैन्य अड्डे बनाने पर विचार करना होगा, क्योंकि एक तो वह ईरान से दूर है और दूसरा वहां विमानों के उड़ान भरने पर पाबंदियों की संभावना भी बहुत कम हैं। अमेरिका, इराक के पश्चिमी अनबार प्रांत में ऐन अल असद एयर बेस पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है, जहां से वह इराकी सुरक्षा बलों की मदद करता है और नाटो मिशन में योगदान देता है। वर्ष 2020 में ईरान ने इस सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले किए थे, जो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका द्वारा हत्या के जवाब में किए गए थे।

अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान की पहुंच से दूर अन्य जगहों पर भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जैसे पश्चिमी सऊदी अरब और मिस्र में, मगर इन जगहों पर इजराइल जैसी वायु रक्षा प्रणाली नहीं हैं और न ही वहां विमानों की उड़ान में उतनी ढील मिल पाएगी, जितनी इजराइल में मिल सकती है। कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका के कई खाड़ी देशों में सैन्य अड्डे हैं, इसलिए उसे अपने सभी हवाई संसाधनों को एक ही जगह रखने के बजाय नए अड्डे बनाने पर विचार करना चाहिए। मगर इसमें भी कई तरह की चुनौतियां हैं।

इजराइल को अपने यहां नए अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भले ही कोई एतराज न हो, लेकिन मिस्र, सऊदी अरब या इस इलाके के दूसरे देश इसे एक बोझ के तौर पर देख सकते हैं और वे उसके बदले सौदेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा, नए सैन्य ठिकाने बनाना बहुत महंगा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी रक्षा बजट पर पहले से ही भारी दबाव है। कतर में वर्ष 1996 में अल-उदीद बेस बनाने में लगभग दो अरब डालर खर्च किए गए थे और तब से इसके रखरखाव पर छह अरब डालर से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने स्थापित करने के पीछे अमेरिका की मुख्य रणनीति वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण, क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना और ईरान जैसे विरोधियों को रोकना है। मगर अब खाड़ी देशों में यह बहस तेज हो गई है कि अमेरिका के ये ठिकाने वास्तव में सुरक्षा देते हैं या उन्हें अनचाहे युद्ध में घसीटते हैं, क्योंकि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों को ही निशाना बना रहा है। बहरहाल, मौजूदा परिस्थितियों ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है।

जागरूकता की चेतना

शोभा जैन

दुनिया मेरे आगे

हमारी चेतना की जमीन हमारे जीवन को संचालित करने वाले निर्णयों से ही उपजती है। जीवन में कईं बार ऐसी परिस्थिति बनती है, जब हमारा मानस निर्णय तो लेता है, लेकिन उन निर्णयों में स्थायित्व नहीं रहता। वे भविष्य में टिक नहीं पाते। चेतना सबकी एक ही होती है। फर्क होता उन मूल्यों का, जो हमारी चेतना में मौजूद रहते हैं। इन मूल्यों के अनुसार ही हमारी चेतना किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये मूल्य ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि वे कौन-से तत्त्व और कार्य होंगे, जो हमें अपराध-बोध से भरेंगे और हमें अपराध-बोध से मुक्त रखेंगे।

जीवन में कभी-कभी ऐसा पड़ाव भी आता है, जब हमारी चित्त अवस्था स्थिर नहीं होती। वैसे भी वह स्थिर नहीं, गतिशील है। वह ठहराव नहीं, निरंतर खोज है, लेकिन यहां अस्थिर होने का आशय विचलन से है। भीतर के प्रश्नों की यात्रा ठहरती नहीं। वह एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां आंतरिक खोज अपने ही छायापथ पर चलती है। मगर अस्थिर मन में जब कोई हमारे अनुकूल काम होता दिखाई देता है, तब मन अपने आप ही किसी आंतरिक उत्साह से भर जाता है। वह छोटा-सा उत्साह कितने दायित्वों को निभाने की ऊर्जा दे देता है, हम इसकी पूर्व से कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अवसाद और आत्महत्या के केंद्र में होता है सहनशीलता का अभाव, ठीक वैसे ही उत्साह और जागरूकता के केंद्र में प्रोत्साहन भी एक कड़ी है। जीवन में ऐसे कईं अवसर आते हैं जब हम उत्साहित होकर किसी लक्ष्य को साधते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में उस लक्ष्य का अपेक्षित परिणाम नहीं पाते। ठीक इसके उलट, एक व्यक्ति के भीतर किसी काम या लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता तो हो, लेकिन उसके भीतर उत्साह की कमी हो, तो उसके लिए आसान राह भी मुश्किल होगी। इसके अलावा, एक स्थिति यह भी होती है कि क्षमता और उत्साह से लैस व्यक्ति को भी अगर कोई निराशा में डुबो दे, उसका उत्साह भंग कर दे, तो किसी काम को आसानी से पूरा करने की उसकी क्षमता विपरीत दिशा में प्रभावित होती है।

> **भेद हमेशा विचारों के स्तर पर होते हैं। चेतना के स्तर पर कभी कोई भेद नहीं होते। ज्यादातर लोग अपनी चेतना को शुद्ध ही मानकर चलते हैं। तर्क-वितर्क से उसे न्यायसंगत ठहरा देते हैं। ऐसे में जीवन में घटित घटनाओं में अपनी निजी चेतना को शुद्धि की कसौटी पर स्वयं कसकर देखना चाहिए।**

कहने का आशय यह कि अगर हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है, तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह लिखा है- उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। अगर फल दूर ही दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ-साथ लगाव न मालूम हो, तो हमारे हाथ-पांव कभी न उठें और उस फल के साथ हमारा संयोग ही न हो। इसमें कर्म-शृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। अगर हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। अगर हम किसी बात पर गुस्सा हुए बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है, तो भी हम उस पर झुंझला उठते हैं। यह सब मनोस्थिति द्वारा संचालित होता है और मनोस्थिति परिस्थितिजन्य होती है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक भय की ग्रंथि से जूझते हैं। ऐसे में संवाद एक उत्साह की चिंगारी जरूर है। दरअसल, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। ऐसे में संवाद को मानव समाज की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहीं से विचार की दोहरी प्रक्रिया शुरू होती है। संवाद का उपक्रम सत्संग भी है। जहां हम अपने मन के भावों को पलायन करने के बजाय अपने छूटे हुए अंतरंग की बुनियादी बुनाइयां बुनने लगे। नीरसता व्यक्ति को नकारात्मक और निरुत्साही बनाती है, तो उसमें मन की अस्थिर अवस्था की केंद्रीय भूमिका रहती है। इसलिए उत्साह में चिंतन की स्थिति बनी रहे, जिसे हम जागरूकता की परिपक्व अवस्था भी कह सकते हैं। बस उत्साह क्षणिक उद्वेगयुक्त होता है, इसलिए उसमें जागरूकता का होना पहली शर्त है।

हमारे उत्साह में हमारी चेतना की भूमिका सर्वोपरि है। चेतना के स्तर पर कभी कोई भेद भी नहीं होते, तो भेद हमेशा विचारों के स्तर पर होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी चेतना को शुद्ध ही मानकर चलते हैं। तर्क-वितर्क से उसे न्यायसंगत ठहरा देते हैं। ऐसे में जीवन में घटित घटनाओं में अपनी निजी चेतना को शुद्धि की कसौटी पर स्वयं कसकर देखना चाहिए। हम दंग रह जा सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, उसके केंद्र में हमारी चेतना है। शुद्ध चेतना जो हमारे कार्य को स्वयं निदेशित करे, किसी दूसरे की चेतना उसकी वैचारिकी का अनुगमन करना होगा। अपनी चेतना को परिष्कृत भी करना पड़ता है और इसमें सबका अपना अलग तरीका होता है, सबके अनुभव अलग। उत्साह और जागरूकता में चेतना की अहम भूमिका रहती है। चेतना में सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान उसकी परिधि में निहित है। जीवन दर्शन और परिवेश इसके रसायन हैं। चेतना निरंतर परिष्कृत होने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो आज है, कल वह अनुभव भी रहे, यह जरूरी नहीं। राम और रावण दोनों में चेतना थी, लेकिन भिन्न स्तर की।

अपने उत्साह को बढ़ाने की कुंजी यह है कि हम अपने स्वार्थ से परे किसी ऐसे उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएं, जिसके प्रति हमारी गहरी लगन हो, जिसमें हमारी चेतना की परिष्कृत अवस्था हो। दूसरों से अर्जित नहीं, स्व-अनुभव से अर्जित। यह उद्देश्य हमें प्रतिबद्धता देगा।

बदलते समाज में

सदियों तक जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार झेलने वाले वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर देना संविधान की मूल भावना रही है। यह व्यवस्था लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आई। अनेक लोग पहली बार उच्च शिक्षा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच सके। इसलिए आरक्षण की ऐतिहासिक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर रही है? क्या इसका लाभ सबसे अधिक वंचित वर्ग तक पहुंच रहा है या अपेक्षाकृत सक्षम परिवारों तक ही सीमित होता जा रहा है? इन प्रश्नों से बचना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करेगा। आज सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली युवाओं में भी असंतोष दिखाई देता है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक संगठन मानते हैं कि सामाजिक भेदभाव आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यही कारण है कि दोनों पक्ष अपने-अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं को न्यायोचित मानते हैं। इसलिए समाधान किसी एक पक्ष की जीत में नहीं, बल्कि संतुलित नीति में है।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

हिम्मत से संघर्ष

'बिखरने के बजाय' (दुनिया मेरे आगे, 28 जुलाई) में जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालने के बारे में बखूबी बताया गया। आज बढ़ते तनाव, टूटते रिश्ते और प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्य न बिठा पाने के कारण लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा कर अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। क्यों हार मान लेना और खुद को असफल मान कर हम बिखर जाते हैं? हारने के बजाय परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। खुद पर विश्वास, गिर कर उठने की प्रवृत्ति, दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में मदद करते हैं। खुद को बिखरने न दें, बल्कि जिंदगी में बाधाओं, चुनौतियों और उतार-चढ़ावों में खुद को निखारें। हार मान आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बना कर संघर्ष का सामना करना ही बहादुरी और समाधान है।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

कानून का दायरा

संविधान ने हर नागरिक को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल दंडनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में छात्र आंदोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारी हों या पुलिस यदि किसी ने भी किसी पर ज्यादती की है, तो वे कानून के दायरे में आएंगे और जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। देश का हर नागरिक कानून से बंधा हुआ है। अपनी उचित मांगों के लिए कोई भी संगठन प्रदर्शन या आंदोलन के माध्यम से आवाज उठाता है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे कानून के दायरे से बाहर न जाएं। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि वह नागरिकों और संगठनों की उचित मांगों के प्रति इतनी उदासीन भी न रहे कि बात आगे बढ़ने लग जाए। वह राजनीति से ऊपर उठ कर संवाद के जरिए मामले सुलझाने का प्रयास करे ताकि धरना-प्रदर्शन की नौबत ही न आए।

– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

अकेले पड़ते बुजुर्ग

वर्तमान समय में कई वृद्ध अपने ही परिवार में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। इसकी कई वजह है, जैसे आधुनिक जीवनशैली, कामकाजी लोगों का स्थानांतरण और युवाओं का शहरों की ओर पलायन। गौरतलब है कि आर्थिक कारणों से भी घरों में बुजुर्गों की उपेक्षा होती है। दुख की बात यह है कि बड़ों के प्रति सम्मान का भाव भी कम होता जा रहा है। लोग न तो अपने माता-पिता के साथ खाना खाते हैं और न ही अपने संग बाहर कहीं घुमाने लेकर जाते हैं। ऐसे में माता-पिता के मन में कई आशंकाएं घिरने लगती हैं कि अंतिम समय में कौन उनकी मदद करेगा। ऐसे में परिजनों को चाहिए कि वे बुजुर्गों की अनदेखी न करें। बुजुर्गों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वे वृद्ध आश्रम में रहने के बारे में न सोचें। ध्यान रहे कि घरों में बुजुर्ग उस घने पेड़ की तरह हैं. जिनकी छाया में हम बड़े हुए।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

व्रत त्योहार

3 अगस्त : सावन का पहला सोमवार।
8 अगस्त : अजा एकादशी।
9 अगस्त : प्रदोष व्रत।
11 अगस्त : सावन शिवरात्रि।
12 अगस्त : श्रावण अमावस्या (हरियाली अमावस्या)।
15 अगस्त : हरियाली तीज।
17 अगस्त : नाग पंचमी।
18 अगस्त : तृतीय मंगला गौरी व्रत।
20 अगस्त : दुर्गाष्टमी व्रत।

प्रकृति के पुनर्जीवन व उल्लास का त्योहार है हरियाली तीज

सुनील दत्त पांडेय

भारतीय पर्व जहां ईश्वर की साधना से जुड़े होते हैं, वही वह समाज में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक मूल्यों की धरोहर को समेटे हुए भी होते हैं। ऐसा ही पर्व हरियाली तीज है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह प्रकृति के स्वागत, शिव-पार्वती के मिलन और महिलाओं के सुहाग का सांस्कृतिक पर्व है। महिलाओं के लिए आपसी मेल-मिलाप, सांस्कृतिक जुड़ाव और रिश्तों को मजबूत करने का एक खास सामाजिक उत्सव है। सावन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यह उत्सव प्रकृति के पुनर्जीवन और उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व जीव और परमात्मा के योग, मन की पवित्रता और प्रकृति के साथ आत्मिक संबंध का संदेश देता है।

यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद दिलाता है। पर्व शिव और पार्वती के दिव्य मिलन, अटूट प्रेम, और कठोर तपस्या की स्मृति से जुड़ा है। यह आदर्श और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। तीज के दिन महिलाएं मिलकर लोकगीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और झूला झूलती हैं। यह उनके सामूहिक आनंद का अवसर है। इस दिन मन से छल, कपट और परनिंदा जैसे विकारों को दूर रखने का आध्यात्मिक संकल्प लिया जाता है। यह उत्सव प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने का माध्यम बनता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार इस पर्व में शिव पार्वती के पूजन का विधान है, वहीं वृंदावन में बांके बिहारी का विग्रह उनके दरबार से बाहर सोने चांदी के हिंडोले में रखा जाता है और साल में केवल एक बार हरियाली तीज के दिन ही उनके विग्रह के पूर्ण दर्शन किए जाते हैं, जहां शिवालयों में हरियाली तीज के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, वही वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्त बड़ी तादाद में एकत्रित होते हैं और बांके बिहारी की भक्ति में लीन हो जाते हैं और बांके बिहारी के विग्रह की सुंदरता देखते ही बनती है।

मान्यता है कि उत्तराखंड के द्वार हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की शिवालिक पर्वत माला की तलहटी में स्थित बिल्वेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ और पार्वती ने हजारों सालों की तपस्या के बाद शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव प्रकृति के संवाहक हैं और श्रावण माह भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। श्रावण माह में प्रकृति अपनी युवावस्था में होती है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और भगवान शिव और पार्वती श्रावण माह में प्रकृति की सुंदरता को देखकर विभिन्न लीलाओं के माध्यम से प्रकृति से जुड़ने का संदेश देते हैं। इस पर्व का महिलाएं पूरे साल इंतजार करती है, और यह पर्व प्रकृति से जुड़ने के साथ-साथ सामूहिकता यानी सामुदायिकता का प्रतीक माना जाता है। पेड़ों की शाखाओं में झूले डाले जाते हैं और कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं जात-पात के बंधनों से दूर सामूहिक रूप से इन झूलों में झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं।

वैसे यह पर्व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा,राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। जहां इस पर्व को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हरियाली तीज कहा जाता है और आम भाषा में इसे तीजो भी कहते हैं। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व को कजली तीज के रूप में मनाया जाता हैं। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए यह व्रत रखती है। इसीलिए उनके लिए इस पर्व का अत्यधिक महत्व है। शिव पार्वती के पुनर्मिलन के कारण यह पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव माना जाता है। श्रावण माह में प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है और संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर हरियाली ही हरियाली होने के कारण इस पर्व को हरियाली तीज कहते हैं। इस दिन महिलाएं हरे रंग के परिधान पहनती है और हाथों की कलाइयों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, साथ ही हाथों और पैरों में विभिन्न कलात्मक रीति से मेंहदी रचाती हैं। इसलिए देश के कुछ राज्यों में इस पर्व को ह्यमेहंदी पर्वह्ण भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करके अपने परिवार की वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। नव विवाहित युवतियां प्रथम सावन में अपने अपने मायके आकर हरियाली तीज पर्व मनाती है ।

हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां हरे रंग का जो श्रृंगार करती हैं उसके पीछे धार्मिक कारणों के साथ ही वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। मेंहदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह मानी जाती है। इसीलिए सुहागन महिलाएं हरियाली तीज पर्व के दिन मेंहदी अवश्य लगाती है। मेहंदी की शीतलता प्रकृति, प्रेम और उमंग के मध्य संतुलन यानी सामंजस्य बिठाने का काम करती है। मान्यता है कि श्रावण माह में स्त्री पुरुष में काम की भावना प्रबल हो जाती है। और महिलाओं में मेंहदी काम की भावना को नियंत्रित करती है और इस तरह पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन बना रहता है। कहते हैं कि हरियाली तीज के व्रत के दिन महिलाओं को क्रोध और कामवासना से दूर रहना चाहिए और मन को नियंत्रित करके रखना चाहिए। मेंहदी का औषधीय गुण महिलाओं की इस कार्य में सहायता करता है। हरियाली तीज के व्रत में सास और घर के बड़े नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेंट करते हैं।

पर्व

सामाजिक सरोकारों, सांस्कृतिक जुड़ाव और रिश्तों को मजबूत करने का प्रतीक है यह उत्सव। यह पर्व जीव और परमात्मा के योग, मन की पवित्रता और आत्मिक संबंध का संदेश देता है।

यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद दिलाता है। पर्व शिव और पार्वती के दिव्य मिलन, अटूट प्रेम, और कठोर तपस्या की स्मृति से जुड़ा है।

हिमाचल का 'बद्रीनाथ धाम' है किन्नौर कैलाश

पवन गौतम

हिंदू धर्म में ऐसी कई धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में माना जाता है कि जीवन में एक बार इन्हें पूरा करने पर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष या मृत्यु के बाद भगवान का धाम मिलता है। साथ ही, उस यात्रा का फल आने वाली कई पीढ़ियों को भी मिलता रहता है। ऐसी ही एक यात्रा है किन्नौर कैलाश की...। किन्नौर कैलाश पर्वत भगवान शिव के सबसे पुराने निवास स्थानों में से एक है। किन्नर कैलाश को 'हिमाचल का बद्रीनाथ' भी कहा जाता है और इसे 'राक कैसल' के नाम से भी जाना जाता है।

हिमाचल के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के निकट स्थित किन्नौर कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6050 मीटर की ऊंचाई पर है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण शिवलिंग चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है। किन्नौर कैलाश का यह प्राकृतिक सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इसे 'किन्नर कैलाश' के नाम से भी जाना जाता है। 'किन्नर' शब्द के साथ कई पौराणिक अर्थ जुड़े हुए हैं। इसका उल्लेख शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण और राजतरंगिणी सहित कई ग्रंथों में किया गया है। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने किन्नौर के किन्नर लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति मेघदूतम्‌ में किन्नरों को मधुर आवाज वाले आकर्षक लोगों के रूप में दर्शाया है जो भगवान कुबेर के राज दरबार में गाते और नाचते थे। किन्नौर कैलाश पर्वत पर स्थापित हिम खंड एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांध कर यह परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में एक सप्ताह से दस दिन का समय लगता है।

यह 79 फुट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग दिनभर के दौरान रंग बदलता रहता है। सूर्योदय से ठीक पहले यह सफेद, सूर्योदय के समय पीला, सूर्यास्त के ठीक बाद लाल और रात होने से ठीक पहले यह काला हो जाता है। यह एक कंक्रीट के खंभे जैसी रचना है जिसे त्रिशूल जैसी दिखने वाली चट्टान पर सावधानी से संतुलित किया गया है। यह चट्टान माउंट कैलाश और माउंट जार्कण्डेन की 20 हजार फीट ऊंची किन्नौर कैलाश पर्वतमाला के बीच में है। किन्नौर कैलाश पवित्र पांच पर्वतों में से एक है। इस यात्रा को मानसरोवर और अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन माना जाता है। किन्नौर कैलाश की यात्रा हर साल सावन के महीने में शुरू होती है। यह यात्रा 2-3 दिन में पूरी हो जाती है। यात्रा पूरी करने के बाद भक्त यहां मौजूद शिवलिंग की पूजा करते हैं। किन्नौर कैलाश को बौद्ध अनुयायी भी पवित्र मानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, इस पर्वत पर ही भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। माना जाता है कि जब शिव-पार्वती का मिलन हुआ, तब ब्रह्म कमल का पुष्प इस स्थान पर खिल उठा, जिसका तेज पूरे संसार में फैल गया। कहा जाता है कि आज भी किन्नौर कैलाश की यात्रा के दौरान अक्सर ब्रह्म कमल के फूल दिखते हैं। माना जाता है कि यह फूल सिर्फ उन्हें ही नजर आता है, जिसका मन पवित्र होता है।

यह भी मान्यता है कि शोणितपुर राज्य के राजा बाणासुर ने किन्नर कैलाश पर ही भगवान शिव की आराधना की थी। रावण भी जब मानसरोवर की यात्रा पर गया था तो उन्होंने किन्नर कैलाश में ही तपस्या की थी। महाभारत के अनुसार, दिव्यास्त्रों के लिए अर्जुन ने भी यहीं पर तपस्या की थी। उन दिनों इसका नाम 'इन्द्रकील पर्वत' हुआ करता था। किन्नर कैलाश पर ही भगवान कृष्ण के पोते का विवाह हुआ था। यह यात्रा अगस्त के महीने में शुरू होती है और एक दिन में केवल 200 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति मिलती है। किन्नौर कैलाश जाने का रास्ता बहुत कठिन है। यह मार्ग दो बेहद ही मुश्किल दर्रों से होकर गुजरता है। पहला लालांति दर्रा और दूसरा चारंग दर्रा है।

आस्था

भक्ति-भाव

मुंबई में रविवार को गणेश चतुर्थी त्योहार से पहले भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को पंडाल में ले जाते हुए।

द्रव्य नहीं, श्रद्धा का समर्पण है दक्षिणा

शास्त्री कोसलेंद्रदास

वैदिक सनातन संस्कृति में दक्षिणा ऐसा शब्द है, जिसे सामान्यतः यज्ञ, पूजा, श्राद्ध अथवा संस्कार के उपरांत आचार्य या पुरोहितों को प्रदान किए जाने वाले धन अथवा उपहार के रूप में समझा जाता है। भारतीय मनीषा में वह केवल द्रव्य का दान नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का समर्पण है। यज्ञ की अग्नि में दी गई आहुतियां जिस प्रकार अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार दक्षिणा प्रत्येक धार्मिक कर्म को सार्थक परिणति प्रदान करती है।

यज्ञ को बनाया अक्षय : वैदिक साहित्य में दक्षिणा यज्ञ का प्राण कही गई है। शतपथ ब्राह्मण का मार्मिक आख्यान इस सत्य को उद्घाटित करता है, जिसमें कहा गया है कि एक समय यज्ञ निर्बल और निष्प्रभावी हो गया। तब देवताओं ने दक्षिणा के द्वारा उसे पुनः समर्थ और अक्षय बनाया। इसी कारण उसका नाम दक्षिणा पड़ा। श्रुति का निर्देश है कि दक्षिणा से रहित यज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। इसी भाव को पुराणों और स्मृतियों ने अनेक प्रकार से व्यक्त किया है। भविष्य पुराण कहता है कि दक्षिणा के बिना किया गया दान, व्रत और संस्कार उसी प्रकार निष्फल हैं, जैसे राख में दी गई आहुति। अग्नि में अर्पित हवि देवताओं तक पहुंचती है, पर राख में डाली गई आहुति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार श्रद्धा और दक्षिणा से रहित धार्मिक अनुष्ठान केवल बाह्य प्रदर्शन बनकर रह जाते हैं।

गीता में समझाया गया महत्त्व : श्रीमद्भगवद्गीता (17.13) में अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र-विधि से रहित हो, जिसमें अन्नदान न हो, मंत्रों का अभाव हो, दक्षिणा न दी जाए और श्रद्धा न हो, वह तामस यज्ञ कहलाता है। यहां प्रयुक्त अदक्षिण शब्द का अर्थ केवल दक्षिणा का अभाव नहीं है। गीता पर श्रीरामानुज भाष्य के व्याख्याकार स्वामी वेदांत देशिक लिखते हैं कि यदि यजमान लोभवश पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देता, तो स्वाभाविक रूप से अन्नदान और अन्य अपेक्षित दानों का भी अभाव हो जाता है। इसलिए अदक्षिण शब्द दक्षिणा के साथ-साथ उन सभी आवश्यक दानों और सत्कारों के अभाव का द्योतक है, जो किसी यज्ञ या संस्कार को पूर्णता प्रदान करते हैं। गीता स्पष्ट करती है कि दक्षिणा केवल आर्थिक अनुदान नहीं, बल्कि धार्मिक कृत्य की आत्मा है।

आधार है श्रद्धा : शास्त्रों ने दक्षिणा के पीछे स्थित श्रद्धा को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। षट्त्रिंशन्मत में निर्देश है कि श्रद्धा, शुचिता और संयम के साथ सदक्षिण दान करना चाहिए। दक्षिणा से रहित दान निष्फल होता है। इसलिए दक्षिणा की वास्तविक कसौटी उसकी मात्रा नहीं, बल्कि दाता का भाव है। निर्धन व्यक्ति यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धान्य, वस्त्र अथवा कोई उपयोगी वस्तु श्रद्धापूर्वक अर्पित करता है, तो वह उतनी ही श्रेष्ठ दक्षिणा है जितनी किसी धनी द्वारा प्रदत्त स्वर्ण।

मीमांसा दर्शन में है विचार : जैमिनि के मीमांसा दर्शन (10/2/22-28) में दक्षिणा के विषय में निश्चित किया गया है कि दक्षिणा किसी अदृष्ट उद्देश्य के लिए नहीं दी जाएगी, प्रत्युत वह यज्ञ-अनुष्ठानों में व्यवस्थित कृत्यों के संपादन के लिए नियुक्त पुरोहितों को दी जाती है। तात्पर्य है कि धार्मिक कृत्यों एवं संस्कारों को विधिपूर्वक संपादन करवाने के लिए पुरोहितों को दी जानी राशि या सामग्री दक्षिणा कही जाती है। उपनिषदों ने दक्षिणा के अर्थ को और अधिक ऊंचाई प्रदान की है। छांदोग्य उपनिषद ने तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य को प्रतीकात्मक यज्ञ की दक्षिणा कहा है। यहां दक्षिणा बाह्य द्रव्य नहीं, बल्कि जीवन के श्रेष्ठ गुण हैं।

दक्षिणा से पूर्ण होता है अनुष्ठान : आश्वलायन-गृह्यसूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति तथा पद्म पुराण प्रत्येक धार्मिक कृत्य के उपरांत दक्षिणा देने का विधान करते हैं। स्कन्दपुराण अत्यंत प्रभावशाली उपमा देते हुए कहता है कि मंत्र, काल या विधि में यदि कोई न्यूनता रह जाए, तो दक्षिणा उससे उत्पन्न दोष का परिमार्जन कर देती है। बिना दक्षिणा के किया गया धार्मिक कृत्य मरुस्थल में वर्षा, अंधकार में नृत्य और बहरे के सम्मुख संगीत के समान निष्फल है। धर्मशास्त्रों ने यह नैतिक मर्यादा भी निर्धारित की कि यजमान केवल उसी संपत्ति की दक्षिणा दे सकता है जो वास्तव में उसकी अपनी हो। भविष्य में प्राप्त होने वाली अथवा किसी अन्य के अधिकार की वस्तु का दान मान्य नहीं है। धर्मशास्त्रों ने दक्षिणा की समयबद्धता पर विशेष बल दिया है।

कठपुतली बन कर जीवन नहीं जीएं, एकाग्र होकर लक्ष्य हासिल करें

जनसत्ता धर्म दीक्षा

यदि आप मनुष्य हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप खिलौने की तरह, कठपुतली की तरह दूसरों के निमित्त के लिए जीवन जिएं, दुनिया की दया पर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरें, या फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके इससे बाहर निकलें और अपने लक्ष्य के अनुरूप जीवन जीएं व स्वतंत्रता प्राप्त करें। गीता के नौवें अध्याय का यही अहम संदेश है। यह अध्याय 'राजविद्याराजगुह्ययोग' कहलाता है।

इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपनी क्षमता से अनभिज्ञ, भ्रमित आत्मा का उपेक्षित होकर संसार के वश में हो जाते हैं व कठपुतली बन जाते हैं। व्यर्थ की आशाओं में जीते हुए, निरर्थक कर्म करते हुए और खोखला, सतही ज्ञान प्राप्त करते हुए, वे विवेकहीन हो जाते हैं। महात्मा, महान आत्माएं, स्वयं में स्थिर होकर, एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और हासिल करते हैं। वे अपने सभी कर्मों को आत्मा को समर्पित करते हैं- यह कर्म योग है। वे सदा अपने प्रेम को ईश्वर की ओर निर्देशित करते हैं -यह भक्ति योग है। वे दृढ़ संकल्पित होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति तक अपने प्रयास में दृढ़ रहते हैं - यह ज्ञान योग है। वे अपने मस्तिष्क और हृदय दोनों को सत्य के साथ संरेखित करते हैं। ऐसी महान आत्माएं निरंतर मुक्ति की लालसा रखती हैं। वे आत्मा का ज्ञान एक (अद्वैत) या पृथक (द्वैत) रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार उपासना आत्मा के साथ एकात्म होने का निरंतर प्रयास है, न कि कोई आकस्मिक, कभी-कभार की जाने वाली प्रार्थना या अनुष्ठान। ज्ञान सब विद्याओं और रहस्यों में राजा है, जो सीधा अनुभव में आता है और मोक्ष देता है। कृष्ण भगवद् गीता के ज्ञान को राजसी रहस्य कहते हैं। यह सर्वोच्च और श्रेष्ठ ज्ञान है। यह वह परम ज्ञान है जो अन्य सभी ज्ञानों को प्रकाशित करता है। इसीलिए इसे राजसी कहा जाता है। यह सभी के लिए अज्ञात है, रहस्य है। आत्मा इतनी गहन और सूक्ष्म है कि अधिकांश लोगों की समझ से परे है। फिर भी यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपनी निर्मल महिमा में उससे परे भी विद्यमान है। इस अध्याय में श्लोक 22 गीता का केंद्रबिंदु है, जिसमें कृष्ण उन सभी को आश्वासन देते हैं जो एकाग्रचित्त होकर, सदा एकात्मता की खोज में ईश्वर की उपासना करते हैं, कि उन्हें योग (आध्यात्मिक ज्ञान) और क्षेम (भौतिक सफलता) दोनों प्राप्त होंगे।

भगवद् गीता किसी अस्पष्ट, मृत्यु के बाद मिलने वाले सुख का वादा नहीं करती। इसके लाभ यहीं और अभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे भौतिक समृद्धि, सुख और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें उद्देश्य की निरंतरता और भाव की गहराई पर बल दिया गया है। अपने लक्ष्य का निरंतर और निष्ठापूर्वक पीछा करें, और आप उसे प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण सबको राह दिखाते हैं, चाहे वे राजसिक हों या तामसिक और आलसी। उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। सही मार्ग चुनने पर कोई भी अयोग्य नहीं है। शांत मन और तीक्ष्ण बुद्धि से वे संसार के स्वभाव को अनित्य (अस्थायी) और असुख (आनंदहीन) समझते हैं। कृष्ण जानते हैं कि वे सच्चे और स्थायी आनंद के उत्तराधिकारी हैं। कृष्ण एक श्लोक में संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग का सार प्रस्तुत करते हुए अर्जुन को दिए अपने ज्ञान संदेश का समापन करते हैं। ज्ञान योग से अपना मन स्थिर करो। बुद्धि आत्मज्ञान को लक्ष्य मानकर निरंतर वास्तविक और असत्य, स्थायी और क्षणिक, शाश्वत और अल्पकालिक में भेद करती रहती है। समर्पण मन को शांत करता है। यह तुम्हें संसार की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है।

गीता सार : अध्याय नौ का संदेश

गीता के नौवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपनी क्षमता से अनभिज्ञ, भ्रमित आत्मा का उपेक्षित होकर संसार के वश में हो जाते हैं व कठपुतली बन जाते हैं। व्यर्थ की आशाओं में जीते हुए, निरर्थक कर्म करते हुए और खोखला, सतही ज्ञान प्राप्त करते हुए, वे विवेकहीन हो जाते हैं। महात्मा, महान आत्माएं, स्वयं में स्थिर होकर, एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और हासिल करते हैं।

कृष्ण भगवद् गीता के ज्ञान को राजसी रहस्य कहते हैं। यह सर्वोच्च और श्रेष्ठ ज्ञान है। यह वह परम ज्ञान है जो अन्य सभी ज्ञानों को प्रकाशित करता है। इसीलिए इसे राजसी कहा जाता है। यह सभी के लिए अज्ञात है, रहस्य है। आत्मा इतनी गहन और सूक्ष्म है कि अधिकांश लोगों की समझ से परे है। फिर भी यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपनी निर्मल महिमा में उससे परे भी विद्यमान है।